राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 5 अंक 50

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021

# दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14



# भारत के लिए बढ़ी पदकों की आस

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** टोक्यो ओलिंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए पदक की उम्मीदों को बढ़ाने वाला रहा। भारत में गुरुवार को जैसे-जैसे सूर्योदय हो रहा था तो उसी समय टोक्यो में हाकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी जोर मार रहा था। कुछ ही देर में भारतीय पुरुष हाकी टीम, शटलर पीवी सिंधु, तीरंदाज अतानु दास और मुक्केबाज सतीश कुमार की जीत ने भारतीय प्रशंसकों की सुबह की ताजगी को और बढ़ा दिया। हालांकि, टोक्यो में शाम ढलते-ढलते भारत को बड़ा झटका लगा, जब पदक की दावेदार मानी जा रहीं मुक्केबाज एमसी मेरी कोम हार के साथ ओलिंपिक से बाहर हो गईं।

**टोक्यो ओलिंपिक**

- पुरुष हाकी टीम ने अर्जेंटीना को दी शिकस्त
- सिंधू, अतानु, सतीश भी जीते, मेरी कोम हारीं



**हाकी में रियो की चैंपियन को हराया:** भारतीय पुरुष हाकी टीम ने अंतिम समय में दो मिनट में दो गोल करते हुए रियो ओलिंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। भारत के लिए वरुण कुमार ने 43वें, विवेक सागर प्रसाद ने 58वें और हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में गोल दागे।

संबंधित खबरें >> पेज 12

### भारत के अन्य परिणाम

निशानेबाजी में मनु भाकर और राही सरनोबत महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन में क्रमशः पांचवें और 25वें स्थान पर रहीं

गोल्फ में अनिर्बान लाहिड़ी पहले दौर में संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर रहे, जबकि उदयन माने सबसे निचले स्थान पर थे

नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे

सेलिंग में केसी गणपति और वरुण ठक्कर की भारतीय जोड़ी पुरुषों की स्किफ 49आर स्पर्धा में कुल 17वें स्थान से निचले पायदान पर रहे। विष्णु सरवनन लेजर स्पर्धा में 23वें स्थान पर रहे। नेत्रा कुमानन महिला लेजर रेडियल में 31वें स्थान पर रहीं

तैराक साजन प्रकाश पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाए

### निशाने पर लगे अतानु के तीर

भारत के स्टार तीरंदाज अतानु दास पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे दौर में लंदन ओलिंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया के ओह जिन हयेक को शूट आफ में हराया। अतानु ने पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए 6-4 से जीत दर्ज की।

### सिंधू ने बढ़ाए मजबूत कदम

रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधू ने अपने दूसरे ओलिंपिक पदक की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। उन्होंने महिला सिंगल्स के एकतरफा प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को सीधे गेमों में 21-15, 21-13 से हराया।

### मुक्केबाजी में सतीश जीते, मेरी कोम को मिली निराशा

भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, छह बार की विश्व चैंपियन एम सी मेरी कोम अंतिम-16 चरण के मुकाबले में हारकर बाहर हो गईं। उन्हें रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंग्रिट वालेंसिया ने 3-2 से हराया।

**जागरण विशेष**

### तंत्रिका तंत्र पर कोरोना के प्रभाव को समझेगा रिम्स



**रांची:** रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के विशेषज्ञ अब मंथन करेंगे कि कोरोना से तंत्रिका तंत्र कैसे प्रभावित हो रहा है। रिम्स को एक अंतराष्ट्रीय शोध के लिए चुना गया है। (पेज-14)

**न्यूज गैलरी**

राष्ट्रीय राजधानी ▸ पृष्ठ 2

### मनी लांड्रिंग मामले में एंबियेंस समूह के चेयरमैन गिरफ्तार

**नई दिल्ली:** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में एंबियेंस समूह के चेयरमैन राज सिंह गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले वर्ष जुलाई में गहलोत, उनकी कंपनियों, कंपनी के निदेशकों और उनके सहयोगियों के परिसरों में छापे मारे थे।

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

### पेगासस कांड में लगातार आठवें दिन संसद में हुआ हंगामा

**नई दिल्ली:** पेगासस जासूसी कांड पर संसद में जारी संग्राम थम नहीं रहा है। विपक्ष मामले पर बहस पर लेकर अड़ा है तो सरकार भी दबाव में मांग मानने को तैयार नहीं दिख रही। सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते आठवें दिन भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ और कामकाज सुचारु रूप से नहीं हो पाया। इसबीच सरकार ने लोस में दो और रास में एक विधेयक पारित करा लिया।

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

### सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

**नई दिल्ली:** मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश निवासी नीरज शंकर व चार अन्य लोगों की ओर से कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें सच्चर कमेटी के गठन को गैरकानूनी बताते हुए कमेटी की सिफारिशों पर अमल रोकने की मांग की गई है।

# मेडिकल में ओबीसी को 27 और गरीबों को 10 फीसद आरक्षण

**बड़ा कदम** ▸ प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले की जानकारी देते हुए इसे अभूतपूर्व बताया

### उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव से पहले फैसला राजनीतिक रूप से अहम

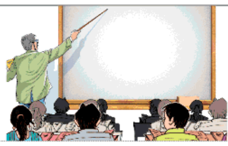
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की खातिर 27 फीसद आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी 10 फीसद सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। चूंकि आरक्षण का यह प्रविधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसीलिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी एमबीबीएस, एमडी, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस कोर्स में मिलेगा।

यूं तो यह कवायद लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव से पहले इस घोषणा का राजनीतिक महत्व भी है। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उसके बाद इस फैसले को तुरुप का पत्ता माना जा रहा है।

एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों व सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी आरक्षण लागू करने का आग्रह किया था। फैसले के तत्काल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया।

- भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों और सांसदों ने किया था आग्रह
- सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा लाभ



#### मोदी ने दिया था केंद्रीय कोटे में आरक्षण का निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को केंद्रीय कोटे में आरक्षण का प्रविधान सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया था। इसके बाद मंत्रालय ने बुधवार को इसे लागू करने का एलान कर दिया।

#### इतने छात्रों को मिलेगा लाभ

- इससे केंद्रीय कोटे में स्नातक की सीटों पर 1,500 और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर 2,500 छात्रों को ओबीसी कोटे से नामांकन का लाभ मिलेगा।
- इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 550 छात्र स्नातक और 1,000 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन करा सकेंगे।

#### 2007 में केंद्रीय कोटे में अनुसूचित जाति, जनजाति को मिला आरक्षण

शुरू में केंद्रीय कोटे में आरक्षण का कोई प्रविधान नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्रीय कोटे की सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसद और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसद आरक्षण का प्रविधान किया गया। 2007 में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 27 फीसद सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने का कानून बना और इसके तहत सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मेडिकल सीटों पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रविधान लागू कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय कोटे की सीटें आरक्षण के दायरे से बाहर रह गईं। इसी तरह से 2019 में आर्थिक रूप से गरीब तबके लिए 10 फीसद आरक्षण के प्रविधान को भी केंद्रीय कोटे की मेडिकल सीटों पर लागू नहीं किया जा सका था।

#### पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई हैं मेडिकल सीटें

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। 2014 में जहां देश में एमबीबीएस की 54,348 सीटें थी। यह 56 फीसद बढ़ोतरी के साथ 2020 में 84,649 हो गई हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें 2014 में 30,191 से बढ़कर 2020 में 54,275 हो गई हैं, जो 80 फीसद की बढ़ोतरी है। पिछले सात वर्षों में सरकार ने 179 नए मेडिकल कालेज खोले हैं।

#### इसलिए किया गया था केंद्रीय कोटे का प्रविधान

दूसरे राज्यों में मौजूद अच्छे मेडिकल कालेजों तक प्रतिभाशाली छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1986 में केंद्रीय कोटे की व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत सभी मेडिकल कालेजों में स्नातक सीटों (यूजी) का 15 फीसद और पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) सीटों का 50 फीसद केंद्रीय कोटे में रखा गया था।

# सीपीईसी बंद करे चीन : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

**सख्त चेतावनी**

- भारत की दो टूक, चीन और पाक अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी करने से बाज आएं
- दोनों देशों के संयुक्त बयान में किया गया था जम्मू-कश्मीर का जिक्र

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच सोमवार को बीजिंग में मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया, वह भारत को नागवार गुजरा है। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वे भारत के अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी करना बंद करें। गैरकानूनी तरीके से कब्जा किए भारतीय जमीन पर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का निर्माण भी बंद करें।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, भारत हमेशा की तरह इन देशों के बयान में जम्मू व कश्मीर का जिक्र आने को सिरे से खारिज करता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। इस संयुक्त बयान में सीपीईसी का जिक्र किया गया है। हमने हमेशा पाक व चीन को कहा है कि तथाकथित सीपीईसी का निर्माण पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई भारतीय जमीन पर किया जा रहा है। हम यथास्थिति बदलने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं। सभी पक्षों को इस तरह का काम बंद कर देना चाहिए।

यह हाल के दिनों में सीपीईसी के बारे में भारत की तरफ से दिया गया सबसे सख्त बयान है। भारत पहले भी सीपीईसी को लेकर विरोध करता रहा है, लेकिन सीधे तौर पर चीन को पहली बार इस पर काम रोकने को कहा है। राज्यसभा में भी गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-अमेरिका रिश्तों पर बयान देते हुए जब यह कहा कि दोनों देश पारदर्शी तरीके से ढांचागत विकास करना चाहते हैं तो उनका इशारा सीपीईसी को लेकर ही था। सीपीईसी पर चीन की तरफ से पहली बैठक वर्ष 2015 में बुलाई गई थी, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। भारत के विरोध के बाद फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय ढांचागत विकास परियोजनाओं में दूसरे देशों की भौगोलिक अखंडता के आदर की बात कही है।



अरिंदम बागची। फाइल फोटो इंटरनेट

#### पाक के गैरकानूनी कब्जे को नहीं छिपा सकता गुलाम कश्मीर में चुनाव

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा, भारत की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके वहां चुनाव कराने से पाक सच को नहीं छिपा सकता। पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है उसका गुलाम कश्मीर के लोग भी विरोध कर रहे हैं। इस तरह के कदम से न तो गैरकानूनी कब्जे को छिपाया जा सकता है और न ही वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को। पाकिस्तान को भारतीय जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। उसे जल्द से जल्द से इस गैरकानूनी कब्जे को छोड़ना चाहिए।

# आइएस की तर्ज पर तालिबान ने की दानिश की निर्मम हत्या

**वाशिंगटन, प्रेट्र:** पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी (38) की हत्या में तालिबान ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) जैसा बर्बर तरीका अपनाया था। तालिबान चरमपंथियों ने दानिश को पकड़कर उनकी पहचान सुनिश्चित की, उसके बाद हत्या की। यह रहस्योद्घाटन अमेरिकी पत्रिका वाशिंगटन एक्जामिनर के ताजा अंक में हुआ है।

दानिश की हत्या तब हुई थी जब वह अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई को कवर करने के लिए कंधार के स्पिन बोल्डाक इलाके में गए हुए थे। इस दौरान जब वह तीन अफगान सैनिकों के साथ जा रहे थे, तभी उन पर तालिबानियों ने धारदार हथियारों से हमला कर किया। दानिश को घायल अवस्था में पास की मस्जिद में ले जाया गया, जहां उनकी प्राथमिक चिकित्सा हुई। इसी बीच मस्जिद में पत्रकार के होने की सूचना पाकर तालिबानियों के समूह ने वहां पर हमला बोल दिया और भारतीय पत्रकार होने का पता चलने के बाद दानिश और उनके साथ के लोगों की हत्या कर दी।

रिपोर्ट देने वाले माइकेल रुबिन ने लिखा है कि दानिश की लाश की फोटो और अंतिम समय का वीडियो देखने से पता चलता है कि भारतीय पत्रकार की बर्बरता से पिटाई की गई। उनके शरीर में गोलियों के भी कई निशान थे। तालिबान का व्यवहार दर्शाता है कि युद्ध के मानकों और कैदी संग किए जाने वाले व्यवहार का भी सम्मान नहीं करता। ज्ञात हो, 18 जुलाई को दानिश को दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रगाह में दफन किया गया था।



दानिश सिद्दीकी। फाइल

**भारतीय पत्रकार के बारे में अमेरिकी पत्रिका का सनसनीखेज रहस्योद्घाटन**

# सरकारी में भी प्ले स्कूल जैसी होगी पढ़ाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति से जुड़ी 10 नई पहल कीं। इनमें स्कूली बच्चों से जुड़ी पहल विद्या प्रवेश योजना भी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूलों जैसी पढ़ाई होगी। यानी पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को तीन महीने का खास कोर्स कराया जाएगा। इसमें पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर व संख्या ज्ञान दिया जाएगा।

पीएम ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि जब हंसी-खुशी से पढ़ाई होगी तो सफलता तय है। उन्होंने देशभर के शिक्षाविदों, अभिभावकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, 'राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़े फैक्टरों में से एक है। यही वजह है कि इसे दबाव से मुक्त रखा गया है। उन्होंने इंजीनियरिंग कालेजों में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी खुशी जताई। उधर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी और नीति तैयार करने वाली कमेटी के प्रमुख डा. के. कस्तूरीरंगन का भी आभार जताया।

(संबंधित खबरें-पेज 5 पर)

#### नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा, पीएम ने लांच कीं 10 नई पहल



नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग से नई पहलों का शुभारंभ करते पीएम। प्रेट्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं की सोच के अनुरूप है। 21वीं सदी के युवाओं को एक्सपोजर चाहिए। वह शिक्षा के पुराने बंधनों और पिंजरों से मुक्त होना चाहता है। नई नीति उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि देश पूरी तरह से उनके और उनके हौसलों के साथ है। -नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

#### एकेडमिक क्रेडिट आफ बैंक स्कीम की भी शुरुआत की

पीएम ने एकेडमिक क्रेडिट आफ बैंक स्कीम की भी शुरुआत की। यानी छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है और फिर शुरू कर सकता है। उसकी पढ़ाई का ब्योरा एकेडमिक अकाउंट में दर्ज रहेगा। इनमें एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेने का भी विकल्प मौजूद है।

#### दिव्यांगजनों के लिए सांकेतिक भाषा में पढ़ाई शुरू

मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए पहली से 12वीं तक सांकेतिक भाषा में पढ़ाने की योजना भी शुरुआत की। एनसीईआरटी ने इसका पाठ्यक्रम तैयार किया है। छात्र सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में भी पढ़ सकेंगे।

#### पीएम की प्रमुख पहल

- **निष्ठा 2.0 :** प्राइमरी के साथ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को भी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **सफल :** सीबीएसई स्कूलों में तीसरी, पांचवीं व आठवीं के छात्रों का आकलन उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर होगा। परीक्षा कांसेप्ट और थिंकिंग बेस्ड होगी।
- **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) फार आल :** सभी स्टेज पर छात्रों को कम से कम चार घंटे का एआइ का कोर्स करना होगा।
- **उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण :** उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी कोर्स शुरू होंगे। 150 संस्थानों ने विदेशी सेंटर खोले हैं।
- **नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर :** आनलाइन पढ़ाई के विकास के साथ बेहतर कंटेंट मुहैया कराने पर भी जोर।
- **नेशनल एजुकेशन टेक्नोलाजी फोरम :** इसके जरिये सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी।

**खतरे की बात**

छोटी सी लापरवाही भी बन जाती है बड़े संक्रमण का कारण, कुछ जगहों पर फिर बढ़ते दिख रहे दैनिक संक्रमण के मामले, नहीं संभले तो जल्द करना पड़ सकता है तीसरी लहर का सामना



# संभलकर रहिए, ऐसे ही शुरू होती है महामारी की लहर

जेएनएन, नई दिल्ली

कानपुर में दैनिक संक्रमण के मामले शून्य की ओर जाते-जाते फिर 20-30 पर आ गए हैं। दिल्ली में भी 40 के करीब आते-आते संख्या फिर 70-80 की ओर बढ़ती दिख रही है। दूसरी लहर में सैकड़ों और हजारों में दैनिक संक्रमण के मामलों को देखने के बाद भले ही ये आंकड़े बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे चिंता बहुत बड़ी है। महामारी की नई लहर ऐसे ही बढ़ती है। इसलिए यह वक्त बहुत संभलकर चलने का है।

देश में महीनेभर से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 35 से 45 हजार के बीच बने हुए हैं। नए मामलों में गिरावट का क्रम जिस तरह से थमा हुआ है, वह सबकी चिंता बढ़ा रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका और ब्राजील समेत कई देशों में जोर पकड़ती नई लहर भी सतर्क होने की चेतावनी दे रही है। अकेले केरल में ही देश के कुल नए संक्रमण के आधे मामले आ रहे हैं। जिस तरह से वहां राज्य सरकार ने बकरीद के नाम पर तीन दिन तक कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियों में ढील दी थी, उसे देखते हुए तमाम विशेषज्ञ चिंता जता रहे थे और अब बढ़ते मामले उस चिंता को सच साबित कर रहे हैं। विज्ञानी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी नहीं संभले तो जल्द ही भारत में तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है।



#### टीके पर टिकी है आस

पूरी दुनिया में अब तक के निष्कर्ष यही बता रहे हैं कि महामारी से निपटने के लिए टीका एकमात्र उपाय है। टीका लगने से संक्रमण की दर कम होती है, संक्रमित लोगों के गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने के मामले भी नियंत्रित होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में बताया है कि देश में अगस्त से बच्चों का टीका आ जाएगा। निसंदेह यह राहत बढ़ाने वाली बात है। जितनी बड़ी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा, संक्रमण से बचाव उतना ही संभव होगा।

**न हटे सावधानी** :सरकार से लेकर विज्ञानी तक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टीके के बाद भी बचाव के कदमों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मास्क लगाना, शारीरिक दूरी का पालन करना और भीड़भाड़ नहीं करना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनसे संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। टीका लगने के बाद भी कुछ लोगों के संक्रमित होने की आशंका रहती है। टीके के कारण उनमें लक्षण गंभीर तो नहीं होते हैं, लेकिन वे अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं।



#### केरल में कोरोना विस्फोट से चिंतित केंद्र ने भेजी टीम

**नई दिल्ली :** केरल में कोरोना विस्फोट को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की छह सदस्यीय टीम को केरल रवाना किया है। केरल में कोरोना स्थिति बेकाबू होती जा रही है और संक्रमण दर 12 फीसद से अधिक पहुंच गया है। हालात यह है कि देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना के नए मामलों में लगभग आधे अकेले केरल से आ रहे हैं। यही नहीं, देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का 37 फीसद से अधिक अकेले केरल में है। (पेज-6)

# जज की हत्या में इस्तेमाल आटो गिरिडीह से बरामद, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद

धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने की वारदात में प्रयोग किए गए आटो (टेंपो) को पुलिस ने गुरुवार को गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरूडीह गांव से बरामद कर लिया। वहीं से लखन कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया, जो वारदात के दौरान आटो चला रहा था। लखन की निशानदेही पर उसके सहयोगी राहुल वर्मा को धनबाद स्टेशन परिसर से दबोच लिया गया।

एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि घटना के वक्त लखन आटो चला रहा था, जबकि राहुल उसके साथ आगे की सीट पर बैठा था। लखन धनबाद जिले के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के सोनापट्टी का रहने वाला है, जबकि राहुल भी उसके पास का ही डिगवाडीह क्षेत्र का निवासी है। इसके अलावा इस घटना से जुड़े जिन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार दोनों युवकों के अपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगालने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के बाद ही यह साफ होगा कि उन्होंने किसके कहने के पर घटना को अंजाम दिया।



उत्तम आनंद की फाइल फोटो। स्रोत : स्वजन

**घटना के समय लखन चला रहा था आटो, बगल में बैठा था राहुल, अभी यह स्पष्ट नहीं कि किसके कहने पर हुई हत्या, पुलिस कर रही पूछताछ**

ऐसे मिला सुराग पेज>>5

**24** घंटे में दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। गुरुवार को 51 नए मामले आए। वहीं 70 मरीज ठीक हुए। संक्रमण दर 0.08 फीसद है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 जुलाई, 2021

# विस के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत

**तकरार** ▶ भाजपा विधायकों ने लगाया उनके प्रस्तावों को कार्यसूची में शामिल नहीं किए जाने का आरोप

## 'विपक्ष के अधिकार छीने जाने को लेकर सदन में नारेबाजी'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र शुरू होने के पहले घंटे में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई, जिसने कुछ ही देर में हंगामे का रूप ले लिया। आरोप-प्रत्यारोप के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भाजपा के पांच विधायकों को उनके निर्देशों का पालन नहीं करने पर मार्शल के जरिये बाहर करा दिया।

गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके दिए प्रस्तावों को कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया। विपक्ष के अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए वे अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच सत्तापक्ष के कुछ विधायक भी वहां आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों को अपनी-अपनी सीट पर वापस जाने और सदन चलने देने के लिए कहा, लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने। इस पर अध्यक्ष ने मार्शलों से पहले अनिल बाजपेयी और बाद में विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओपी शर्मा और जितेंद्र महाजन को सदन से बाहर करवा दिया।



विधानसभा के मानसून सत्र में जाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

**वहीं**, भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा पर आप विधायकों ने अपने खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। इस पर गोयल ने शर्मा को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन शर्मा के इन्कार कर देने पर उन्हें पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

**संविधान की हत्या करने पर तुली है केंद्र सरकार:** विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के अधिकार छीने हैं, उसके बाद आज सत्र हो रहा है। इससे वह खुद को इतना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है। केंद्र सरकार संविधान की हत्या करने पर तुली है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे कार्यकाल में यह हुआ है कि समितियों के अधिकार छीन लिए गए। उस दिन लगा कि मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूं।' विपक्ष ने इस पर एक बार भी उनसे बात नहीं की और आज अधिकारों की बात कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों को गृह मंत्री से जाकर बात करनी चाहिए, यह दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन है।

**विपक्ष को बोलने के लिए 20 मिनट का समय ही मिलेगा:** विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में आज आप है तो कल भाजपा भी आ सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा सदन को बैलेंस करके चलाया है, लेकिन विपक्ष को 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन्हें छीना जा रहा है। यह निर्णय करने में उन्हें पीड़ा हो रही है। सदन 11 बजे से पांच बजे तक चलेगा। प्रश्नकाल के बाद भोजन अवकाश एक घंटे का होगा। बचे हुए तीन घंटे में सत्तापक्ष के विधायकों को बोलने के लिए 160 मिनट का वक्त मिलेगा, जबकि विपक्ष के विधायकों को सदन के नियमों के अनुसार 20 मिनट से अतिरिक्त एक सेकेंड भी नहीं दिया जाएगा।

### भाजपा विधायकों को सदन से बाहर करने की निंदा

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विपक्षी विधायकों को मार्शलों द्वारा बाहर किए जाने की कड़ी निंदा की है। गुप्ता ने कहा कि डीटीसी बसों की खरीद और उसके रखरखाव अनुबंध पर सदन को गुमराह करने के आरोप में विपक्षी विधायक परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए थे, लेकिन उसे कार्यसूची में नहीं डाला गया। विपक्ष यह जानना चाहता था कि किसी भी नए स्कूल या कालेज को खोलने में सरकार की विफलता और स्कूलों में शिक्षकों की कमी से संबंधित मामला, जिसे चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया था, उसे संशोधित कार्यसूची से उसे क्यों हटा दिया गया।

### सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित

दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि बहुगुणा ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को अपने जल, जंगल और जमीन बचाने का विजन दिया था। उनका विजन था कि अगर पर्यावरण के साथ समन्वय कर हमने अपने जीवन को नहीं ढाला, तो यह सृष्टि नहीं बचेगी। दिल्ली विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन पूरे देश की यही चाहत है कि बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

### राष्ट्रगीत के दौरान गैलरी में मौजूद अधिकारी बैठे रहे

परंपरा के अनुसार विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी सदस्य इस दौरान सदन में खड़े रहे, लेकिन गैलरी में मौजूद अधिकारी बैठे रहे। इस मामले पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव को संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दे दी है। इस मामले में एक्शन लेने और इसकी सूचना छह अगस्त तक देने के लिए कहा गया है।

# भ्रष्टाचार के आरोपितों को बचा रही है सरकार : भाजपा



दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (बीच में मास्क लगाए) व कार्यकर्ता। संजय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपितों को बचा रही है।

गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से लाभ में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड बदहाल हो गया है। कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिला। गरीबों का राशन गोदाम में रखकर सड़ा दिया गया। कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले तीन सौ से ज्यादा योद्धाओं के स्वजन को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 17 परिवारों को यह राशि मिली। एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद व रखरखाव की प्रक्रिया में अनियमितता हुई है। इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। नालों की सफाई नहीं होने से दिल्लीवासियों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में पीने को न पानी है और न ही सफर करने को बस। कुछ ऐसा ही हाल स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है। कोरोना काल में इलाज कराने के लिए लोग भटक रहे थे। स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही हैं। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री विजय गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, राजन तिवारी व जयवीर सिंह राणा, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिनेश प्रताप सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे।

## न्यूज गैलरी

### विधायकों के कार्यालय में भी तैनात किए जाएंगे मार्शल

**नई दिल्ली:** राजधानी के सभी विधायकों के कार्यालय में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए मार्शल की तैनाती की जाएगी। सत्ता पक्ष के विधायक सोमदत्त ने कहा कि हर विधायक के कार्यालय में रोजाना सैंकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन वहां कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं हो पाता। अगर मार्शल तैनात कर दिए जाएं तो स्थिति में सुधार हो सकता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रक्रिया चल रही है। विधायकों के कार्यालय में मार्शल तैनात किए जाएंगे। (राब्यू)

### मनी लांड्रिंग केस में न्यूजक्लिक के मालिक को राहत

**नई दिल्ली:** मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित न्यूजक्लिक वेबपोर्टल के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने को लेकर दी गई राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने दो सितंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि प्रबीर के खिलाफ जमानत आवेदन पर सुनवाई से पहले जांच में शामिल होने की स्थिति में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। प्रबीर ने मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया है। (जासं)

### जेएनयू में पीएचडी दाखिले के लिए आवेदन शुरू

**नई दिल्ली:** जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में एमफिल दाखिले नहीं होंगे। छात्र पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। जेएनयू ने गुरुवार को पीएचडी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। जेआरएफ पात्रता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन होगी। आवेदन तभी मान्य होंगे जब अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क जमा करेगा। (जासं)

### 5जी से जुड़े मामले में जूही चावला ने वापस ली याचिका

**नई दिल्ली :** अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ दायर वाद को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज करते हुए चावला पर जुर्माना लगाया था। चावला ने इस फैसले से राहत पाने के लिए एक याचिका दायर की थी। गुरुवार को अभिनेत्री ने इस याचिका को वापस ले लिया। (जासं)

# मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने एंबियंस समूह के चेयरमैन को गिरफ्तार किया

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में एंबियंस समूह के चेयरमैन राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गहलोत को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने गहलोत, उनकी कंपनी अमन हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल), एंबियंस समूह की कुछ अन्य कंपनियों, कंपनी के निदेशक दयानंद सिंह, मोहन सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों के परिसरों में पिछले साल जुलाई में छापे मारे थे।

जम्मू के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने एएचपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली में यमुना खेल परिसर के पास फाइव स्टार लीला एंबियंस कन्वेंशन होटल के निर्माण एवं विकास में कथित मनी लांड्रिंग के लिए 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी है। गहलोत के खिलाफ ईडी का मामला इसी प्राथमिकी पर आधारित है।

**कसा शिकंजा**

- 800 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि की हेराफेरी का मामला
- गहलोत, उनकी कंपनी व अन्य के ठिकानों पर ईडी ने पिछले साल की थी छापेमारी



राज सिंह गहलोत। फाइल फोटो

ईडी की जांच में पाया गया कि 800 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि के एक बड़े हिस्से का एएचपीएल, राज सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों ने उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से हेरफेर किया गया था। बैंकों के समूह ने होटल परियोजना के लिए इस कर्ज को मंजूरी दी थी।

एजेंसी का आरोप है कि ऋण की राशि का एक बड़ा हिस्सा एएचपीएल द्वारा कई कंपनियों और व्यक्तियों को मौजूदा बिलों के भुगतान और सामग्री की आपूर्ति और निष्पादित कार्य के लिए अग्रिम भुगतान के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

एजेंसी के अनुसार, एंबियंस समूह के कर्मचारियों और गहलोत के सहयोगियों को इन कंपनियों में निदेशक और मालिक बनाया गया था और गहलोत इन कंपनियों में से कई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।

ईडी ने कहा, किसी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी और न ही कोई काम किया गया था और लगभग पूरी राशि तुरंत राज सिंह एंड संस एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) और उनके भाई के बेटे के स्वामित्व वाली कंपनियों को भेज दी गई थी। फिर समूह की कंपनियों के जरिये रुपये का हेरफेर किया गया था।

एएनआइ के अनुसार, ईडी ने गहलोत को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया और 14 दिन की हिरासत की मांग की। गहलोत को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में पेश किया गया।

# पुलिस आयुक्त अस्थाना की नियुक्ति पर सियासत गरमाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला गरमाता ही जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को इसे लेकर सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही आयुक्त बनाए जाने का आदेश वापस लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया। सत्ता पक्ष का कहना था कि आप नेताओं को परेशान करने के लिए अस्थाना की नियुक्ति की गई है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए। इस बीच विपक्ष के नेता रामबीर सिंह बिधूड़ी ने अस्थाना को दो बार राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाला सम्मानित व ईमानदार अफसर बताते हुए प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।

विधानसभा में गुरुवार को अल्पकालिक चर्चा के दौरान विधायक संजीव झा ने अस्थाना को वापस बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर किसी अधिकारी के पास कार्यकाल के छह माह का समय शेष नहीं है, तो उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अस्थाना चार दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे। आप विधायक गुलाब सिंह, अखिलेश पति त्रिपाठी, सोमनाथ भारती और बी एस जून ने झा के प्रस्ताव का समर्थन किया और आरोप लगाया कि अस्थाना को आप का गला घोटने और परेशान करने के लिए दिल्ली लाया गया है। त्रिपाठी ने कहा कि आप नेता और कार्यकर्ता अस्थाना की नियुक्ति से डरते नहीं हैं।

इस बीच विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, अस्थाना सम्मानित और अनुभवी अफसर हैं। उन्होंने गोधरा नरसंहार और पुरुलिया हथियार गिराने के मामलों की सफलतापूर्वक जांच की। उन्होंने एक राजनीतिक दल के प्रमुख के दामाद से संबंधित भूमि घोटाले की भी जांच की। इसलिए सदन को उनकी नियुक्ति का स्वागत करना चाहिए। इस पर दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिधूड़ी को 'दामाद' के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनौती दी, जिसका वह नाम नहीं ले रहे थे और कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

# पेगासस मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** जासूसी प्रकरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के खिलाफ गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल एक तरफ तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समर्थक होने के साथ-साथ गरीबों के कल्याण करने का दावा करते हैं, लेकिन मीडिया व विपक्षी नेताओं की जासूसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली विधानसभा के इसी सत्र में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की जाए। यह लोगों की निजता और लोकतंत्र पर हमले के साथ-साथ राष्ट्रद्रोह का मामला है। कांग्रेस का आरोप है कि घेराव के लिए पहुंचे उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं को जबरन हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार के साथ बल प्रयोग भी किया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पिछले सात वर्ष केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता के प्रति संवेदनहीन व्यवहार किया है।

## 'सुपरटेक ने हरित क्षेत्र का अतिक्रमण कर एमेरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में दो टावर बनाए'

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** नोएडा स्थित एमेरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड ने हरित क्षेत्र का अतिक्रमण करके और दो बड़ी टावर बनाकर बढ़े हुए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का फायदा लेने की कोशिश की है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने दो टावरों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के आदेश के खिलाफ सुपरटेक लिमिटेड की अपील पर अंतिम सुनवाई शुरू की है। रेजिडेंट एसोसिएशन ने अदालत से कहा कि एफएआर बढ़ने के बाद भी बिल्डर हरित क्षेत्र नहीं बदल सकता।

एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने कहा कि नियमों के अनुसार, बिल्डर फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना हरित क्षेत्र को नहीं बदल सकता। गार्डन एरिया न केवल ब्रोशर में बल्कि कंप्लीशन प्लान में भी दिखाया गया था। अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

# त्रासदी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा, तो फिर आक्सीजन बांटने वाले सभी गुरुद्वारे, मंदिर व सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे ड्रग कंट्रोलर
- ड्रग कंट्रोलर को दिया दो दिन के अंदर मामले में निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश

भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानवीय त्रासदी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गौतम गंभीर व प्रवीण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ड्रग कंट्रोलर की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि क्या प्रवीण कुमार दवा का वितरण कर रहे थे। इसके जवाब में ड्रग कंट्रोलर की तरफ से पेश हुईं अधिवक्ता नंदिता राव ने कहा कि प्रवीण कुमार अपने स्तर पर पंजाब से आक्सीजन हासिल कर रहे थे। ड्रग कंट्रोलर की इस दलील पर पीठ ने कहा कि ऐसे में फिर तो ड्रग कंट्रोलर को सभी गुरुद्वारों, मंदिरों और सभी सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

पीठ ने कहा कि आखिर एक व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्र व दिल्ली सरकार आक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई और इन्हीं लोगों ने आक्सीजन उपलब्ध कराई। इसके जवाब में जब राव ने दलील दी कि ड्रग कंट्रोलर ने अदालत के तीन जून के आदेश के तहत कार्रवाई की है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर आप इसे आधार बना रहे हैं, तो फिर सभी गुरुद्वारों, मंदिर और सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करिए। राव ने दलील दी कि दोनों के पास आक्सीजन को रखने का लाइसेंस नहीं था। इस पर पीठ ने कहा हम आपकी दलील को रिकार्ड पर लेते हैं कि आप दिल्ली में आक्सीजन जमा करने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। राव इसके जवाब में कहा कि जिनके खिलाफ शिकायत मिली है उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या आपकी आंखें बंद हैं, आपको आक्सीजन की मांग करते और वितरण करने की फोटो मीडिया में दिखाई नहीं दी। पीठ ने कहा कि आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वह सिर्फ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि जहां तक गौतम गंभीर का मामला है, उन्होंने गैरजिम्मेदार तरीके से कोरोना की दवा को जमा किया था, उनके इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन तरीका ठीक नहीं था।

इस पर राव ने कहा कि उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाए, वे उचित कार्रवाई करेंगी। पीठ ने कहा कि हम आपको दो सप्ताह का समय नहीं देंगे, आप दो दिन के अंदर जवाब दाखिल करें। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

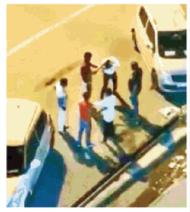
# कांस्टेबल ने युवक को किया अगवा, पीट-पीटकर कर मार डाला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- रौडरेज में साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम, शव को मोदीनगर के गंगनहर में फेंका
- आरोपित पुलिसकर्मी एक साथी के साथ गिरफ्तार, सेवा से बर्खास्त

न्यू अशोक नगर इलाके में रोडरेज के मामले में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की सरेराह पिटाई की। उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद कार में उसकी पीट-पीटकर हत्या करके शव को मोदीनगर में गंग नहर में डाल दिया। चार जून की इस वारदात में डेढ़ महीने तक युवक अजित के स्वजन थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस परिवार को टहलाती रही। कुछ दिन पहले वारदात का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चार लोग अजित और उसके दोस्त अतुल को पीटते हुए नजर आए। पुलिस के हाथ जब वीडियो लगा तो वारदात से पर्दा उठा। पुलिस ने पांडव नगर थाने में तैनात आरोपित कांस्टेबल मोनू सिरोही और लक्ष्मी नगर निवासी उसके दोस्त हरीश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाकी दो साथी विकास और विनीत अभी फरार हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त सागर प्रीत ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर न्यू अशोक नगर के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। वहीं आरोपित मोनू को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस को फिलहाल अजित का शव बरामद नहीं हुआ है, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोनू की कार बरामद कर ली है।

पुलिस के अनुसार अजित अपने परिवार के साथ बी-ब्लाक, न्यू कोंडली में रहते थे। उसके परिवार में मां कृष्णा देवी, भाई अशोक और बहन नीतू है। अजित कोंडली रोड पर ही फल की रेहड़ी लगाते थे। उनकी बहन नीतू ने बताया कि चार जून रात आठ बजे अजित कोंडली रोड से सब्जी खरीदने के लिए गए थे, रास्ते में उन्हें उनका दोस्त अतुल मिल गया। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। उसी दौरान एक कार में सवार चार लोग वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। चारों युवकों ने बुरी तरह दोनों को पीटा, अतुल किसी तरह वहां से भाग गया। डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आरोपितों ने उनके भाई को पकड़े रखा और कार में अपहरण कर ले गए। वारदात का वीडियो घटनास्थल के पास एक मकान में रहने वाले युवक ने अपने फोन से बना लिया।



सड़क पर दोनों युवकों को (सफेद कमीज में) पीटते हुए आरोपित। वीडियो ग्रेब

**थाने के चक्कर काटता रहा पीड़ित परिवार :** इस बीच सात जून को अतुल से परिवार ने पूछताछ की तो अपहरण का पता चला। इसके बाद परिवार न्यू अशोक नगर थाने के चक्कर काटता रहा, कड़ी मशक्कत के बाद 13 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट ली गई। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो दिन पहले यह वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। इसके बाद अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच स्पेशल स्टाफ को सौंपी गई। स्पेशल स्टाफ को वीडियो में कार का नंबर दिखा। यह कार मोनू की थी। इसके बाद मोनू को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि अजित की हत्या कर शव को गंगनहर में फेंक दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने एफआइआर में हत्या और साजिश रचने की धाराएं जोड़ीं।

**कार के सामने आ गए थे युवक:** सूत्रों की मानें तो चार जून को मोनू ही कार चला रहा था। कार में सवार चारों आरोपितों ने शराब पी हुई थी। जब वह कार लेकर न्यू कोंडली रोड पर पहुंचा तो उसकी कार के आगे अजित और उसका दोस्त आ गया। इस पर गुस्साए मोनू ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब युवकों ने विरोध किया तो मोनू और उसके साथियों ने दोनों को जमकर पीटा।

**समस्या**

छोटे पार्कों और कालोनियों से कीकर उन्मूलन पर नहीं है किसी का ध्यान, ट्री एक्ट में संरक्षण मिले होने के कारण अधिकारी भी नहीं करते हैं पहल

# कालोनियों, गांवों व छोटे वन क्षेत्रों में भी फैल रहा कीकर

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए सेंट्रल रिज को विलायती कीकर से मुक्त करने की योजना बनाई गई है। सेंट्रल रिज के तहत आने वाले बुद्धा जयंती पार्क, तालकटोरा स्टेडियम व दिल्ली कैंट के बड़े क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से कीकर मुक्त किया जाना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति व डीडीए की बायोडायवर्सिटी पार्क परियोजना के प्रभारी प्रो. सीआर बाबू के नेतृत्व में दिल्ली के अन्य बायोडायवर्सिटी पार्कों में भी यह काम किया जा रहा है, लेकिन राजधानी की कालोनियों व गांवों के पार्कों और हरित क्षेत्रों में फैले कीकर पर किसी का ध्यान नहीं है। यहां से कीकर हटाने के लिए न तो कोई योजना चल रही है और न ही स्थानीय लोग इन्हें हटा सकते हैं। कानूनी मजबूरियों और जटिल प्रक्रिया के कारण बायोडायवर्सिटी पार्कों से भी कीकर को पूरी तरह से खत्म होने में अभी कई साल लग सकते हैं।



कालकाजी इलाके में स्थित हंसराज सेठी उद्यान में लगे कीकर के पेड़। जागरण

ग्रेटर कैलाश के जहांपनाह सिटी फारेस्ट, कालकाजी स्थित हंसराज सेठी उद्यान, ओखला स्थित डीडीए की भूमि, तुगलकाबाद फोर्ट का इलाका, एमबी रोड पर लालकुआं व प्रेमनगर आदि इलाके कीकर से भरे पड़े हैं। हालांकि, जहांपनाह सिटी फारेस्ट व हंसराज सेठी उद्यान में देशज पेड़-पौधे लगाकर चरणबद्ध तरीके से कीकर को हटाया जा रहा है, लेकिन कालोनियों व गांवों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारी निगम व वन विभाग से कीकर हटाने के संबंध में शिकायत भी करते हैं तो उन्हें नियम-कानून का हवाला देकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

**कानूनी संरक्षण बन रहा कीकर उन्मूलन में बाधा :** बायोडायवर्सिटी पार्कों में कीकर उन्मूलन के लिए काम कर रहे पारिस्थितिकी विज्ञानियों का कहना है कि कीकर को काटने या पूरी तरह से हटाने में सबसे बड़ी बाधा ट्री एक्ट है। सभी पेड़ों की तरह कीकर को भी इस एक्ट में कानूनी संरक्षण प्राप्त है। बिना काटे कीकर को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। दक्षिणी दिल्ली के उप वन संरक्षक अमित आनंद ने बताया कि पहले कीकर की टहनियों को काटकर इसकी छाया खत्म की जाती है। फिर इसके आसपास देशज पौधे लगाए जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी छाया में कीकर की ठूंठ को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे वह धीरे-धीरे सूख जाता है।

**विलायती कीकर के ये हैं नुकसान**

- देशज पेड़ों की जड़ें पानी को ऊपर खींचती हैं, जिससे भूजल स्तर ऊपर उठता है, जबकि कीकर की जड़ें बहुत गहरे तक जाकर पानी सोख लेती हैं। इससे कीकर के आसपास की जमीन का भूजल स्तर और गिरता जाता है। यह देशज पेड़ों की अपेक्षा अधिक पानी सोखता है।
- खुद जीवित रहने के लिए कीकर देशज पेड़-पौधों की तुलना में ज्यादा पोषक तत्व व पानी का दोहन करता है, इसलिए इसके आसपास अन्य पेड़-पौधों के लिए पोषक तत्व बचते ही नहीं हैं।
- इसमें जहरीले रासायनिक तत्व होने के कारण इसकी पत्तियां डिकंपोज नहीं होती हैं। इससे पेड़ के नीचे न तो कोई अन्य पौधा उगता है और न ही मिट्टी में नमी रह जाती है। इस कारण पेड़ के नीचे कीट-पतंगे भी नहीं पनपते हैं, इसलिए कीकर पर न तो कोई चिड़िया आती है और न ही कोई अन्य जीव-जंतु। इससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है।

**32** मामले जाली पासपोर्ट और वीजा पर यात्रा करने के सामने आए हैं इस वर्ष जनवरी से जून के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर। 2020 और 2019 में ऐसे मामलों की संख्या क्रमशः 56 और 171 थी।



# लगातार आठवें दिन संसद में हुआ हंगामा

## पेगासस कांड पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, सरकार भी झुकने को राजी नहीं

### सरकार ने शोर–गुल के दौरान ही पारित करा लिए तीन विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड पर संसद में जारी संग्राम के थमने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष जासूसी कांड पर बहस की मांग से पीछे हटने को राजी नहीं है तो सरकार भी विपक्षी दलों के दबाव में चर्चा की मांग पर मानने को तैयार नहीं दिख रही। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कायम इस गतिरोध के चलते आठवें दिन भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ और कामकाज सुचारु रूप से नहीं हो पाया। हंगामे-नारेबाजी के बीच सरकार ने लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक विधेयक पारित करा लिया।

पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष एकजुट होकर सरकार की घेराबंदी में जुटा है। गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो संसद में शोर-गुल और नारेबाजी कर कार्यवाही ठप कराई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने बुधवार को कांग्रेस व तृणमूल समेत कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा कागज फाड़कर आसन और प्रेस दीर्घा की ओर उछालने के आचरण पर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सदस्यों के ऐसे व्यवहार से आहत हैं। सदस्यों को चेतावनी देते हुए स्पीकर ने कहा कि दुबारा इस तरह का आचरण करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

स्पीकर की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष सदन में बहस और कामकाज चलाने के पक्ष में हैं, लेकिन मौजूदा गतिरोध की वजह सरकार की जिद है और वह विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने नहीं दे रही है। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने अधीर को बीच में ही रोकते हुए कहा कि आरोप लगाने के बजाय कागज उछालने वाले सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। जोशी के जवाबी हमलों के बाद शोर-शराबा बढ़ गया और सदन 11.30 बजे तक स्थगित हो गया। सदन फिर शुरू हुआ तो स्पीकर की जगह पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामे में ही बचा हुआ प्रश्नकाल चलाया। सदन दो बार और स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे पीठासीन सभापति भाजपा के किरीट सोलंकी ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच दो विधेयक ध्वनिमत से पारित करा दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट्स इकोनामिक रेगुलेटरी अथारिटी संशोधन बिल पेश कर अपनी बात रखी और फिर इसे बिना बहस पारित कर दिया गया। इसके बाद जहाजरानी व पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल परिवहन बिल पेश कर इसे पारित कराया। इन दोनों विधेयकों के पारित होते ही लोकसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

**विपक्ष ने पहले ही दिखाए अपने तेवर :** जासूसी कांड पर विपक्ष ने अपने रुख से पीछे नहीं हटने का संदेश सदन शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए दे दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए जासूसी कांड पर बहस की विपक्ष की मांग दोहराई।

**राज्यसभा में भी हुआ हंगामा :** राज्यसभा में भी पेगासस जासूसी पर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन लंच से पहले दो बार ठप हुआ। सभापति वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस खारिज कर दिए। हालांकि इस दौरान उपसभापति हरिवंश ने हंगामे में ही आधे घंटे से ज्यादा प्रश्नकाल चलाया। दो बजे जब फिर सदन शुरू हुआ तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने फैक्ट्री रेगुलेशन संशोधन बिल पेश किया। हंगामे के बीच ही भाजपा, अन्नाद्रमुक और टीआरएस के एक-एक सदस्य ने संक्षिप्त चर्चा में अपनी बात रखी। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित कर कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।


पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों पर गुरुवार को भी राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। प्रेट्र

#### 500 लोगों, समूहों ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को 500 से अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिख कर कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फौरन हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने इजराइली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है।

उन्होंने मीडिया में आई इन खबरों पर हैरानी जताई कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल छात्राओं, विद्वानों, पत्रकारों, मानवाधिकार के पैरोकारों, वकीलों और यौन हिंसा पीड़िताओं की निगरानी के लिए किया गया। शीर्ष कोर्ट से यौन उत्पीड़न पर लैंगिक रूप से तटस्थ डाटा सुरक्षा और निजता नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है।

# देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी सरकार : जयशंकर

- राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह भी कहा कि भारत को विश्वास है कि क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में उसके सहयोगी मदद करेंगे।

विदेश मंत्री ने कहा कि इसी सप्ताह भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मानवाधिकारों, लोकतंत्र, तस्करी, प्रौद्योगिकी और अफगानिस्तान सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर उनकी अच्छी और व्यापक बातचीत हुई।

उनसे सदन में पूछा गया कि क्या चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने अमेरिका की मदद मांगी है, इस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि अमेरिका के साथ हमारा मजबूत सुरक्षा और संरक्षा सहयोग है। हमने नीतियों का आदान प्रदान किया है, अभ्यास खासकर नौवहन अभ्यास किए हैं। भारत सरकार हमेशा ही देश की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, उठाएगी।

ब्लिंकन के साथ बातचीत के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर हमारे रुख से अवगत कराया। उचित समन्वय की आकांक्षा रखने के साथ-साथ हमें इतिहास में हुई गलतियों को भी दुरुस्त करना है। लेकिन जब आजादी की बात हो तो आजादी को गैर-प्रशासन या जिम्मेदारियों से बचाव के तौर पर नहीं देखा चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि इस विषय पर हमारी बातचीत संतुलित होनी चाहिए। हमें यह भी लगता है कि जब वे मुद्दों को देखते हैं तो हमारे मानक समान होने चाहिए और समस्त वार्तालाप तथ्य आधारित होना चाहिए।

क्वाड और दक्षिण चीन सागर में, खासकर वहां चीन के हस्तक्षेप को देखते हुए नौवहन सुरक्षा बनाए रखने में इसकी प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि भारत की अपनी सोच है जो हिंद-प्रशांत संबंधों पर देश के हित को सर्वोपरि रखती है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि हम क्वाड को ऐसे मंच के तौर पर देखते हैं जहां चारो देश पूरी दुनिया के कल्याण के लिए एक साथ आए हैं, जो दुनिया को टीका मुहैया कराने, शिक्षा, संपर्क, नौवहन सुरक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि क्वाड के वास्तविक नजरिये को पूरी दुनिया स्वीकार करेगी, जिसे भारत ने आगे बढ़ाया है।

जयशंकर ने कहा कि देश की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े हितों को अपने प्रयासों से पूरा करने की भारत की नीति में उसके कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगी उसके साथ है। अफगानिस्तान के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ इस बारे में विस्तार से बातचीत की और भारत के रुख से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान में बातचीत से राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए, सैन्य समाधान कोई उपाय नहीं है और अफगानिस्तान में सेना का उपयोग कर नियंत्रण नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा कि समाधान के लिए राजनीतिक बातचीत आगे बढ़ाई जाए और वह नतीजे हमें कभी स्वीकार नहीं होंगे जो सेना तय करेगी। अफगानिस्तान में शांति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रुख में समानता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सभी देशों में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका का साझा उद्देश्य है।


संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में बोलते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

# चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समारोह में शामिल हुए वामपंथी नेता

- पार्टी के 100 साल पूरे होने पर भारत स्थित दूतावास ने किया था आयोजन
- भाजपा का आरोप- वाम दलों की निष्ठा भारत नहीं, बल्कि रूस–चीन के प्रति

नई दिल्ली, एएनआइ : चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को आयोजित वर्चुअल समारोह में भारत के कम्युनिस्ट (वामपंथी) नेताओं ने भी शिरकत की। भारत में चीनी दूतावास ने यह जानकारी दी। प्रेट्र के मुताबिक, चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बावजूद इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भाजपा ने वामदलों की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय हितों का विरोध और दूसरे देश के प्रति निष्ठा वाम दलों की पुरानी परंपरा है। उनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं, बल्कि रूस और चीन के प्रति है।

भारत स्थित चीनी दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी. राजा, द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार और आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक की केंद्रीय समिति के सचिव जी. देवराजन ने हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए भारत में चीन के राजदूत सन वीडांग ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सौ वर्ष होने पर 170 से अधिक देशों से 600 से अधिक राजनीतिक दलों व संगठनों ने 1,500 से अधिक बधाई संदेश या पत्र भेजे। इनमें भारत से माकपा, भाकपा और आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक शामिल हैं।

समारोह में गलवन की घटना पर वीडांग ने कहा, चीन ने कई मौकों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। गलवन घाटी और पैंगोंग झील इलाकों में सीमा पर तैनात दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। चीनी राजदूत ने कहा, 'भारत और चीन के संबंध क्षेत्र और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए अहम हैं। हमें अपने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।'

प्रेट्र के मुताबिक, वाम नेताओं के इस समारोह में हिस्सा लेने पर भाजपा सांसद और पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जब अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण किया था तो उन्होंने कम्युनिस्टों को दशकों तक विरोध प्रदर्शन करते देखा था। वे कहा करते थे कि चीन के चेयरमैन ही उनके चेयरमैन हैं। इन्हीं सब कारणों से लोगों ने उन्हें नकार दिया है। बंगाल में 2011 तक सत्ता में रहने के बावजूद वहां से उनका कोई सांसद या विधायक तक नहीं है।

पलटवार करते हुए डी. राजा ने कहा कि राष्ट्रीय हितों के बारे में कोई कम्युनिस्टों को शिक्षा न दे। कहा, 'ब्रिटिश व पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई में कम्युनिस्ट अग्रिम मोर्चे पर थे। हमने देश की स्वाधीनता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। भारत की स्वाधीनता में भाजपा, जनसंघ या आरएसएस की क्या भूमिका थी? अब वे संसद में अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं।' राजा ने कहा कि सरकार खुद कई मसलों पर चीन से बात कर रही है। सरकार शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और चीन के साथ आर्थिक सहयोग पर बैठकों में हिस्सा ले रही है।

# अफगानिस्तान के मुद्दे पर और करीब आए भारत व अमेरिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

**साझा प्रयास**
- अमेरिकी सेना के कमांडर क्लार्क के साथ सेना प्रमुख नरवणे की वार्ता में अफगान मुद्दा रहा अहम
- विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान के भीतर और पड़ोस में शांति की कोशिश में भारत

अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम और चीन की तरफ से तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करने की सूचनाओं के बीच भारत और अमेरिका की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि वह अफगानिस्तान में अपनी साझा कोशिशों को और तेज करेंगे। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की बुधवार को हुई बैठक में इस बारे में सहमति बनी और गुरुवार को अमेरिकी सेना के विशेष आपरेशन कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क के साथ भारतीय सेना के प्रमुख एमएम नरवणे के बीच हुई लंबी बातचीत में अफगानिस्तान के हालात और वहां उपजी चुनौतियों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई।

अगले हफ्ते अमेरिकी सेना के प्रमुख जेनरल जेम्स सी मैककानविले की भारत यात्रा के दौरान भी अफगानिस्तान के हालात से निबटने की साझा कवायद एक अहम मुद्दा होगा। हालांकि दोनों तरफ से इस बारे में गहरी चुप्पी है लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को जिस तरह से बीजिंग में तालिबान के शीर्ष नेताओं को बुलाकर बैठक की है उससे अमेरिका और भारत की चिंता बढ़ी है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जयशंकर के साथ साझा प्रेस कांफ्रेंस में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग-थलग होने की जो बात कही है उसके पीछे चीन के इस रवैये को ही कारण बताया जा रहा है। ब्लिंकन ने बुधवार को कहा था कि अफगानिस्तान को अमेरिका व भारत कमोवेश एक ही नजर से देखते हैं। भारत ने वहां स्थायित्व व विकास के लिए काफी काम किया है। अमेरिका भी उसके साथ मिल कर काम करेगा ताकि जो प्रगति अभी तक हासिल की गई है वह अमेरिकी सेना की वापसी से प्रभावित न हो। हम भारत के इस मत को साझा करते हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य वहां के लोगों की तरफ से ही तय होना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से बढ़ते हमले और कुछ इलाकों में उनकी तरफ से अत्याचारों को पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में ही सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया और तालिबान की प्रकृति पर सवाल उठाये।

ब्लिंकन ने जयशंकर की इस बात का समर्थन किया कि अफगान का मामला हिंसा से तय नहीं किया जा सकता। गुरुवार को भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात दोहराई कि भारत एक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक व स्थिर अफगानिस्तान देखना चाहता है जिसके भीतर भी शांति हो और जिसके पड़ोस में भी शांति हो।

यही वजह है कि गुरुवार की भारतीय सेना प्रमुख नरवणे के साथ अमेरिकी कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क की नई दिल्ली में बैठक और अगले हफ्ते अमेरिकी सेना प्रमुख की तीन दिवसीय भारत यात्रा की अहमियत बढ़ गई है।

इस बारे में पूछने पर सरकारी सूत्रों ने कोई जवाब नहीं दिया है। भारतीय सेना की तरफ से बस इतना बताया गया कि दोनों के बीच द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। अन्य जानकारों का कहना है कि दोनों पक्ष फिलहाल अफगानिस्तान के सैन्य विभाग व सुरक्षा एजेंसियों को अपनी-अपनी तरफ से मदद दे रहे हैं। भविष्य में इनके बीच अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सेना को संयुक्त रूप से भरपूर सहयोग करने की सहमति बन सकती है। अफगानिस्तान सरकार इस बारे में भारत व अमेरिका के साथ संपर्क में है।


अमेरिकी सेना के विशेष आपरेशन कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क ने गुरुवार को नई दिल्ली में थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे से मुलाकात की। प्रेट्र

## माल्या ने बैंकों का उड़ाया मजाक, कहा- अभी भी उनका पैसा है मेरे पास

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइडीबीआइ बैंक द्वारा बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से अपना पूरा बकाया वसूल कर चुकने की रिपोर्टों के साथ भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को बैंकों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अभी भी उसके पास बैंकों का धन है।

माल्या ने ट्विटर पर एक खबर पोस्ट की। इसमें कहा गया है कि आइडीबीआइ बैंक ने एयरलाइंस के ऊपर बकाया 753 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं। साथ ही माल्या ने ट्वीट किया, 'और बैंक कहते हैं, मैं उनका बकायेदार हूं।'मालूम हो कि ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को माल्या को दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी किया था। इससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई में भारतीय बैंकों के समूह के लिए किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली के लिए वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई कराने का रास्ता साफ हो गया है।

# सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने वाली सच्चर कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें सच्चर कमेटी के गठन को गैरकानूनी बताते हुए कमेटी की सिफारिशों पर अमल रोकने की मांग की गई है।

मनमोहन सिंह सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से नौ मार्च, 2005 को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके तहत मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। इसे सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने 17 नवंबर, 2006 को रिपोर्ट दी थी, जिसमें कई सिफारिशें की गई थीं।

उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीरज शंकर सक्सेना व चार अन्य ने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये दाखिल याचिका में मांग की है कि भारत सरकार को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कहीं भी आधार बनाने या उस रिपोर्ट पर अमल करते हुए मुसलमानों के लिए कोई योजना लागू करने से रोका जाए। सच्चर कमेटी का गठन गैरकानूनी था, क्योंकि उसके गठन की अधिसूचना में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह अधिसूचना कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद जारी की गई है। इसका मतलब है कि तत्कालीन पीएम ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर को जांचने के लिए अपनी मर्जी से कमेटी गठित की थी। संविधान का अनुच्छेद 14 प 15 किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ अलग व्यवहार करने की इजाजत नहीं देता है। संविधान के अनुच्छेद 340 में समाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की स्थिति जांचने के लिए आयोग गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।


जनहित याचिका दायर कर कमेटी के गठन पर उठाया गया है सवाल

याचिका में कहा गया है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं चिह्नित किया गया है। इसलिए पूरे मुस्लिम समुदाय को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर एक विशेष वर्ग मानते हुए पिछड़ों को मिलने वाले लाभ नहीं दिए जा सकते। सच्चर कमेटी के गठन को गैरकानूनी बताते हुए कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 77 के मुताबिक राष्ट्रपति की ओर से जारी होते हैं। कमेटी के गठन का आदेश अनुच्छेद 77 के मुताबिक जारी नहीं हुआ था।

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय किसी विशेष लाभ या व्यवहार का हकदार नहीं है, क्योंकि यह बहुत वर्षों तक शासक रहा और ब्रिटिश काल में भी साझी सत्ता का आनंद उठाया। आजादी से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत प्रताड़ित रहा। उसका जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण भी कराया गया। अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री की रुचि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान की थी तो उन्हें इन वर्गों के लिए लाभ की योजना लानी चाहिए थी। याचिका में कहा गया है कि नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग व साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को चुनौती दी गई है। उस मामले में दाखिल जवाब में सरकार ने मुख्य तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन परिस्थितियों में वे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं।

# संसदीय समिति को 'पिंग पोंग मैच' बना रहे हैं कुछ तत्व : थरूर

**लिया आड़े हाथ**
- पेगासस मामले में सरकारी अधिकारियों से पूछताछ का भाजपा कर रही विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक को लेकर जारी गतिरोध के बीच समिति अध्यक्ष व कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को भाजपा सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ तत्वों ने इसे 'पिंग पोंग मैच' बनाकर रख दिया है, जो संसद की भावना के अनुरूप नहीं है। समिति में पेगासस विवाद पर सरकारी अधिकारियों से पूछताछ करने का भाजपा सदस्य विरोध कर रहे हैं।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने के सवाल पर थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि इसकी कोई वैधता नहीं है। प्रस्ताव पेश करने में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को सदन की अनुमति लेनी होती है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा के निशिकांत दुबे को 'बिहारी गुंडा' कहने के आरोपों पर भी अनभिज्ञता प्रकट की। उधर, निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद को नियमों की जानकारी नहीं है और वह निराश हैं। उनका ध्यान लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की जगह कांग्रेस का नेता बनने पर ज्यादा है।

उल्लेखनीय है कि आइटी पर स्थायी समिति की बैठक गत दिवस कोरम अधूरा रहने की वजह से नहीं हो पाई थी। इसमें पेगासस जासूसी विवाद पर सरकारी अधिकारियों से सवाल-जवाब होने तय थे। बैठक कक्ष में पहुंचे समिति में शामिल भाजपा सदस्यों ने विरोध स्वरूप उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

## लाभ की बात

श्रमिक कामन सर्विस सेंटर और डाकघर में मुफ्त करा सकेंगे पंजीयन, एनआइसी तैयार कर रहा पोर्टल, मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का फायदा

# अगस्त से शुरू हो सकता प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) का काम अगले महीने शुरू हो सकता है। सरकारी एजेंसी नेशनल इनफारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए नेशनल डाटाबेस फार अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स (एनडीयूडब्ल्यू) नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। प्रवासी श्रमिकों के पंजीकृत होने से उन्हें सरकार की तरफ से दी जा रही सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ मिल सकेगा। चाहे वह श्रमिक किसी भी राज्य में काम कर रहा हो।

पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान देशव्यापी लाकडाउन होने पर प्रवासी श्रमिकों के पलायन के वक्त इस प्रकार के श्रमिकों के पंजीयन की जरूरत महसूस की गई ताकि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही सभी सरकारी लाभ मिल सकें। पिछले एक साल से भी अधिक समय से प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रम मंत्रालय की तैयारी चल रही थी।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन का काम अगस्त में शुरू हो सकता है। पंजीयन में श्रमिकों के आधार नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश भर में स्थित लगभग चार लाख कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) और डाक घर की कुछ विशेष शाखाएं पंजीयन केंद्र के रूप में काम करेंगी। प्रवासी श्रमिक इन जगहों पर जाकर अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन के लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

एक बार पंजीयन का काम शुरू होने के बाद राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों से संपर्क कर उनके डाटा को पोर्टल पर संग्रहित करेंगी। मंत्रालय के मुताबिक प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टल शुरू होने से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना जैसी स्कीमों का लाभ सभी श्रमिकों तक पहुंचाने की चुनौती खत्म हो सकती है। इसके अलावा इन श्रमिकों को ईएसआइसी और ईपीएफओ से जुड़ी स्कीमों का भी लाभ मिलेगा। कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेगा। अभी प्रवासी श्रमिकों का सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। सबसे अधिक निर्माण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय के मुताबिक भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में करीब 2.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। मंत्रालय ने निर्माण कार्यों से जुड़े इन श्रमिकों की भलाई के लिए एक माडल स्कीम तैयार की है जिसे सख्ती से लागू करने के लिए सभी राज्यों को भेजा गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने में हो रही देरी पर फटकार लगाई थी।


फाइल/इंटरनेट मीडिया

## नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक खर्च हुए 238 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन के निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास पर 63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आनी है और अगले साल अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा होना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच किए जा रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास पर 608 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इस साल नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। सरकार के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं पर वित्त वर्ष 2021-22 तक 1,289 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी



**1** अगस्त को लखनऊ में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। उनके आगमन को लेकर गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने बैठक की।



# निशिकांत को बिहारी गुंडा बोलने पर गरमाई सियासत

राज्य ब्यूरो, पटना

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुआई वाली सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की महुआ मोइत्रा ने सांसद निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा बोल दिया। इस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। भाजपा-जदयू के साथ कांग्रेस एवं राजद ने भी आपत्ति जताई है। जदयू ने ऐसी भाषा को ही गुंडई कहा है। कांग्रेस ने हिंदी पट्टी का अपमान बताया है।


महुआ मोइत्रा। फाइल/इंटरनेट मीडिया


निशिकांत दुबे। फाइल/इंटरनेट मीडिया

सबसे कड़ी प्रतिक्रिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब टीएमसी के सहयोगी राजद की सरकार थी तो सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी के कारण बिहारियों को बिहारी गुंडा जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता था। अब सुशासन की सरकार है, जिसमें बिहारी शब्द सम्मान से जुड़ा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि तृणमूल सांसद का बयान बिहारियों का अपमान और नफरत फैलाने वाला है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मोइत्रा पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

जदयू ने इस मुद्दे पर भाजपा का साथ दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तृणमूल सांसद ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वही गुंडई है। बिहार आर्यभट्ट की धरती है। यहां ज्ञान की बात होती है, गुंडई की नहीं। तृणमूल सांसद को माफी मांगनी चाहिए।

### निशिकांत ने ट्वीट कर दी जानकारी

झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बताया है कि 13 साल के संसदीय जीवन में पहली बार गाली सुनी है। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा ने बैठक में तीन बार बिहारी गुंडा बोला। उन्होंने कहा कि शशि थरूर ने संसदीय परंपरा को खत्म करने की सुपारी ले रखी है।

तृणमूल को कांग्रेस का भी साथ नहीं मिला। बिहार में कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रेमचंद मिश्रा ने इसे सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषी सभी प्रदेशों का अपमान बताया है। कहा कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बिहार के बारे में इस तरह की भाषा को बर्दाश्त से बाहर बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने मोइत्रा का बचाव करते हुए कहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शायद भाजपा के वैसे नेताओं के लिए किया गया होगा, जो विधानसभा चुनाव में बंगाल जाकर हंगामा करते रहे होंगे।

# पार्टी में नहीं होती सुनवाई, कांग्रेस कार्यकर्ता ने की खुदकुशी

जागरण संवाददाता, लुधियाना

▶ सिद्धू के नाम आडियो जारी किया, कहा, तीस साल कांग्रेस के लिए लगाए

पंजाब के विधानसभा क्षेत्र दाखा के गांव जांगपुर के एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता दलजीत सिंह हैप्पी बाजवा ने गांव हिस्सोवाल में जाकर जहर खा खुदकुशी कर ली। हैप्पी कांग्रेस के स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेल देहाती का जिला चेयरमैन थे। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी गुरुवार देर रात हैप्पी के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हैप्पी की मौत पर दुख जताया और डीजीपी दिनकर गुप्ता को आदेश दिए कि मामले की जांच कर तत्काल आरोपितों पर केस दर्ज किया जाए।

हैप्पी ने आत्महत्या करने से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को संबोधित करते हुए एक आडियो इंटरनेट मीडिया में शेयर किया। इसमें उसने कहा कि कांग्रेस वर्करों की सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अंतिम सांस तक कांग्रेस की सेवा की। तीस साल सेवा के बावजूद अपने परिवार के लिए आटा-दाल तक नहीं लगवा पाया। चुनावों में पार्टी के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कुछ और राज्यों में भी काम किया। पार्टी के पोस्टर तक लगाए। पार्टी के लिए काम करने के दौरान कई बार मुझ पर केस भी दर्ज हुए। कई तरह की चुनौतियों के बावजूद पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मिला कुछ नहीं। इस बात का मलाल हमेशा रहेगा।


दलजीत सिंह हैप्पी बाजवा। फाइल फोटो

हैप्पी ने आडियो में गांव के तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। वह कहता है कि उसने जमीन खरीदी, लेकिन उसमें भी रुकावट डाली जा रही है। अब वह अपने जीवन से परेशान है। हैप्पी के भाई सुरिंदर सिंह ने कहा कि आडियो उनके भाई का है। कांग्रेस वर्कर हैप्पी बाजवा ने आडियो में कहा कि उसने पार्टी की सेवा के लिए शादी भी नहीं की। उसने अपने भाई और उसके बच्चों के साथ ही जीवन बिताया है। भाई के बच्चों को ही अपने बच्चे समझा। सिद्धू से गुजारिश की कि वह भाई के बच्चों पर अपना हाथ रखें।

आडियो में हैप्पी बाजवा ने कहा कि उसने आंतकवाद के दौर में भी पार्टी के लिए निडर होकर काम किया। हमेशा कड़ी मेहनत की। सुनवाई नहीं होने पर अब जमीर मारकर अब आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं।

## न्यूज गैलरी

### अमेठी में बनेगा स्मृति का मकान, बेटे ने किया भूमि पूजन

**अमेठी :** केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी द्वारा खरीदे गए भूखंड पर आवास के निर्माण के लिए उनके पुत्र जोहर ईरानी ने भूमि पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने नींव की ईंट रखी। गौरीगंज के मेदन मवई गांव में भूमि पूजन के दौरान सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता भी मौजूद रहे। बीते आम चुनाव में जीत के बाद स्मृति ने यहां अपना आवास बनाने का वादा किया था। काफी समय से उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही थी। 22 फरवरी को स्मृति ने गौरीगंज के मेदन मवई राजस्व गांव में स्थित सराय भागमानी निवासी फूलमती पांडेय की 11 बिस्वा भूमि का बैनामा 12 लाख 11 हजार रुपये देकर कराया था। इसी भूमि पर गुरुवार को भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। (जासं)

### पांच साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम करेगी रूपाणी सरकार

**अहमदाबाद :** गुजरात में विजय रूपाणी सरकार के पांच साल पूरे होने पर एक से नौ अगस्त तक राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें आनलाइन भाग लेंगे। रूपाणी ने सात अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री तीन अगस्त को समारोह से वर्चुअल जुड़कर गुजरात के सवा चार लाख परिवारों को अनाज की किट के वितरण की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सात अगस्त को चार हजार करोड़ की वतन प्रेम योजना का आनलाइन लोकार्पण करेंगे। (राब्यू)

# सोनिया गांधी से बात किए बिना सत्ता व संगठन में नहीं होगा बदलाव : गहलोत

**फेरबदल ▶** राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी माकन की सक्रियता के बीच सीएम ने दिया संदेश

### उधर, विधायक बोले–गहलोत के मंत्रियों के भरोसे दोहरे अंक को पार नहीं कर सकेंगे

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

राजस्थान में सत्ता और संगठन में अमूलचूल फेरबदल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन द्वारा की जा रही रायशुमारी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विश्वस्तों को संदेश दिया है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात किए बिना कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चाहे माकन विधायकों से रायशुमारी कर लें या फिर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल फेरबदल को लेकर कसरत, लेकिन वह अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले नहीं होने देंगे।

गौरतलब है कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की तैयारी में जुटा है। इसी के तहत माकन ने जयपुर में कांग्रेस विधायकों के साथ ही गहलोत सरकार को समर्थन कर रहे 13 निर्दलीय विधायकों के साथ रायशुमारी की है।


अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से की जा रही रायशुमारी से नाराज हैं। फाइल

**पायलट खेमे को निर्दलियों को बुलाने पर आपत्ति**

पायलट खेमे ने रायशुमारी में 13 निर्दलीय विधायकों को बुलाने पर आपत्ति जताई है। पायलट खेमे के विधायक मुरारी लाल मीणा और वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि उन निर्दलियों को बुलाने का क्या मतलब, जिनके कारण कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग हारे थे। इनके स्थान पर चुनाव हारने वालों से फीडबैक लिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी निर्दलीय विधायक गहलोत के साथ हैं।

बुधवार से शुरू हुई रायशुमारी गुरुवार शाम को खत्म हुई। वन टू वन संवाद के दौरान विधायकों ने माकन से कहा कि मौजूदा मंत्रियों के भरोसे 2023 के विधानसभा चुनाव में दोहरा अंक (डबल डिजिट) पार नहीं किया जा सकता है। विधायकों ने कहा कि जनता के सरोकारों से सीधे जुड़े विभागों के मंत्रियों को जल्द नहीं हटाया गया तो कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। इस बीच पिछले दो दिनों में मिलने पहुंचे मंत्रियों और विधायकों को गहलोत ने संदेश दिया कि सोनिया गांधी के साथ बात करने के बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल अथवा राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार गहलोत माकन द्वारा की जा रही रायशुमारी से नाराज हैं। उधर, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सक्रिय रहे। उन्होंने दो दिन में कई नेताओं से मुलाकात की।

**माकन इन मुद्दों पर कर रहे संवाद:** माकन ने सरकार के कामकाज, मंत्रियों के व्यवहार और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति व संगठन के मौजूदा हालातों को लेकर विधायकों से फीडबैक लिया। उन्होंने गुरुवार को 20 जिलों के 52 विधायकों के साथ वन टू वन चर्चा की। इससे पहले बुधवार को 65 विधायकों से संवाद किया था।

सूत्रों के अनुसार दोनों दिन विधायकों ने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभागों में कामकाज की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई।

**भड़के चिकित्सा मंत्री :** खुद को हटाए जाने की चर्चा और विधायकों की नाराजगी झेल रहे चिकित्सा मंत्री डा. रघु शर्मा ने कहा कि रायशुमारी को लेकर जो सुर्खियां बन रही हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। बिना पायलट खेमे का नाम लिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हटाने की बातें नियोजित रूप से उछाली जा रही हैं। वहीं, पायलट के विश्वस्त रामनिवास गावड़िया ने पत्रकारों से कहा कि डोटासरा ने शिक्षा का भगवाकरण किया, इसलिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं।

**सीएम के रात्रि भोज में नहीं पहुंचे पायलट :** सीएम गहलोत ने गुरुवार देर शाम विधायक दल की बैठक बुलाई। उन्होंने विधायकों को रात्रि भोज भी दिया। हालांकि, रात्रि भोज और विधायक दल की बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। वह दो दिन से दिल्ली में हैं। उनके खेमे के विधायक रमेश मीणा और हेमाराम चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंचे।

# सिद्धू ने फिर कैप्टन पर साधा निशाना, बोले– प्रयास नहीं परिणाम चाहिए

जागरण संवाददाता, जालंधर

▶ कहा, हाईकमान द्वारा दिए गए 18 सूत्रीय फार्मूले को सरकार को लागू ही करना पड़ेगा

पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद पहली बार जालंधर दौरे पर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, किसी इंसान की काबिलियत का पता इससे चलता है कि किसी भी काम को उस व्यक्ति ने किस तरह से पूरा किया है। प्रयास करने से ज्यादा परिणाम जरूरी है। सिद्धू ने यह प्रतिक्रिया बीते दिन कैप्टन की तरफ से विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की बात पर दी।

सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पंजाब के लोगों व उनके हितों की पहरेदारी की है। अब पंजाब में कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिए गए 18 सूत्रीय फार्मूले को लागू करवाया जाएगा और इसे सरकार को लागू करना ही पड़ेगा।

गुरुवार को सिद्धू ने जालंधर के कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों को संबोधित करने से पहले मीडिया से बातचीत में नए कृषि कानूनों का जिक्र किए बिना कहा कि केंद्र सरकार को तीन काले कानूनों को रद करना ही पड़ेगा। यह कानून राज्यों के अधिकारों पर डाका हैं।

# सामूहिक दुष्कर्म मामले में गोवा के सीएम के बयान पर बवाल

▶ विपक्षी दलों ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा,बीच पर दुष्कर्म का आरोपित सरकारी कर्मी निलंबित

**पणजी, प्रेट्र :** गोवा में एक बीच पर दो नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में विपक्ष के दबाव का सामना कर रही राज्य की भाजपा सरकार विवाद में घिर गई है। यह विवाद दुष्कर्म पीड़िताओं को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी से जुड़ा है। सावंत ने कहा है कि माता-पिता को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके बच्चे देर रात बीच पर क्यों थे।

सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बुधवार को सावंत ने कहा, 'जब 14 साल के किशोर-किशोरियां पूरी रात बीच पर गुजारते हैं तो माता-पिता को आत्ममंथन करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बच्चे बात नहीं सुनते हम अपनी जिम्मेदारी सरकार व पुलिस पर नहीं थोप सकते।' गृह मंत्रालय का भी दायित्व संभाल रहे सावंत ने कहा कि माता-पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने इशारा किया कि अभिभावकों को बच्चों, खासकर नाबालिगों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए।

सावंत ने कहा, 'हम सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि 10 युवक बीच पर पार्टी करने गए थे, जिनमें से छह घर लौट गए और चार पूरी रात वहां रहे।' उन्होंने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान सदन को बताया कि आरोपित सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। उसे बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले के चारों आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सावंत के इस बयान को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता अल्टोन डीकोस्टा ने कहा कि गोवा में कानून-व्यवस्था खराब हो रही है। कहा, 'हमें रात में घूमने में डर क्यों लगना चाहिए? अपराधियों को जेल में होना चाहिए।' गोवा फारवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा, 'लोगों की सुरक्षा पुलिस व सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।' निर्दलीय विधायक रोहन खोंटे ने ट्वीट किया, 'अगर राज्य सरकार हमें सुरक्षा नहीं देगी तो कौन देगा? गोवा ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश रहा है।' सदन में बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर पुलिस को बचाने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था।

उल्लेखनीय है कि गोवा में बेनालिम बीच पर रविवार की रात चार लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए दो नाबालिगों से दुष्कर्म किया था और उनके साथ के लड़कों की पिटाई की थी। इनमें से एक कृषि विभाग का वाहन चालक है।

# विधायकों से बातचीत पूरी, आलमगीर जल्द भेजेंगे रिपोर्ट

**राज्य ब्यूरो, रांची :** झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में आलाकमान को रिपोर्ट देने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सभी विधायकों का मंतव्य प्राप्त कर लिया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क करनेवालों की सूची में शामिल था। इस बीच, एक बात साफ तौर पर सामने आई है कि अधिसंख्य कांग्रेस विधायकों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी और काम नहीं हो पाने के कारण नाराजगी है। विधायकों ने छोटी-छोटी मांग भी पूरी नहीं होने की बात बताई है। अब जल्द ही आलमगीर आलम पूरी रिपोर्ट आलाकमान को भेज देंगे। इस बीच, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव इस मामले को अधिक तूल नहीं देना चाहते हैं और विधायकों के साथ खड़े हैं।

झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने गुरुवार तक प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों का मंतव्य जान लिया और अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अब वे एक-दो दिनों में आलाकमान को पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट भी भेज देंगे। इसके बावजूद उनकी बातचीत के क्रम में विधायकों ने काम नहीं होने को लेकर अपनी नाराजगी बताई। विधायकों की यह शिकायत भी है कि क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को वाजिब सम्मान नहीं मिल पा रहा है।

# बंगाल में लगवाएं इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग : ममता

▶ बंगाल की सीएम ने गडकरी से सड़क समेत अन्य परियोजनाओं पर भी की चर्चा

▶ कभी टाटा को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर कर चुकी हैं ममता

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** बंगाल के सिंगूर में प्रस्तावित टाटा की नैनो कार परियोजना को आंदोलन के जरिये राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर करने वाली ममता बनर्जी ने अब बुनियादी ढांचे के विकास व उद्योगों की स्थापना के लिए वैश्विक निवेश को आमंत्रित करने की दिशा में पहल की है। इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की स्थापना की इच्छा जताई। उन्होंने यह भी कहा कि उनका राज्य बांग्लादेश, नेपाल व भूटान का सीमावर्ती और पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, इसलिए वहां बेहतर सड़कों के नेटवर्क की जरूरत है।

आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने और एक मोर्चे पर लाने की उम्मीद के साथ दिल्ली दौरे पर आईं ममता बनर्जी ने गडकरी से ताजपुर में गहरे समुद्र के बंदरगाह समेत लंबित सड़क व परिवहन परियोजनाओं पर बातचीत की। कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित इस बंदरगाह में 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इसे पूरा होने पर बंगाल में रोजगार के 25 हजार नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

ममता ने कहा, 'नितिन गडकरी ने मुझे अपने मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। उनके महानिदेशक, लोकनिर्माण मंत्री, सचिव, परिवहन सचिव व वह खुद भी वहां होंगे। मेरे मुख्य सचिव शुक्रवार को बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हैं। गडकरी जी की सुविधा के लिए मैं अपने मुख्य सचिव को उनसे मुलाकात करने के लिए भेज दूंगी।'


बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। एएनआइ

गडकरी के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की।'

सूत्रों ने भी बताया कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत बंगाल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर केंद्रीय मंत्री को एक रिपोर्ट भी सौंपी। वह जल्द ही पेट्रोलियम, विमानन, रेलवे और वाणिज्य जैसे अहम विभागों के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगी।

# बंगाल में रास की सीट पर टीएमसी की जीत तय

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता :** बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर नौ अगस्त को होने वाले उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत तय है, क्योंकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रत्याशी नहीं उतारने की घोषणा की है। गौरतलब है कि भाजपा ने पहले इस सीट पर उम्मीदवार उतारने का एलान किया था। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से राज्यसभा की यह सीट रिक्त हुई थी। अब तृणमूल कांग्रेस ने प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार को उम्मीदवार बनाया है। वह बुधवार को विधानसभा जाकर नामांकन पत्र भी जमा कर चुके हैं। आंकड़ों के हिसाब से जवाहर सरकार का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट तृणमूल कांग्रेस के ही पास थी।

दूसरी ओर बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने उत्तर 24 परगना जिले की हाबरा विधानसभा सीट से विधायक ज्योतिप्रिय मलिक की जीत को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सिन्हा इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे।

# 2022 ही नहीं 2024 के लिए कसें कमर : नड्डा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विकास कार्यों के साथ-साथ जातिगत समीकरण और जनसंपर्क ही भाजपा का चुनावी मंत्र है। दिल्ली में दो दिनों तक चली उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों की बैठक में यह स्पष्ट हो गया। गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर संभाग के सांसदों के साथ बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों और सप्ताह में दो दिन टीकाकरण केंद्रों के दौरे का निर्देश दिया। वहीं, मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले मंत्रियों का अलग-अलग जिलों में स्वागत का भी कार्यक्रम बनाने को कहा गया है। यानी जिस जिले से मंत्रियों की यात्रा निकलेगी वहां के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। यह स्पष्ट किया गया कि न केवल 2022 बल्कि 2024 के लिए भी अभी से सबको जुटना है।

बुधवार को सांसदों की बैठक में नए मंत्रियों को आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा गया था। गुरुवार को दूसरे सांसदों को भी बताया गया कि अपने-अपने जिलों में वे भी उनका स्वागत करें। मालूम हो कि उप्र से नए बने मंत्रियों में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण जाति के मंत्री हैं। बताने की जरूरत नहीं कि बसपा, कांग्रेस व सपा भी अलग-अलग जातियों को लुभाने में लगे हैं।



नई दिल्ली में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के पार्टी सांसदों की बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। एएनआइ

नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। नड्डा के अलावा केवल योगी ने बैठक को संबोधित किया। उनका संबोधन मुख्यतः राज्य में हो रहे विकास कार्यों पर था। सूत्रों के अनुसार, योगी ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और गन्ना भुगतान समेत कुछ बातों का भी जिक्र किया। सांसदों को राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में पुस्तक दी गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की थी। संदेश साफ है कि सभी सांसदों को अपने-अपने जिलों में प्रचार-प्रसार भी करना है और उम्मीदवारों की जीत की जिम्मेदारी भी लेनी है।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। भाजपा अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही दो लाख गांवों में स्वयंसेवक मुस्तैद करने की घोषणा की है। 'अपना बूथ कोरोना मुक्त' का नारा दिया गया है। उसके लिए प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। गुरुवार को उन्होंने सांसदों को याद दिलाया कि उन्हें सप्ताह में कम से कम दो बार टीकाकरण केंद्रों का दौरा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि ईमानदारी से काम हो रहा है। सांसदों से कहा गया है कि मानसून सत्र खत्म होते ही सभी अपने-अपने क्षेत्रों में रहें। स्वतंत्रता के 75वें साल के लिए प्रधानमंत्री की ओर से जो कार्यक्रम दिया गया है, उसका क्रियान्वयन करें और गावों में प्रवास करें।

# लालू ने जातिगत जनगणना को बताया जरूरी

राज्य ब्यूरो, पटना

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद देश-प्रदेश की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शासन में देश बहुत पीछे चला गया है। इसे पटरी पर लाना होगा, जो आसान नहीं है। इसी के साथ उन्होंने पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग की आबादी की वास्तविक संख्या और हकीकत जानने के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया।

लालू ने गुरुवार को दिल्ली में कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद लालू अभी दिल्ली में राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास में रह रहे हैं। टीका लगवाने के बाद लालू ने मीडिया को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में तबीयत में सुधार है। जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद पटना भी जाना है। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले पर लालू ने कहा कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन में घुसकर विधायकों की पिटाई कर दी जाए।

**तेजस्वी बोले, कुत्ते–बिल्ली की गणना करा रहे पर पिछड़े व अति पिछड़े की नहीं**

जातीय जनगणना पर राजद ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। वैसे विधानसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल के ठीक पहले इस प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने की अनुमति जरूर दी। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि कुत्ते–बिल्ली की गणना हो रही, लेकिन पिछड़े व अति पिछड़े की नहीं।

**विपक्ष को एकजुट करना जरूरी :** राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह से मुलाकात के बारे में लालू ने बताया कि सबको एकजुट करना जरूरी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली में रहकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दीदी अपना काम कर रही हैं।

**तेजस्वी में नेतृत्व का जबरदस्त गुण :** जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी लालू ने अपने पुराने स्टैंड को दोहराया। अपने बेटे तेजस्वी यादव की मांग का समर्थन किया और कहा कि किसकी कितनी आबादी है, इसे पता किया जाना चाहिए। इसे लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। लालू ने तेजस्वी की तारीफ की। कहा कि मैं जेल में था, फिर भी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अच्छी मेहनत की थी। देश-प्रदेश के लोगों ने इसे देखा है। वह मुझसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी के बनाने से कोई नेता नहीं होता है। खुद बन जाता है। उनकी सभाओं में जुट रही भीड़ को देखकर समझा जा सकता है। लालू ने आरोप लगाया कि बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने दी गई।

**50** लाख घरों में शौचालय बनाए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में। एक लाख सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने ओडीएफ प्लस नियमावली जारी की।



# झारखंड में जज की हत्या न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला : हाई कोर्ट

सही दिशा में जांच नहीं होने पर सीबीआइ को सौंप देंगे मामला , जब नक्सलियों का वर्चस्व था तब भी कभी जज को नहीं बनाया निशाना, घटना से राज्य के कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, डीजीपी करें निगरानी

**अदालत की टिप्पणी**

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पहले राज्य में नक्सलियों का बोलबाला था, लेकिन उन्होंने कभी भी न्यायिक पदाधिकारी को निशाना नहीं बनाया। जब राज्य में नक्सलियों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। सीसीटीवी फुटेज देखकर प्रतीत होता है कि जज उत्तम आनंद की हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। राज्य की कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। कुछ दिनों पहले एसआइ रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत, सोमवार को एक वकील की दिनदहाड़े हत्या और फिर धनबाद में एक जज की हत्या हो गई। यह घटना न्यायिक पदाधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव डालेगी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उक्त बातें कही।

अदालत ने इस मामले में धनबाद के प्रधान जिला जज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए एडीजी संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एसआइटी जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगी और एसआइटी समय-समय पर अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी। अगर किसी भी समय अदालत को ऐसा प्रतीत हुआ कि जांच सही दिशा में नहीं है, तो इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इसकी जांच एसआइटी कर रही है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में एक मामले की जांच एसआइटी को सौंपी है, लेकिन एसआइटी जांच से कोर्ट को बहुत ही निराशा हुई है। अदालत ने कहा कि इस घटना के बाद बड़े अपराधियों का मामला न्यायिक पदाधिकारी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि वर्तमान हालात में वे स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। यह देश की पहली घटना है, जहां एक न्यायिक पदाधिकारी की हत्या की गई है।

**अपराध के ग्राफ की मानीटरिंग करें डीजीपी :** सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी राज्य में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को देखा है। उनको इसकी निगरानी करनी चाहिए तभी तो अपराध पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस पर डीजीपी ने कहा कि 11 फरवरी 2021 को उन्हें डीजीपी पद पर तैनाती मिली है। उन्होंने अपराध का डाटा नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही इससे संबंधित डाटा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि सिनेमा समाज का आइना होता है। गैंग आफ वासेपुर फिल्म देखी ही होगी। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन सच्चाई तो है, क्योंकि धनबाद में कोल माफिया काम करते हैं। अगर इस मामले की जांच में देरी हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा।

**सीजेआइ ने ली रिपोर्ट :** सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गुरुवार को कहा कि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान ले चुके हैं और मामले में संबंधित अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह बात उस समय कही, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस घटना का उल्लेख किया और कहा कि यह हमला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निर्लज्ज हमला है। सिंह ने कहा कि मामले में जांच सीबीआइ को दी जानी चाहिए, क्योंकि एक गैंगस्टर को जमानत नहीं देने पर न्यायिक अधिकारी की हत्या न्यायिक व्यवस्था पर हमला है।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने सिंह से कहा, घटना के बारे में हमें पता है और हम एससीबीए (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) के प्रयासों की सराहना करते हैं। मैंने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। वहां मामला चल रहा है। इसे वहीं रहने दीजिए। इस स्थिति में शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय मामले का पहले ही संज्ञान ले चुका है।



झारखंड के धनबाद में पैदल सैर कर रहे जज उत्तम आनंद को एक आटो टक्कर मारकर भाग निकला। वह काफी देर तक घटनास्थल पर पड़े रहे और उनकी मौत हो गई। एएनआइ

## ऐसे मिला सुराग

प्रथम पृष्ठ से आगे

घटना के बाद पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच शुरू की। प्रमुख सड़कों पर लगे सभी सीसीटीवी को खंगाला गया। पुलिस की तकनीकी टीम के अलावा फोरेंसिक और साइबर सेल की भी मदद ली गई। इसके सहारे आटो के गिरिडीह में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां जाकर आटो को बरामद किया। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की 50 से अधिक टीम काम कर रही है।

**जिसका परिवार दूसरों को न्याय दिला रहा था, आज उसे चाहिए इंसाफ :** जज उत्तम आनंद गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जज के भाई सुमन आनंद इस दुख की घड़ी में बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उन्होंने कहा-जिसका परिवार लोगों को न्याय देने का काम कर रहा था, आज उसे खुद इंसाफ की दरकार है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य सुबूतों से स्पष्ट है कि मेरे भाई की सुनियोजित तरीके से हत्या हुई है। परिवार ने सीबीआइ जांच की मांग की है।

# 30 लोग अब भी लापता, नहीं मिला सुराग

**सर्च अभियान** ▸ जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में जुटे रहे बचाव दल

एनडीआएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, अपनों को ढूंढने में जुटे स्वजन

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल फटने और भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, करीब 30 लोग बाढ़ के पानी में बह गए, जिनका गुरुवार को भी कुछ पता नहीं चला है। किश्तवाड़ जिले की दच्छन तहसील के हंजर गांव में बादल फटने से लापता 19 लोगों का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। बचाव कार्य में वायुसेना की टीमें उतर चुकी हैं। इसी बीच एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें हेलीकाप्टर से घटनास्थल पर पहुंचाई गई हैं। दो घायलों को एयरलिफ्ट कर किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं, राज्य प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का आश्वासन दिया है। बता दें कि बुधवार तड़के हंजर गांव में बादल फटने से गांव में कई लोग बह गए थे। बुधवार को सात शव बरामद हो गए थे, जबकि 17 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं, 19 लोगों का गुरुवार को भी सुराग नहीं लगा है।

**हिमाचल में नहीं लगा लापता 11 लोगों का सुराग :** हिमाचल के लाहुल स्पीति के तोंजिंग व कुल्लू के ब्रह्मगंगा नाला में बादल फटने से आई बाढ़ में बहे 11 लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तोंजिंग और ब्रह्मगंगा नाला में सर्च अभियान के दूसरे दिन रेस्क्यू टीमों को कुछ नहीं मिल पाया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने जाहलमा व तांदी से कीर्तिंग तक सड़क बहाल कर ली है। काजा मार्ग भी बहाल हो गया है, जबकि बीआरओ लेह मार्ग बहाली के करीब है।

**हेलीकाप्टर से पहुंची एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें :** जम्मू से वायुसेना के तीन हेलीकाप्टर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और डाग स्क्वायड की टीमों को हंजर तक पहुंचाया। पूरे दिन बचाव कार्य जारी रहा, लेकिन सुराग नहीं मिला।

**दच्छन से लेकर रामबन तक रेड अलर्ट घोषित :** बादल फटने से आई बाढ़ के कारण बड़े-बड़े पत्थर इलाके में फैल गए हैं। कुछ पेड़ गिरे पड़े हैं।



किश्तवाड़ बादल फटने से गंभीर तौर पर घायल लोगों को वायुसेना एयरलिफ्ट कर रही है। इन्हें जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीआरओर डिफेंस

तोंजिंग नाला में लापता लोगों की तलाश में सर्च अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। दिनभर रेस्क्यू टीमें जुटी रहीं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। कई जगह स्वजन भी अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं।
-नीरज कुमार, उपायुक्त लाहुल-स्पीति

ब्रह्मगंगा नाले में बहे मां-बेटे, कैंपिंग साइट मैनेजर व पनविद्युत प्रोजेक्ट कर्मी की तलाश की जा रही है। 20 पुलिसकर्मी व स्थानीय लोग सर्च अभियान में लगे हुए हैं। गुरुवार को किसी का कोई सुराग नहीं लग पाया।
-आशुतोष गर्ग, उपायुक्त कुल्लू

## उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में भीषण तूफानों की तीव्रता में वृद्धि की प्रवृत्ति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में भीषण तूफानों की तीव्रता में बीते चार दशक में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। यह जानकारी भारतीय विज्ञानियों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में सामने आई है। यह अध्ययन 'क्लाइमेट डायनेमिक्स' नाम के जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन कहता है कि इस बढ़ती प्रवृत्ति के लिए ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका का संकेत मिलता है। आइआइटी खड़गपुर के महासागर इंजीनियरिंग विभाग एवं नेवल आर्किटेक्चर के जिया अल्बर्ट, अथिरा कृष्णन और प्रसाद भास्करन समेत अन्य विज्ञानियों की टीम ने वेल्लोर में वीआइटी विश्वविद्यालय में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के केएस सिंह के साथ मिलकर यह अध्ययन किया है। इसमें उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिविधि पर बड़े स्तर पर पर्यावरणीय प्रवाह में अहम वायुमंडलीय मापदंडों और अल नीनो-सदर्न ऑसलेशन (ईएनएसओ) की भूमिका और प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

इस अध्ययन में उनका जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत आने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने सहयोग किया है। मानसून से पूर्व के मौसम के दौरान बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। हाल के दशकों (सन 2000 से) यह प्रवृत्ति बंगाल की खाड़ी और अरब सागर बेसिन, दोनों स्थानों पर अधिक पाई गई है। अध्ययन के मुताबिक, क्षोभमंडल में जल वाष्प का हिस्सा बढ़ा है।

## नहीं मिली बेटी की कोई निशानी, बेसुध होकर गिरी मां

जासं, कुल्लू : हिमाचल के ब्रह्मगंगा नाले में बादल फटने से आई बाढ़ की चपेट में आने से बही कैंपिंग साइट मैनेजर विनिता चौधरी के स्वजन गाजियाबाद से यह उम्मीद लेकर चले थे कि कुल्लू पहुंचते ही कोई सुखद सूचना मिलेगी। मगर बेटी का सुराग लगना तो दूर मां को जब उसकी कोई निशानी तक नहीं मिली तो वह बेसुध होकर गिर गई। पथराई आंखों से स्वजन बेटी की तलाश में कई घंटे तक ब्रह्मगंगा नाले की खाक छानते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। स्वजन ने कैंपिंग साइट का चप्पा-चप्पा छाना लेकिन पत्थर व मलबे के सिवाय वहां कुछ नहीं था। उन्होंने विनिता के सहयोगी अर्जुन से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी।

# भगत सिंह नाटक का रिहर्सल कर रहे बच्चे की फंदा लगने से मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं

**दुखद**

- फंदे पर छपटपटता रहा मासूम, नादान साथियों को लगा अभिनय कर रहा
- चंद मिनट में चली गई जान, खेत पर मजदूरी करने गए थे माता-पिता

स्कूल नहीं गया मगर, 10 वर्ष के शिवम को बलिदानी भगत सिंह के बारे में खूब पता था। स्वजन से सुनी क्रांतिकारियों की कहानियों को जीवंत अभिनय में उतारने के लिए वह गुरुवार को दोस्तों की टोली में शामिल हो गया। बलिदानी भगत सिंह नाटक का रिहर्सल करते हुए फंदे पर लटकने का अभिनय करना था मगर, क्रूर काल को कुछ और ही मंजूर था। वह सांकेतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में फंदे पर झूल गया। छटपटाया, सामने खड़े साथियों को हाथ से इशारा भी किया मगर, वे नादान समझ नहीं सके। चंद मिनट में शिवम की जान चली गई।

बदायूं जिले में कुंवरगांव के गांव बावट निवासी भूरे और आरती खेतों में मजदूरी करते हैं। परिवार का माहौल कहें या आर्थिक दुश्वारी, वे एकलौते बेटे शिवम को स्कूल नहीं भेज सके थे। ज्यादातर वक्त वह नानी के घर में रहता था। पिछले महीने वह माता-पिता के पास आया, उसके बाद नानी के यहां नहीं गया था।

**दोस्तों से कहा, मैं बनूंगा भगत सिंह:** गुरुवार को मां, पिता खेत पर काम करने गए थे। दोपहर करीब दो बजे शिवम के छह दोस्त उसके घर पहुंचे। बताया कि 15 अगस्त को नाटक मंचन होता है। इसका रिहर्सल करते हैं। शिवम भी नाटक मंचन में साथ हो गया। बोला, भगत सिंह मैं ही बनूंगा।

**इंकलाब के नारे लगे और फंदे पर झूल गया:** साथी बच्चों ने बताया कि वे सब नाटक मंचन करते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इतने में शिवम घर में रखी रस्सी तलाश लाया। एक सिरा दरवाजे पर बांधा, दूसरे का फंदा बना लिया। इसके बाद उसने भी नारा लगाया और फंदा अपने गले में फंसा लिया। उसे नीचे रखे स्टूल पर ही पैर रखने थे मगर, अचानक वह हाथ-पैर इधर-उधर फेंकने लगा इससे स्टूल छिटककर दूर जा गिरा। उस समय लगा कि वह अभिनय कर रहा।

**पांच मिनट में चली गई जान:** स्टूल छिटकने से गले में फंदा फंसा और पांच मिनट बाद उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अन्य बच्चों ने कोई हलचल होती नहीं देखी तो चीखते हुए वहां से भागे। लोग लोग पहुंचे तो फंदे से शव लटका हुआ था।

**बेटा उठो, नाटक खत्म हो गया**

बेटे का शव देखकर आरती बेसुध हो गई। कहती रहीं कि बेटा उठो, नाटक खत्म हो गया। बाद में बच्चे को गांव के बाहर दफना दिया गया। पुलिस को सूचना नहीं दी गई। ग्राम प्रधान भीमसेन सागर ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, इसी में हादसा हो गया। एसओ रवि करन का कहना है कि थाने में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। हादसे के बारे में मालूम कराएंगे।

## असम और मिजोरम सीमा पर हुई केंद्रीय बलों की तैनाती

**विवाद**

- सीमा के विवादित इलाके में सामान्य लोगों के जाने पर पाबंदी, प्रशासन ने कहा, हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम-मिजोरम सीमा पर इस सप्ताह की शुरुआत में हिंसा और सात लोगों की मौत के बाद गुरुवार को स्थिति शांत और नियंत्रण में रही। लैलापुर में अंतरराज्यीय सीमा पर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया, जबकि राज्य पुलिस के जवान अपनी-अपनी सीमाओं के 100 मीटर अंदर रहे। इस विवाद में असम पुलिस के छह जवानों समेत कुल सात लोगों की जान जा चुकी है।

कछार के जिला अधिकारी ने कहा कि लोगों को सीमा की ओर जाने की अनुमति नहीं है, इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि यह वर्तमान में संघर्ष क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़कने के बाद से कुछ स्थानों पर कुछ संगठनों द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी का प्रभाव आंशिक रहा है। बराक घाटी के तीन जिलों में रहने वाले छात्रों और मिजो लोगों के लिए भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

असम जातीय परिषद पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सिलचर का दौरा करेगा और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेगा। इस बीच कछार के प्रभारी मंत्री अशोक सिंघल और पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने बुधवार रात सिलचर मेडिकल कालेज और अस्पताल में घायलों का दौरा किया और 35 घायल पुलिस वालों और दो नागरिकों को एक लाख रुपये का चेक और फलों का बाक्स सौंपा। उल्लेखनीय है सोमवार को हमले में पांच पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी ने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

## गुजरात में 'काला हिरण' का वीडियो देख मोदी ने कहा, सर्वोत्तम

भावनगर, प्रेट्र : गुजरात के भावनगर जिले में काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान के पास सैकड़ों 'काला हिरण' के सड़क पार करते समय का वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हुआ है। इस वीडियो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है।

विभाग ने ट्वीट किया, 'भावनगर के काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान में 3000 से ज्यादा काला हिरणों को सड़क पार करते देखा जा सकता है।' विभाग द्वारा साझा किए गए एक मिनट के वीडियो पर प्रधानमंत्री ने 'सर्वोत्तम' लिख कर टिप्पणी की है। राष्ट्रीय उद्यान के रेंज वन अधिकारी अंकुर पटेल के अनुसार, काला हिरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। धोलेरा-भावनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस चेक पोस्ट में तैनात ग्राम रक्षक दल जवान द्वारा कुछ दिनों पहले वीडियो शूट किया गया था। वीडियो में जो सड़क दिख रही है वह वेलावदार गांव और राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है।

# आंतरिक मूल्यांकन नीति को सीबीएसई ने सही ठहराया

**हाई कोर्ट से**

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अपनी आंतरिक मूल्यांकन नीति को सही ठहराया है। कोरोना के कारण परीक्षा रद होने पर सीबीएसई ने यह नीति अपनाई है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सीबीएसई ने कहा कि 10वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति भी 12वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति के आधार पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संतुष्टि जाहिर की है। लिहाजा इसके खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने बताया कि तकनीक व उच्च शिक्षा के विशेषज्ञों ने मूल्यांकन नीति को तैयार किया है। पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं हो। संबंधित स्कूल अपने छात्रों को वास्तविक योग्यता के आधार पर अंक दें। बोर्ड ने नीति में संशोधन की मांग को आधारहीन बताते हुए कहा कि इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

## 12वीं की परीक्षा संबंधी फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा को लेकर अपने 22 जून के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कोरोना महामारी के बीच आफलाइन परीक्षा लेने के लिए सीबीएसई की मूल्यांकन योजना में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था।

याचिका में उस योजना की समीक्षा का आग्रह किया गया था, जिसके तहत इस साल 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा पुनर्विचार याचिका 22 जून, 2021 के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई है। हमारी राय है कि पुनर्विचार का कोई मामला ही नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने 22 जून को 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफेट एग्जामिनेशन द्वारा अपनाई गई आकलन योजना में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था।

### सीबीएसई की वेबसाइट पर मिलेगी रोल नंबर की जानकारी

सीबीएसई के 10वीं-12वीं के छात्रों को रोल नंबर से संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि परीक्षाएं नहीं होने के कारण बोर्ड ने छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया था, जिससे छात्रों को आवंटित रोल नंबर की जानकारी नहीं है। लेकिन, परिणाम देखने के लिए रोल नंबर जरूरी है। छात्र इस लिंक https//cbseit.in/cbse/www/rfinder/landing.aspx पर जाकर रोल नंबर खोज सकते हैं। लिंक में अपना रोल नंबर खोजने के लिए छात्रों ने स्कूलों को लिस्ट आफ कैंडिडेट में जो जानकारी उपलब्ध कराई थी, उन्हें भरनी होगी। छात्रों का परिणाम डिजी लाकर में जारी किया जाएगा।

**बदलाव की बयार**

# कभी तनाव झेल चुका कश्मीर का डाउन-टाउन अब मुस्कुरा रहा

मुसैब सोफी का वीडियो आधारित रैप 'वन मिनट अप एंड वन मिनट डाउन, बेबी दिस इज डाउन-टाउन' मचा रहा धूम, वीडियों में डाउन-टाउन की दुश्वारियों को चुटेले अंदाज में पेश किया गया

नवीन नवाज, श्रीनगर

डाउन-टाउन, शहर-ए-खास, कभी पत्थरबाजी और राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों के चलते सुर्खियों में रहने वाला यह इलाका एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कुछ और है। अब डाउन-टाउन के लोग हंस रहे हैं और खुलकर ठहाके लगा रहे हैं। दरअसल, डाउन-टाउन में ही पले-बढ़े 28 वर्षीय मुसैब सोफी का वीडियो पर आधारित रैप 'वन मिनट अप एंड वन मिनट डाउन, बेबी दिस इज डाउन-टाउन' खूब धूम मचा रहा है। इसकी पहली दो लाइन अंग्रेजी में हैं, बाकी कश्मीरी भाषा में है। डाउन-टउान की तंग गलियों में शूट इस वीडियो में मुसैब ने इलाके की दुश्वारियों को चुटीले अंदाज में उकेरा है। इसमें बताया गया है कि डाउन-टाउन में अस्पताल तो है पर एंबुलेंस नहीं। गाड़ियां तो खूब हैं पर पेट्रोल पंप नहीं। गलियां तंग हैं और घर साथ-साथ सटे, लेकिन फायर स्टेशन नहीं। रास्ते हैं पर सड़कें टूटीं। पर्यटक स्थल हैं पर सैलानी नहीं।

मुसैब सोफी ने यह वीडियो अपने दो चचेरे भाइयों शुजान और शरजील के साथ मिलकर तैयार किया है। शरजील ग्रेजुएशन कर रहा है और शुजान 12वीं का छात्र है। वीडियो में अशाल भी है, जो पेशे से आटो रिक्शा चालक है। इसी वीडियो की वजह से वह श्रीनगर में एक सेलिब्रिटी बना हुआ है। अशाल की कदकाठी, लंबे बाल और उसका बातचीत करने का अंदाज सभी को भा रहा है।

मुसैब का पूरा वीडियो अभी चार अगस्त को म्यूजिक एप स्पोटिफाई पर रिलीज होना है, लेकिन इस वीडियो को चार दिन में ही यू-ट्यूब पर 2.6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। फेसबुक पर भी 2.03 लाख लोगों ने यह वीडियो देखा और सराहाने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।

**कैंसर रोगी ने मेरे वीडियो का सराहा :** मुसैब ने गीत गुनगुनाया और कहा कि इस गाने ने मुझे नयी पहचान दी है। इससे पहले यहां लोग मुझे कामेडियन ही समझते थे, क्योंकि मैं लोगों को हंसाने, गुदगुदाने वाले वीडियो तैयार कर उन्हें यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था। मुझे अपने इन वीडियो के लिए कई लोगों की सराहना मिली है।

**घरवाले चाहते थे मैं वकील बनूं :** मुसैब ने कहा कि मेरा पुश्तैनी मकान नवाकदल में ही है। मैं डाउन टाउन में ही पला-बढ़ा हूं। गांधी कालेज से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर इग्नू से एमकाम किया। मेरे पिता व्यापारी हैं और बहन वकील। घर वाले चाहते थे कि मैं भी वकील बनूं, वह मेरे शोक से नाराज थे। शुरू में उन्होंने मेरा काफी विरोध किया। मैंने इसे जारी रखा और पिता के साथ काम में हाथ भी बंटाया। एक दिन मैंने पापा से कहा कि आप यहां की जिंदगी को अच्छी तरह समझते हैं, यहां अगर किसी के चेहरे पर मेरे कारण हंसी आएगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को दिल खोलकर हंसाऊं, इसलिए कुछ और कश्मीरी गीत व सीरियल तैयार करूंगा।



वीडियो पर आधारित रैप बनाने वाले श्रीनगर के मुसैब सोफी (मध्य) तथा उनके चचेरे भाई शरजील और शुजान। सौजन्य : मुसैब

'कश्मीर में जो हालात रहे हैं, उसने हम लोगों के पास मुस्कराने, हंसने की वजहों को छीन लिया है। सभी किसी न किसी तनाव और अवसाद का शिकार रहे हैं। इसलिए मैंने यह वीडियो रैप तैयार किया।'
-मुसैब सोफी

# बिहार में कटिहार के मेयर की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, कटिहार

- बाइक सवार तीन हमलावरों ने की वारदात, घात लगाकर सीने में तीन गोलियां मारीं

बिहार में कटिहार के महापौर (मेयर) शिवराज पासवान उर्फ शिवा पासवान को हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में संतोषी चौक रेलवे गेट के समीप गुरुवार रात की है। गंभीर रूप से जख्मी शिवा को स्वजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेयर रहे विजय सिंह के बरारी से विधायक निर्वाचित होने के बाद शिवराज पासवान 23 मार्च को मेयर निर्वाचित हुए थे।

**पंचायत कर बाइक से लौट रहे थे घर :** गुरुवार की देर शाम एक मामले में पंचायत कर मेयर शिवराज पासवान बाइक से घर लौट रहे थे। रेलवे गेट के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। उनके सीने में तीन गोलियां लगीं। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। अपराधियों की संख्या तीन बताई जा रही है।

**जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार से भी जुड़े थे :** सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता, मेयर जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार से भी जुड़े थे। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर शव को थाना परिसर में ही अभी रखा गया है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। शहीद चौक पर मेयर के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई थी। समर्थक अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

## टीका लगने के बाद भी संक्रमित होने का गणित



कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद से ही यह माना जा रहा था कि टीके की दोनों डोज के बाद संक्रमित होने का खतरा नहीं रहता है। हालांकि दुनियाभर में बढ़ते मामलों और ज्यादा संक्रामक डेल्टा वैरिएंट की चिंताओं के बीच कई रिपोर्टों में सामने आया है कि दोनों डोज के बाद भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। टीके की दव डोज लेने के 14 दिन बाद जांच में संक्रमण का पता लगने को ब्रेकथ्रू इंफेक्शन कहा जाता है। अमेरिका की वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के स्टाफ साइंटिस्ट संजय मिश्रा ने इस संबंध में कई सवालों के जवाब दिए हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि कोरोना के टीके कारगर हैं और संक्रमण के लक्षणों से बहुत हद तक बचाते हैं।

**86%** कारगर हैं टीके डेल्टा के कारण अस्पताल में भर्ती होने से बचाने के मामले में

**90%** से ज्यादा कारगर पाया गया है गंभीर लक्षणों से बचाने में

### बहुत आम नहीं है ब्रेकथ्रू इंफेक्शन

ब्रेकथ्रू संक्रमण के मामले पहले के अनुमानों से ज्यादा तो आ रहे हैं, लेकिन कुल की तुलना में ऐसे मामले बहुत कम हैं। साथ ही टीका लगवा चुके लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं रहता है या बहुत हल्के लक्षण दिखते हैं। अमेरिका के 46 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, पहली जनवरी से 30 अप्रैल के बीच टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों में 10,262 संक्रमण के मामले आए। इसी अवधि में कुल मामले 1.18 करोड़ थे।

### टीके का असर

**35%** असर पाया गया है टीके की एक डोज का डेल्टा पर

**79%** प्रभावी पाए गए हैं टीके डेल्टा वैरिएंट पर

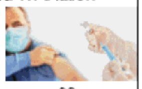
**89%** कारगर थे एमआरएनए टीके अल्फा वैरिएंट पर

### हालत गंभीर होने से बचाता है टीका

अमेरिका के सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, ब्रेकथ्रू के 27 फीसद मामले ऐसे थे, जिनमें संबंधित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं था। 10 फीसद को अस्पताल जाना पड़ा, जिनमें से कुछ के भर्ती होने का कारण कोरोना नहीं था और दो फीसद लोगों की जान गई। 2020 में जब टीकाकरण शुरू नहीं हुआ था, छह फीसद से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई थी। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक, फाइजर के टीके की एक डोज के बाद ही संक्रमित व्यक्ति में अन्य की तुलना में कम वायरस पाए जाते हैं।

### कुछ लोगों में खतरा ज्यादा

सीडीसी के आंकड़ों मुताबिक, ब्रेकथ्रू इंफेक्शन में 63 फीसद महिलाएं पाई गई हैं। कुछ अन्य अध्ययन भी बताते हैं कि महिलाओं में इसकी आशंका ज्यादा रहती है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। इसके अलावा, बड़ी उम्र के लोगों में अपेक्षाकृत टीके का असर कुछ कम रहता है। यही कारण है कि ब्रेकथ्रू इंफेक्शन के 75 फीसद मामले 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में पाए गए। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी या फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे लोगों में भी खतरा ज्यादा रहता है।



### टीके ने बचाई कई जिंदगियां

अमेरिका में 16.3 करोड़ लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। 65 साल से ज्यादा उम्र के करीब 90 फीसद को कम से कम एक डोज लग चुकी है। एक आकलन के आधार पर टीकाकरण के दम पर वहां जून के आखिर तक 2,79,000 लोगों की जान बची और 12.5 लाख लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। मई में अमेरिका में 18 हजार से ज्यादा जानें गई, जिनमें से दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या मात्र 150 थी। इंग्लैंड में टीके के कारण 30,300 लोगों की जान बचने का अनुमान है।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

# केरल में लगातार तीसरे दिन 22 हजार मामले

**बढ़ी चिंता** ▶ 24 घंटों में देश में 43 हजार से अधिक नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,28,114 हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में गुरुवार को कोरोना के 43,509 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,28,114 हो गई। इन नए मरीजों में 22 हजार से अधिक मामले अकेले केरल में दर्ज किए गए हैं। यानी नए मामलों में पचास फीसद से अधिक मामले अकेले इसी राज्य के हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब केरल में 22 हजार से अधिक मामले देखे गए।

जानकारी के अनुसार केरल में गुरुवार को कोरोना के 22,064 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 128 मौतें भी हुईं। बुधवार को राज्य में 22,056 और मंगलवार को 22,129 मामले दर्ज किए गए थे। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने गुरुवार को कहा पिछले 24 घंटों में 1,63,098 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस दौरान राज्य में पाजिटिविटी दर 13.53 फीसद रही। विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में केरल संक्रमण के मामलों में शीर्ष पर रहेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 640 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,22,662 हो गई।

## राज्यों को 47.48 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई

नई दिल्ली, एएनआइ

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 47.48 करोड़ से अधिक कोरोनारोधी वैक्सीन की डोज प्रदान की गईं। इसके अलावा राज्यों को जल्द ही 53,05,260 डोज और मुहैया करा दी जाएंगी। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य ने दी। सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, 47,48,77,490 डोज में से अपव्यय सहित कुल 44,74,97,240 डोज का उपयोग हो चुका है। इस तरह राज्यों के पास 2,88,55,050 डोज उपलब्ध हैं।

**22 जुलाई तक वैक्सीन के 6.4 करोड़ डोज विदेश भेजे : सरकार :** सरकार ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि भारत ने 12 जनवरी से 22 जुलाई के बीच कोरोनारोधी टीकों की करीब 6.4 करोड़ खुराक दूसरे देशों को भेजी हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 12 जनवरी से 22 जुलाई के बीच 42.2 करोड़ डोज तैयार की गईं। इनमें से तकरीबन 35.8 करोड़ डोज घरेलू हवाईअड्डों के जरिये भेजी गईं जबकि 6.4 करोड़ खुराक विदेश भेजी गईं।



तमाम आशंकाओं और अफवाहों के बीच लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। हैदराबाद में गुरुवार को म्यूनिसिपल ग्राउंड में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। एपी

**गुरुवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति**

| | |
|---|---|
| नए मामले | 43,509 |
| कुल मामले | 3,15,28,114 |
| सक्रिय मामले | 4,03,840 |
| मौतें (24 घंटे में) | 640 |
| कुल मौतें | 4,22,662 |

**सुबह आठ बजे तक के आंकड़े**

| | |
|---|---|
| ठीक होने की दर | 97.38 फीसद |
| मृत्यु दर | 1.34 फीसद |
| पाजिटिविटी दर | 2.52 फीसद |
| सा. पाजिटिविटी दर | 2.38 फीसद |
| जांचें (बुध) | 17,28,795 |
| कुल जांचें (बुध) | 46,26,29,773 |

**गुरुवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके**

| | |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 6.17 लाख |
| उत्तर प्रदेश | 4.15 लाख |
| राजस्थान | 4.01 लाख |
| महाराष्ट्र | 3.53 लाख |
| बंगाल | 2.11 लाख |
| हरियाणा | 1.48 लाख |
| बिहार | 1.01 लाख |
| पंजाब | 1.03 लाख |
| जम्मू-कश्मीर | 0.58 लाख |
| दिल्ली | 0.72 लाख |
| झारखंड | 1.13 लाख |
| हिमाचल | 0.29 लाख |
| छत्तीसगढ़ | 0.95 लाख |
| उत्तराखंड | 0.86 लाख |

(कोविन प्लेटफार्म के आंकड़े)

## कोरोना की 'आर-वैल्यू' में क्रमिक वृद्धि

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाले 'आर-फैक्टर' में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है और इस संदर्भ में केरल तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के शीर्ष स्थान पर रहने से महामारी के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंता बढ़ रही है।

चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के विश्लेषण में कहा गया है कि देश के दो महानगरों, पुणे और दिल्ली में आरवैल्यू एक के करीब है। विश्लेषण के मुताबिक, जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब देश में संपूर्ण आर-वैल्यू नौ मार्च से 21 अप्रैल के बीच 1.37 रहने का अनुमान था। यह 24 अप्रैल और एक मई के बीच घट कर 1.18 रह गई और फिर 29 अप्रैल से सात मई के बीच 1.1 पर आ गई। आर-वैल्यू 0.95 होने का यह मतलब है कि प्रत्येक 100 संक्रमित व्यक्ति औसतन 95 अन्य लोगों को संक्रमित करेंगे। यदि आर-वैल्यू एक से कम है तो, इसका मतलब यह होगा कि नये संक्रमित लोगों की संख्या इससे पूर्व की अवधि में संक्रमित हुए लोगों की संख्या से कम होगी, जिसका मतलब है कि रोग के मामले घट रहे हैं।

आर-वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी तेजी से रोग घटेगा। इसके उलट, यदि आर वैल्यू एक से अधिक होगा तो हर चरण में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी--तकनीकी रूप से, इसे महामारी का चरण कहा जाता है।

## बच्चों के लिए वायल में नहीं, सीरिंज में आएगी वैक्सीन डोज

दीपेंद्र प्रताप सिंह, बरेली

कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण मध्य सितंबर से शुरू होने की पूरी संभावना है। इसके लिए विशेष प्रकार की प्रीफिल्ड सीरिंज (पीएफएस) का उपयोग किया जाएगा। पीएफएस में वैक्सीन की डोज लोड रहने से केवल पैकिंग खोलकर वैक्सीन लगाई जा सकेगी।

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बच्चों पर सभी ट्रायल हो चुके हैं। वैक्सीन साइंस के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा.अतुल अग्रवाल बच्चों को लगाने के लिए तैयार की गई कोवैक्सीन की डोज पीएफएस प्रारूप में होने ये ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसमें वैक्सीन तय मात्रा में होने से ज्यादा सुरक्षित होती है। हर वायल में 0.5 मिलीलीटर वैक्सीन की मात्रा होगी। अभी 15 सितंबर से बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की संभावना है,। इसकी आधिकारिक घोषणा 15 अगस्त को हो सकती है।

**बच्चों को भी लगेंगी दो ही डोज : डा.अतुल** अग्रवाल के अनुसार बच्चों को वयस्कों की तरह दो डोज ही लगाई जाएंगी। दोनों में वैक्सीन की बराबर मात्रा रहेगी।

बच्चों के लिए भी 28 से 42 दिन के बीच दूसरी डोज का प्रविधान रहेगा। हालांकि 27 दिन के बाद जल्द ही लगवा लेना बेहतर रहेगा। छह से 12 वर्ष के आयु वर्ग में कोवैक्सीन बाजू या फिर जांघ पर कहां लगे, इसके लिए जल्द ही नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप (एनटैगी) फैसला लेगा।

**प्रीफिल्ड सीरिंज के लाभ**

- वैक्सीन के लिए 10 बच्चों के एक साथ आने का इंतजार नहीं करना होगा।
- वयस्कों की वैक्सीन में 10 लोगों के न होने पर वेस्टेज होती थी, जो बचेगी।
- सीरिंज के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कम लोगों की आवश्यकता होगी।
- हर बच्चे को कंप्यूटराइज्ड माप से 0.50एमएलकीसमानडोजलगेगी।

## उत्तर प्रदेश में कम पड़ने लगी वैक्सीन, मायूस होकर वापस लौट रहे लोग

**उत्साह पर फिरा पानी**

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

यूपी में एक ओर जहां फिर से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं तो वहीं टीका लगवाने के लिए कतार में लगे लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन मांग के अनुसार टीके पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। जुलाई में तीन करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य तय था, जबकि सिर्फ 1.55 करोड़ वैक्सीन ही लग पाईं। गुरुवार को भी 16 लाख वैक्सीन जिलों में भेजी गईं। फिर भी टीके कम पड़ रहे हैं।

निजी अस्पताल टीकाकरण में बेरुखी दिखा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त टीका लग रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में शुल्क लिया जा रहा है, जिससे वहां कम लोग जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 3652 टीकाकरण केंद्रों में से सिर्फ 63 केंद्र निजी अस्पतालों में हैं। राज्य को दिए जाने वाले कुल टीके की 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बीते जून माह के अंतिम सप्ताह से देने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह इस महीने 48 लाख वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए आवंटित की गईं, लेकिन ये अस्पताल मात्र आठ लाख वैक्सीन ही लगा पाए। 40 लाख वैक्सीन वापस हो जाएंगी। दरअसल प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड लगाने के लिए 780 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पूतनिक के लिए 1145 रुपये प्रति डोज शुल्क लिया जा रहा है।

**युवाओं में जबरदस्त उत्साह:** टीका लगवाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं में है। मात्र दो महीने में ही 18 से 44 वर्ष की उम्र के 2.14 करोड़ लोगों ने टीके लगवाए हैं। 45 से 60 वर्ष की आयु के 1.53 करोड़ और 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुवार को 4.21 लाख टीके ही लगाए जा सके। अब 16 लाख वैक्सीन भेजी गई हैं, इससे कुछ रफ्तार बढ़ेगी।

**राष्ट्रीय फलक**

## बैंकों की बड़ी लापरवाही उजागर, 17 साल से बुजुर्गों के निधन पर वसूलते रहे पेनाल्टी

राजीव सक्सेना, कानपुर

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में बुजुर्गों के निधन पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, इस आदेश को बैंकों ने अपने साफ्टवेयर पर 17 साल अपडेट ही नहीं किया। अब कोरोना के दौरान जब बहुत अधिक संख्या में वरिष्ठ नागरिकों का निधन हुआ और इस योजना से जुड़े बुजुर्गों के नामिनी को कटौती कर धनराशि जारी की गई तो शिकायतें भारतीय बैंक संघ तक पहुंचीं। इस पर हैरान हुए संघ ने सभी बैंकों को 2004 के संशोधन की याद दिलाई।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। इस समय इसमें ब्याज दर 7.4 फीसद है, जो सामान्य एफडी के ब्याज दर से ज्यादा है। इसलिए सेवानिवृत लोग इस खाते में एक बार में पैसा लगा देते हैं। इस योजना में बैंक और डाकघर दोनों के जरिये शामिल हुआ जा सकता है। योजना की शुरुआत में मृत्यु होने पर किए जाने वाले भुगतान से कटौती के निर्देश थे। वर्ष 2004 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि मृत्यु की दशा में कोई पेनाल्टी नहीं काटी जाएगी, लेकिन बैंकों ने साफ्टवेयर अपडेट नहीं किया और कटौती होती रही। कोरोना काल में काफी वरिष्ठ नागरिक भी काल कवलित हुए। उनके नामिनी से भुगतान के दौरान कटौती की गई, तो लोगों ने अलग-अलग स्तर से अपनी शिकायतें ऊपर तक भेजीं। भारतीय बैंक संघ तक यह शिकायत पहुंची, तो उसने पाया कि 2004 का जो संशोधन लागू किया था, बैंकों ने अपने साफ्टवेयर में उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की। बैंक संघ ने अब 22 जुलाई को सभी बैंकों को तुरंत अपने साफ्टवेयर में बदलाव करने और पेनाल्टी न काटने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये राहत भरा कदम है। 17 वर्ष से बैंक इसमें संशोधन नहीं कर रहे थे। इस संशोधन से नामिनी को मिलने वाले धन में कटौती नहीं होगी।
– सुरेश चंद्र, खाताधारक

जब 2004 से ये संशोधन लागू किया गया था तो इस बीच जितने लोगों की कटौती की गई है, उनके नामिनी को उस कटौती का धन लौटाया जाए।
– आशीष कुमार मिश्रा, महामंत्री, वी बैंकर्स

अभी तक बैंक ये कटौती कर रहे हैं। अब भारतीय बैंक संघ के आदेश पर इस कटौती को बंद किया जाएगा।
– एके वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक

### देश के 14 टाइगर रिजर्व को मिली कैट्स की मान्यता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को देश के 51 टाइगर रिजर्व में से 14 को बेहतर संरक्षण और रखरखाव के लिए कैट्स (कंजरवेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड) की मान्यता दी है। बाघों के संरक्षण से जुड़ा यह एक विश्वस्तरीय प्रमाणीकरण है जिसका निर्धारण बाघों के बेहतर प्रबंधन से जुड़े उच्च मानकों पर किया जाता है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को इसे जारी करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि देश के सभी 51 टाइगर रिजर्व को कैट्स की यह मान्यता मिले। दुनिया के कुछ ही देशों को यह मान्यता मिली है। इनमें नेपाल, भूटान और रूस के अलावा भारत के भंडार मानस, काजीरंगा और ओरंग (असम), सुंदरवन (बंगाल), पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच (मप्र), वाल्मीकि (बिहार), दुधवा (उप्र), अन्नामलाई और मुदुमलाई (तमिलनाडु); परम्बिकुलम (केरल) और बांदीपुर (कर्नाटक) शामिल हैं।

## हाई कोर्ट से कहा जांच में असहयोग के कारण कुंद्रा को किया गिरफ्तार

▶ पोर्न फिल्म मामले में कोर्ट ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को अग्रिम जमानत देने से किया इन्कार

मुंबई, प्रेट्र : पुलिस ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि पोर्न फिल्म निर्माण व वितरण मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। उधर, मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संदर्भ में दाखिल शपथपत्र में पुलिस ने तर्क दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 (ए) को मामले में तत्काल लागू कर दिया गया था। यह धारा पोर्न सामग्री के निर्माण या प्रकाशन से संबंधित है।

जस्टिस एएस गडकरी के समक्ष सुनवाई के दौरान कुंद्रा के वकील अबद पोंडा ने कहा कि पुलिस जब नोटिस जारी करती है तो कम से कम दो हफ्ते का नोटिस देती है, लेकिन उनके मुवक्किल को दो घंटे का भी वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, '19 जुलाई को कुंद्रा के दफ्तर की तलाशी ली गई। तीन घंटे तक चली तलाशी के दौरान कुंद्रा वहीं मौजूद थे और जांच में सहयोग कर रहे थे। शाम में उन्हें थाने चलने को कहा गया और वहां गिरफ्तार कर लिया गया।' हालांकि, पुलिस ने शपथपत्र में कहा है कि जब कुंद्रा के दफ्तर की तलाशी ली जा रही थी, तब कारोबारी व कंपनी के आइटी टेक्नीशियन रयान थोर्पे वाट्सएप ग्रुप से संदेशों को डिलीट कर रहे थे। आरोपित साक्ष्यों से आगे छेड़छाड़ न कर पाएं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को कुंद्रा के अंधेरी स्थित वियान व जेएल स्ट्रीम दफ्तर में एक गुप्त अलमारी मिली है।

### चिटफंड घोटाले के आरोपी निर्मल सिंह भंगू को झटका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हजारों करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले के आरोपी निर्मल सिंह भंगू ने छत्तीसगढ़ की विशेष अदालत द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए जेल अथारिटी और स्थानीय अस्पताल पर कड़ी टिप्पणी की हैं। निर्मल सिंह भंगू ने अपने खराब स्वस्थ का हवाला देकर प्रोडक्शन वारंट के आदेशों को रद करने की मांग की थी।

### बहू के खिलाफ 'ओछी' अर्जी देने वाली सास पर जुर्माना

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने अरवल्ली जिला निवासी रसीला खराड़ी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पारिवारिक विवाद में इस महिला ने अपनी बहू को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह कहते हुए सुनवाई से इन्कार कर दिया कि समझौते का दबाव बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है।

### अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र सुलझेगा तिब्बत का मुद्दा : तेंजिन लेक्ष्य

जासं, धर्मशाला : निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रवक्ता तेंजिन लेक्ष्य ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत का मुद्दा शीघ्र सुलझेगा। उन्होंने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की वार्ता को सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि निर्वासित तिब्बती सरकार इस बैठक का स्वागत करती है।

बकौल तेंजिन लेक्ष्य, इस बैठक से चीन को भी कड़ा संदेश जाएगा। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि विभिन्न मंचों से तिब्बत मसले के समाधान के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री व अमेरिकी विदेशी मंत्री के बीच हुई वार्ता से तिब्बत की आजादी के लिए नई उम्मीद दिखी है। उनके अनुसार स्वायत्तता का मामला शीघ्र सुलझेगा। उन्होंने तर्क दिया कि मामला उठता रहा है, लेकिन अब ब्लिंकन ने भारत दौरे के दौरान लाई लामा के प्रतिनिधियों से बातचीत की है।

## रेल मंत्री बोले, कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का हो रहा समाधान

▶ आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन में कर्मचारियों के योगदान की सराहना

▶ यूनियन का आरोप, सुविधाओं में हो रही कटौती, निजीकरण के खिलाफ होगा आंदोलन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के विकास में रेल कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

अश्विनी वैष्णव आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के वार्षिक अधिवेशन को आनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों की मांगों व उनकी समस्याओं को लेकर रेल प्रशासन फेडरेशन के पदाधिकारियों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। कई समस्याओं का समाधान किया गया है।

एआइआरएफ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी की आड़ में कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। उन्होंने रेल यूनियन का चुनाव शीघ्र कराने की मांग की। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यकारी अध्यक्ष जेआर भोसले ने कहा कि रेलवे के निजीकरण के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रेलवे कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कोरोना योद्धा की संज्ञा तो दी गई, लेकिन उनकी सुविधाओं में कटौती की जा रही है।



वादों की रेल : अश्विनी वैष्णव। फाइल फोटो

सामाजिक कार्यकर्ता डा. रंजना कुमारी ने रेलवे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेलवे में सिर्फ सात फीसद महिला कर्मचारी हैं। इनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल सहित फेडरेशन के कई नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित किया। कोरोना के कारण आनलाइन तीन दिवसीय अधिवेशन किया जा रहा है।

## कैदी को सजा अवधि और रिहाई से संबंधित सूचना मिलनी चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : जेल में बंद कैदियों को अपनी सजा की अवधि, रिहाई और अवधि पूर्व रिहाई के अधिकार के संबंध में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्हें पैरोल और फरलो के अधिकार के संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही है।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में बंद कैदियों की सजा अवधि के संबंध में पोर्टल बनाने के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा। पीठ ने कहा कि वह मामले में दिल्ली सरकार की दलील से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने कैदियों के संबंध में जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने को उचित नहीं माना था। कहा था कि इससे कैदियों की निजता के अधिकार का हनन होगा। जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा, इस सूचना को सार्वजनिक करने से निजता का उल्लंघन होने का तर्क समझ से परे है। हमारा मानना है कि यह सूचना जनसामान्य की जानकारी में भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 साल से जेल में है तो उसे पैरोल और फरलो से अपनी रिहाई के बारे में जानकारी होने का भी हक है। अगर उसके बारे में जनता भी जान जाए तो किसी को क्या कठिनाई हो सकती है ? पीठ ने यह बात दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता जयंत सूद से कही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए मुकेश कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट के 2007 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में सजा से संबंधित सूचना सार्वजनिक होने पर आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि दिल्ली की जेलों में ई-कियोस्क की सुविधा दी गई है। इन कियोस्क में जाकर कैदी अपने संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 30 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
# बिजनेस
7
www.jagran.com

### ग्रीन हाइड्रोजन को परिवहन ईंधन बनाने पर विचार

नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को परिवहन ईंधन बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर ही छूट देने की उम्मीद जताई। हाइड्रोजन और गैस आधारित वाहन पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत में विशाल सौर, पवन, पनबिजली उत्पादन क्षमता है। इन क्षमताओं के साथ देश हरित हाइड्रोजन उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। (प्रेट्र)

मोबाइल फोन पर शेयरों की खरीद-फरोख्त सुविधा से शेयर बाजारों में नई पीढ़ी के निवेशकों की संख्या काफी बढ़ी है। इससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
- आशीषकुमार चौहान, चेयरमैन, बीएसई



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स 52,653.07 ▲ 209.36 | निफ्टी 15,778.45 ▲ 69.05 | सोना प्रति दस ग्राम ₹46,992 ▲ ₹382 | चांदी प्रति किलोग्राम ₹66,274 ▲ ₹1,280 | डॉलर ₹74.29 ▼ ₹0.09 | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 74.19 |

# तत्व चिंतन के निवेशक हुए मालामाल

## 113 फीसद से अधिक उछाल दर्ज किया गया सूचीबद्धता के दिन ही शेयरों में

**2,310.25** रुपये के स्तर पर बंद हुए शेयर गुरुवार को बीएसई पर

**1,083** रुपये इश्यू प्राइस रखी गई थी कंपनी के शेयरों की

**5,120.68** करोड़ रुपये हो गया कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहले ही दिन

**78.60** लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई एनएसई पर पहले दिन



नई दिल्ली, प्रेट्र: स्पेशलिटी केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी तत्व चिंतन के निवेशक शेयर बाजारों में इसकी सूचीबद्धता के दिन ही मालामाल हो गए। कंपनी ने 1,083 रुपये की इश्यू प्राइस पर शेयरों को सूचीबद्ध कराया था। लेकिन गुरुवार को सूचीबद्धता के दिन ही कंपनी के शेयर 113.31 फीसद मजबूती के साथ 2,310.25 रुपये के स्तर पर बंद हुए। बीएसई में कंपनी के शेयर 94.99 फीसद प्रीमियम के साथ 2,111.80 पर खुले और इंट्रा-डे में 129.57 फीसद उछलकर 2,486.30 रुपये के स्तर तक उछले।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में भी निवेशकों ने तत्व चिंतन के शेयरों को हाथोंहाथ लिया। एक्सचेंज में कंपनी के शेयर 95 फीसद प्रीमियम के साथ 2,111.85 रुपये पर खुले। कारोबार के आखिर में एनएसई पर कंपनी के शेयर 112.67 फीसद उछाल के साथ 2,303.30 रुपये पर बंद हुए। शेयरों में इस जबर्दस्त उछाल के चलते गुरुवार को कारोबार के आखिर में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5,120.60 करोड़ पर जा पहुंचा। पहले दिन बीएसई पर कंपनी के 8.99 लाख और एनएसई पर 76.60 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई। गुजरात-स्थित यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स का निर्माण करती है। कंपनी के उत्पाद अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका व ब्रिटेन समेत 25 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं।

**शेयर बाजारों की गिरावट थमी:** इस बीच, लगातार तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद गुरुवार को शेयर बाजारों में थोड़ी रौनक लौटी। मेटल और आइटी कंपनियों में अच्छी खरीदारी के दम पर बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 209.36 अंक यानी 0.40 फीसद मजबूती के साथ 52,653.07 पर बंद हुआ। एनएसई का 50-शेयरों वाला निफ्टी 69.05 यानी 0.44 फीसद उछाल के साथ 15,778.45 पर स्थिर हुआ। सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक 6.87 फीसद का उछाल टाटा स्टील के शेयरों में दर्ज किया गया।

### विंडलास बायोटेक का आइपीओ चार अगस्त को खुलेगा



नई दिल्ली, प्रेट्र : फार्मास्युटिकल्स फार्मुलेशंस निर्माता कंपनी विंडलास बायोटेक ने प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) के लिए 448-460 रुपये का प्राइस बैंड निर्धारित किया है। तीन दिनों का यह आइपीओ चार अगस्त को खुलेगा और छह अगस्त को बंद होगा। आइपीओ के तहत कंपनी 165 करोड़ रुपये मूल्य के ताजा शेयर जारी करेगी। इसके साथ ही आफर फार सेल (ओएफएस) के माध्यम से 5,142,067 शेयरों की बिक्री करेगी। आइपीओ के आधे शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआइबी) के लिए आरक्षित हैं।

### चार महीनों में ही एनएसई पर 50 लाख से अधिक नए निवेशक

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 50 लाख से अधिक नए निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। एनएसई के अनुसार पहली अप्रैल से 25 जुलाई तक 31.3 लाख नए निवेशक पंजीकरण करा चुके हैं। वर्ष 2019 की अप्रैल-जुलाई अवधि में 8.5 लाख और वर्ष 2020 की इसी अवधि में 20 लाख नए निवेशकों ने पंजीकरण कराया था।

# बकाया बिल के बदले एनबीएफसी से कर्ज ले सकेंगी छोटी कंपनियां



संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में बोलतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण • प्रेट्र

**फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पारित, एमएसएमई का नकदी संकट दूर होने में मिलेगी मदद: वित्त मंत्री**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एमएसएमई अब अपने खरीदार के बकाया बिल के आधार पर लगभग 9,000 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कर्ज ले सकेंगे। अभी एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां सिर्फ सात बैंकों से इस प्रकार का कर्ज ले सकती हैं। फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल के संसद के दोनों सदनों से पारित होने से एमएसएमई को यह सुविधा मिलेगी। इसी सप्ताह लोकसभा से पारित इस विधेयक को राज्यसभा ने भी गुरुवार को पारित कर दिया।

गुरुवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक पारित होने से एमएसएमई का नकदी संकट एक हद तक दूर होगा और कंपनियां आसानी से परिचालन पूंजी जुटा सकेंगी।

फैक्टरिंग कानून में यह प्रविधान है कि अगर एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां किसी ग्राहक को अपना सामान उधार में बेचती हैं तो उस उधार के बिल के आधार पर वे एनबीएफसी से कर्ज ले सकेंगी। उसके बाद कर्जदाता संस्थान उस ग्राहक से बकाया वसूली करेगा। इस सुविधा को व्यापक रूप देने के लिए सरकार फैक्टरिंग बिल में संशोधन करना चाह रही थी, ताकि सभी एनबीएफसी एमएसएमई को उनके बकाया बिल के आधार पर कर्ज दे सके।

इस विधेयक के कानून का रूप ले लेने के बाद घरेलू निर्माताओं और निर्यातकों को परिचालन पूंजी की कमी नहीं रहेगी। वहीं, कर्ज देने के लिए तैयार 9,000 एनबीएफसी की आपसी स्पर्धा के चलते कंपनियों को कर्ज पर ब्याज भी कम देना पड़ेगा। एमएसएमई की नकदी की समस्या को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यूके सिन्हा कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने फैक्टरिंग कानून, 2011 में संशोधन की सिफारिश की थी। भारत में एमएसएमई की कुल उधारी में फैक्टरिंग उधारी की हिस्सेदारी मात्र 2.6 फीसद है। चीन में फैक्टरिंग प्रणाली के तहत 11.2 फीसद कर्ज एमएसएमई को दिए जाते हैं।

# अगले वित्त वर्ष में सात फीसद तक विकास दर का अनुमान : सीईए



मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमणियन • जागरण आर्काइव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमणियन ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष (2022-23) में भारत की विकास दर 6.5-7 फीसद और उसके अगले वर्ष आठ फीसद तक जा सकती है। उन्होंने कहा, निवेश दर के उच्च होने, निर्यात में वृद्धि एवं निजी क्षेत्रों की अधिक उत्पादकता से यह दशक निश्चित रूप से भारत की उच्च विकास दर का दशक होगा। बढ़ती महंगाई के बारे में सीईए ने कहा, इस माह की महंगाई दर छह फीसद से नीचे आ सकती है। मई के बाद से दर छह फीसद से ऊपर चल रही है।

उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में सीईए ने कहा, पूंजीगत खर्च से अनौपचारिक सेक्टर में मांग का सृजन होता है और यह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ समय से सरकार ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए हैं वे वर्ष 1991 में किए गए सुधारों की तरह महत्वपूर्ण हैं। सुब्रमणियन ने कहा, दूसरी लहर छह से आठ सप्ताह में खत्म हो गई। इस वजह से विकास पर इसका पिछले वर्ष जितना असर नहीं होगा। जीएसटी संग्रह से भी पता चल रहा है कि खपत में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि जीएसटी संग्रह खपत से जुड़ा हुआ कर है। पिछले वर्ष सितंबर से जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से अधिक था।

### जीएसटी दरें जल्द होंगी युक्तिसंगत : सुब्रमणियन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना सरकार के एजेंडे में शामिल है। उनके अनुसार जीएसटी दरों के मौजूदा ढांचे में जल्द बदलाव होना निश्चित है। उनके अनुसार मूल योजना तीन दरों वाले ढांचे की थी और यह काफी महत्वपूर्ण है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक आयात शुल्क की व्यवस्था को भी ठीक करने की जरूरत है। जुलाई, 2017 से अस्तित्व में आई जीएसटी व्यवस्था में पांच टैक्स स्लैब 0.25 फीसद, पांच फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद हैं। हालांकि उद्योग संगठन एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं ने जिस सोच के साथ पांच दरों के प्रारूप में इसे लागू किया था, वह बहुत अच्छा है।

### भारत में खूब बढ़ी सोने की मांग

मुंबई, प्रेट्र : इस वर्ष दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) के दौरान देश में सोने की मांग 19.2 फीसद बढ़ी है। इसी अवधि में दुनियाभर में सोने की मांग पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले लगभग सपाट रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में 76.1 टन सोने की मांग रही, जो बीते वर्ष समान अवधि में 63.8 टन रही थी।

डब्ल्यूजीसी ने कहा, मूल्य के हिसाब से इस वर्ष अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में 23% बढ़ोतरी के साथ 32,810 करोड़ मूल्य के सोने की मांग रही। पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 26,600 करोड़ रहा था। ठीक पिछली तिमाही के मुकाबले अप्रैल-जून में सोने की मांग 46% घट गई। वहीं, चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही (जनवरी-जून, 2021) में देश में सोने की मांग 157.6 टन रही, जो वर्ष 2019 की इसी अवधि के मुकाबले 46 फीसद और वर्ष 2015-2019 की पहली छमाहियों के औसत से 39 फीसद कम है।

# देसी प्रजाति के चावल के निर्यात में बढ़ोतरी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

**प्रोत्साहन**
- जेनेटिक सुधार से काला नमक हुआ बौना, बढ़ी उत्पादकता
- घरेलू बाजार के साथ सुगंधित चावलों की बढ़ी निर्यात मांग
- संरक्षण में किसानों और स्थानीय समुदायों की भूमिका अहम



कुल 26 सामुदायिक सीड बैंक स्थापित किए गए हैं • फाइल फोटो

चावल की देसी प्रजातियों की घरेलू व निर्यात मांग बढ़ने से इनकी खेती को प्रोत्साहन मिलने लगा है। संरक्षित चावल की कई प्रजातियों की उत्पादकता बढ़ाने को इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के तहत कई संस्थानों में अनुसंधान हो रहा है। जेनेटिक सुधार के माध्यम से देसी चावल की गुणवत्ता व सुगंध बनाए रखने के साथ उत्पादकता में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। इसी टेक्नोलाजी के माध्यम से पूर्वी उप्र का काला नमक का पौधा बौना हो गया है और पैदावार बढ़ गई है। देसी प्रजातियों के संरक्षण में किसानों और स्थानीय समुदायों की भूमिका अहम है।

आइसीएआर के दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स (एनबीपीजीआर) में 45,107 देसी प्रजाति के चावलों को संरक्षित किया गया है, जिन्हें समय-समय पर रिसर्च के उद्देश्य से जारी किया जाता है। संरक्षित प्रजातियों में 4,000 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण परंपरागत किसानों ने कर रखा है। इनमें पोषण व गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर और सुंगधित प्रजातियों की उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिली है। कुल 26 सामुदायिक सीड बैंक स्थापित किए गए हैं। किसानों ने चावल की कुल 1645 ऐसी प्रजातियां संरक्षित की है, जिन्हें जीआइ टैग प्राप्त हो चुका है।

इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइएआरआइ) के निदेशक व चावल के प्रमुख विज्ञानी डा. एके सिंह का कहना है, देसी प्रजाति वाले चावलों की निर्यात मांग संभावनाएं बढ़ी हैं। पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय चावलों की मांग है। खाद्य उत्पादों की निर्यात एजेंसी एपीडा ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिया है। सिंह ने बताया, विभिन्न राज्यों में चावल की 150 प्रजातियां चिन्हित की गई है, जिन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआइ) टैग भी मिल चुका है। ऐसी प्रजातियों को विकसित करने की दिशा में शोध का कार्य चल रहा है।

उप्र में काला नमक, आदम चीनी व जीरा बत्तीस जैसी प्रजातियां हैं, जिनमें काला नमक को बौनी प्रजाति में तब्दील कर दिया गया है। उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। जेनेटिक सुधार से पैदावार बढ़ाने की कोशिश कामयाब हो रही है। ओडिशा का काला जीरा, बंगाल का गोविंदभोग व रंधुनी पागल और बिहार के कतरनी को जीआइ टैग मिल चुका है। वहीं, महाराष्ट्र की अंबे मोहर, छत्तीसगढ़ की तिलक चंदन, केरल की जीरकशाला, गंधकशाला, आंध्र प्रदेश के चित्तमुती आत्म, जम्मू-कश्मीर के मुश्क-बुद्जी और मणिपुर की चखाव पैराडान प्रजाति की गुणवत्ता को देखते हुए उसे व्यावसायिक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है।

अग्रणी देसी प्रजाति वाले इन चावलों को संरक्षित करने वाले किसानों और समुदायों को हर साल 10 लाख तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। फिलहाल देश के 10 हजार से अधिक किसानों के खेतों पर इस तरह की प्रजाति वाले चावल (धान) की खेती की जा रही है। स्थानीय स्तर पर इन प्रजातियों को प्रोत्साहित करने में राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय, जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका अहम है। इन प्रजातियों के बीजों को संरक्षित करने के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

## राष्ट्रीय फलक

### न्यूज गैलरी

#### ईडी ने रोज वैली की संपत्ति के कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिटफंड कंपनी रोज वैली की संपत्ति के कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी के अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कोर्ट ने रोज वैली की संपत्ति को बेचकर ग्राहकों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। (राब्यू)

#### एनआइए करेगी अलकायदा के आतंकियों की जांच

लखनऊ : अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद के आतंकियों की उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश की आगे की कड़ियां अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) खंगालेगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने लखनऊ से पकड़े गए अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल के आतंकियों के केस को अपने हाथ में ले लिया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) अब तक की छानबीन से जुड़े सभी दस्तावेज व केस डायरी एनआइए के सिपुर्द करेगा। आइजी एटीएस जीके गोस्वामी ने आतंकियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की जांच एनआइए को सौंपे जाने की पुष्टि की है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश में आतंकियों के पकड़े जाने की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी थी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के मामले में पकड़े गए बांग्लादेश व म्यांमार के तीन नागरिकों के विरुद्ध दर्ज केस की जांच भी एनआइए अपने हाथ में ले सकती है। एटीएस ने गत 11 जुलाई को अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद के सक्रिय सदस्य मिनहाज अहमद व मसीरुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दावा किया था कि दोनों 15 अगस्त से पहले लखनऊ, कानपुर व अन्य बड़े शहरों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बम धमाकों की साजिश रच रहे थे।। (राब्यू)

#### भारत-नेपाल सीमा के पास दो विदेशी नागरिक पकड़े गए

पौआखाली (किशनगंज) : भारत-नेपाल सीमा से सटे सुखानी थानाक्षेत्र के मौजीडांगी के पास 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने बुधवार को दो विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। एक के पास चीन, नेपाल और ब्रिटेन की नागरिकता के दस्तावेज मिले। (संसू)

# प्रेमी के साथ जाने पर बहन की गला काटकर हत्या

**बदायूं में आनर किलिंग**

- प्रेमी के साथ बयान दर्ज कराने दातागंज कोतवाली पहुंची थी छात्रा
- बहाने से कोतवाली से बुलाकर ले गए दो भाई और गला रेत दिया

जागरण संवाददाता, बदायूं

26 जुलाई को बिल्सी के परौली में आनर किलिंग लोग भूले नहीं थे, बुधवार रात को इससे भी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। फास्ट पुलिसिंग, कानून व्यवस्था को रौंदते हुए दो भाइयों ने कोतवाली में बैठी बहन को बहाने से बुलाया और गेट पर ले जाकर हत्या कर दी। छात्रा का गुनाह सिर्फ इतना था कि तीन माह पूर्व वह प्रेमी के साथ चली गई। वारदात में छात्रा के पिता भी शामिल थे, सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पलिया गुजर गांव के जुड़वा भाई चंद्रपाल और कुंवरपाल ने एक ही महिला से शादी की है। उनकी बड़ी बेटी अर्चना बीए की छात्रा थी। रिश्ते के तहेरे भाई देवेंद्र उर्फ हैपी से उसके प्रेम संबंध थे। तीन महीने पहले दोनों घर छोड़कर चले गए और आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद बरेली के सुभाषनगर की बीडीए कालोनी में रहने लगे थे। दूसरी ओर छात्रा के भाई रवित ने देवेंद्र सिंह और उसके दो भाइयों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था, इसलिए पुलिस तलाश में लगी थी। दबाव बनता देख बुधवार रात करीब 10 बजे देवेंद्र व अर्चना बयान दर्ज कराने दातागंज कोतवाली पहुंचे। देवेंद्र के अनुसार, भनक लगी तो छात्रा के स्वजन भी पहुंच गए। कोतवाली में दोनों पक्षों में समझौते की बात की जाने लगी।

**बातों में उलझाकर कोतवाली के बाहर लाया और मार डाला** : रवित व पुष्पेंद्र को समझौते की बात नागवार गुजर रही थी। वे दोनों बात करने के बहाने अर्चना को कोतवाली गेट तक लेकर आए। उसे बातों में उलझाया और अर्चना का गला रेत दिया।

### अमानवीय : कर्नाटक में शरारती तत्वों ने 30 बंदरों को मार डाला

हासन, आइएएनएस : केरल के मलप्पुरम में करीब दो साल पहले गर्भवती हथिनी को पटाखा खिलाने की घटना शायद ही कोई भूला होगा। कर्नाटक के हासन जिले में एक ऐसी ही अमानवीय वारदात हुई है। शरारती तत्वों ने गुरुवार की भोर में 30 बंदरों की हत्या कर दी। 20 घायल अवस्था में पाए गए।

वारदात बेलुर तालुका के चोवदानहल्ली गांव की है। शरारती तत्वों ने बोरों (बारदाना) में भरकर बंदरों को गांव के बाहरी इलाके में फेंक दिया था। स्थानीय युवाओं ने सुबह बोरों को खोला तो स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि बोरों में बंद करने के बाद बंदरों को पीटा गया है। कुछ बंदर हांफ रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी पिलाया और खाना खिलाया। इसके बाद 18 बंदर जंगल की ओर चले गए। दो का पशु चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि बंदरों को दूसरी जगह भेजने की योजना होगी। ऐसा करने से विफल रहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पोस्टमार्टम में जहर देने की बात सामने आई है।

### खजाने की तलाश में 1200 साल पुराने मंदिर की खोदाई

सुरेंद्रनगर, प्रेट्र : छिपे हुए खजाने की काल्पनिक खबरों पर विश्वास करते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित 1200 साल पुराने शिव मंदिर के गर्भ गृह को खोद डाला। प्राचीन मंदिर में बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं। यह मंदिर संरक्षित स्मारक है और जीर्ण हालत में है।

पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोरों ने परिसर में खजाना छिपे होने की फैलाई गई काल्पनिक खबरों पर भरोसा कर यह कदम उठाया होगा। स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में दो जगह गड्ढा देखने के बाद गुरुवार को पुलिस को सूचना दी। अधिकारी ने कहा कि जामवाड़ी गांव के समीप स्थित मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। चोरों ने शिवलिंग हटाने के बाद पहले एक फीट गहरा गड्ढा खोदा। शिवलिंग को दीवार के पास रख दिया गया था। चोरों ने बाहर स्थित नंदी की प्रतिमा भी हटा दी और चार फीट गहरा का गड्ढा खोदा।

# बस व ट्रक के चालक और मालिक सहित टोलकर्मियों पर मुकदमा

संवादसूत्र, बाराबंकी

अयोध्या हाईवे पर 27 जुलाई की रात रामसनेहीघाट में हुए भीषण हादसे के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव की तहरीर पर बस व ट्रक के चालक व मालिक सहित टोलकर्मियों को शामिल किया गया है।

तहरीर में लिखा गया है कि बस का एक्सल मंगलवार की शाम करीब सात बजे टूटा था और साढ़े चार घंटे तक टोल प्लाजा की ओर से पेट्रोलिंग नहीं की गई। अज्ञात टोल कर्मियों और दोनों वाहन के स्वामियों व चालकों के खिलाफ लापरवाही, खतरनाक ड्राइविंग, लोगों की जान को खतरे में डालना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन और महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा कराया है। एआरटीओ ने बताया कि एटी कोठुआ सारंगपुर, थाना दरौंधा जिला सिवान, बिहार के बस स्वामी बस स्वामी राजेश कुमार व कंचन गली हरी फाटक, इंदौर के ट्रक स्वामी मो. आदिल खिजली हैं। इससे पहले 28 जुलाई को घायल हुए बिहार के यात्री फगुनी साहनी ने बस, ट्रक के चालकों और ट्रेवल्स एजेंसी के खिलाफ मुकदमा कराया था। अब पुलिस के सामने इन आरोपितों को चिह्नित करने और गिरफ्तारी की चुनौती है।

> दोनों मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसमें एनएचएआइ की लापरवाही सामने आई है। एनएचएआइ को पेट्रोलिंग करना चाहिए था और रूट डायवर्ट भी। घटना स्थल पर रिफ्लेक्शन लगाकर घेराबंदी करना चाहिए था। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक की रिपोर्ट ली जा रही है।
> -यमुना प्रसाद, एसपी

## खेल जागरण

# श्रीलंका ने 2-1 से जीती टी-20 सीरीज

## अंतिम मैच में भारत सात विकेट से हारा, हसरंगा ने लिए चार विकेट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली



विकेट लेने के बाद खुश हसरंगा। एएफपी

भारत के हाथों वनडे सीरीज में हारने वाली मेजबान श्रीलंका की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए गुरुवार को तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। गुरुवार को 24 साल के हुए लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हुए तीसरे व अंतिम टी-20 मैच में नौ रन देकर चार विकेट झटके, जो कि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। उनके इस प्रदर्शन के आगे भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर सिर्फ 81 रन ही बना सकी। जवाब में श्रीलंका ने 14.3 ओवर में तीन विकेट पर 82 रन बनाकर सात विकेट से मैच जीत लिया। श्रीलंका की ओर से धनंजय डिसिल्वा ने 20 गेंदों पर दो चौकों की मदद से सर्वाधिक नाबाद 23 रन बनाए।

भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, वह अपने फैसले को ही सही साबित नहीं कर सके और अपनी पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना ही दुष्मंता चमीरा को विकेट दे बैठे। इसके साथ ही भारतीय विकेटों के गिरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मानों बल्लेबाजों ने विकेट पर टिकना सीखा ही नहीं हो। वो तो भला हो कुलदीप यादव (नाबाद 23) व भुवनेश्वर कुमार (16) का जिन्होंने निचले क्रम में उपयोगी पारियां खेलकर भारत को उसके न्यूनतम स्कोर पर सिमटने से बचा लिया। हसरंगा ने संजू सैमसन (0) और रुतुराज गायकवाड़ (14) को एक ही ओवर में आउट करने के अलावा भुवनेश्वर और वरुण चक्रवर्ती (0) के भी विकेट झटके। जवाब में श्रीलंकाई टीम किसी भी समय दवाब में नहीं दिखी। अविष्का फर्नांडो (12) और मिनोद भानुका (18) ने 23 रन जोड़कर श्रीलंका को सधी शुरुआत दिलाई। हालांकि, लेग स्पिनर राहुल चाहर (3/15) ने उसे लगातार अंतराल पर झटके दिए, लेकिन अन्य भारतीय गेंदबाज कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। वानिंदु हसरंगा ने बल्ले से भी योगदान देते हुए नाबाद 14 रन बनाए और डिसिल्वा के साथ चौथे विकेट की अटूट साझेदारी में 26 रन जोड़े।

### दीक्षा को ओलिंपिक में जगह मिली

टोक्यो, प्रेट्र : दीक्षा डागर को पांच अगस्त से शुरू हो रही टोक्यो ओलिंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है, जिससे भारतीय चुनौती मजबूत होगी। पिछले महीने जब अंतिम सूची तैयार की गई थी तो दीक्षा रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थीं। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ ने भारतीय गोल्फ यूनियन (आइजीयू) के जरिये दीक्षा के ओलिंपिक में जगह मिलने की सूचना दी।

अदिति अशोक ओलिंपिक में खेलने के लिए कट हासिल कर चुकी हैं। महिला गोल्फ स्पर्धा में अब भारत की दो खिलाड़ी होंगी। बायें हाथ की खिलाड़ी दीक्षा पहली बार ओलिंपिक में हिस्सा लेंगी, जबकि अदिति दूसरी बार खेलों के महाकुंभ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दीक्षा को सुनने में दिक्कत है और वह 2017 में बधिर ओलिंपिक और अब ओलिंपिक में हिस्सा लेने का गौरव हासिल करेंगी। वह बधिर ओलिंपिक में रजत पदक जीतने में सफल रही थीं। दक्षिण अफ्रीका की पाला रेटो ने टोक्यो खेलों से हटने का फैसला किया और आस्ट्रिया की गोल्फर सारा शोबर को बदलने के आग्रह को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद दीक्षा को प्रतियोगिता में जगह मिली।

# बेलिंडा और मार्केटा के पास इतिहास रचने का मौका

**ओलिंपिक डायरी**

टोक्यो, एपी: स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनकिक शनिवार को टोक्यो ओलिंपिक में टेनिस की महिला सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा से भिड़ेंगी। बेलिंडा ने सेमीफाइनल में कजाखस्तान की एलिना रायब्किना को 7-6 (7-2), 4-6, 6-3 से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मार्केटा ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-3,6-1 से हराया। स्विट्जरलैंड को 1992 ओलिंपिक के बाद टेनिस में स्वर्ण पदक नहीं मिला है। तब मार्क रासेट ने बार्सिलोना ओलिंपिक में पुरुष सिंगल्स स्पर्धा का स्वर्ण स्विट्जरलैंड को जिताया था। अब बेलिंडा के पास स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने का मौका है। वहीं, 42वीं रैंक वाली मार्केटा अगर स्वर्ण पदक जीतती हैं तो वह सबसे निचली रैंक के साथ ओलिंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी होंगी।

**डबल्स में भी बेलिंडा रच सकती हैं इतिहास** : बेलिंडा महिला डबल्स सेमीफाइनल में विक्टोरिजा गोलूबिक के साथ ब्राजील की लौरा पिगोसी और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी के खिलाफ भी खेलेंगी। अगर बेलिंडा फाइनल में पहुंच गईं तो ओलिंपिक के एक ही संस्करण में दो फाइनल में पहुंचने वाली पांचवीं खिलाड़ी बन जाएंगी। उनसे पहले सेरेना व वीनस विलियम्स और एंडी मरे व निकोलस मसू यह कारनामा कर चुके हैं।

**ली को स्वर्ण पदक जीतते हुए घर से देख रही थीं बाइल्स** : ओलिंपिक से अचानक मानसिक बीमारी के चलते अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने जिम्नास्ट की हर स्पर्धा से नाम वापस ले लिया। उनकी साथी खिलाड़ी सुनिसा ली ने आलराउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया।

**टेबल टेनिस में 33 साल से चीन का स्वर्ण पर कब्जा बरकरार** : चीन की चेन मेंग ने अपनी हमवतन सुन यिंगशा को 4-2 से हराकर महिला सिंगल्स ओलिंपिक टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता।

**सबसे कम आबादी के साथ पदक जीतने वाला देश बना सैन मैरिनो:** निशानेबाजी ट्रैप स्पर्धा में सैन मैरिनो की एलिसांद्रा पिरेली ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। अब सैन मैरिनो ओलिंपिक में सबसे कम आबादी के साथ पदक जीतने वाला देश बन गया है।

दैनिक जागरण

नियंत्रित मन ही जीवन को सही दिशा दे सकता है

# तीसरी लहर का अंदेशा

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। हालांकि वहां के हालात से चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है, लेकिन कहना कठिन है कि राज्य सरकार उसके सुझावों के हिसाब से जरूरी कदम उठाती है या नहीं? वैसे संक्रमण के मामलों में यकायक तेजी आते देख केरल सरकार दो दिनों के लिए संपूर्ण लाकडाउन लगाने जा रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से संक्रमण थम जाएगा। यह साफ है कि संक्रमण के मामले में केरल इसीलिए मुश्किलों से घिर गया है, क्योंकि उसने बकरीद के अवसर पर लाकडाउन में तीन दिनों के लिए छूट दे दी। यह छूट यह जानते हुए भी दी गई कि इससे संक्रमण बेलगाम हो सकता है। चूंकि केरल सरकार पर वोट बैंक को संतुष्ट करने का भूत सवार था, इसलिए उसने उन आपत्तियों पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से व्यक्त की गई थीं। एक गड़बड़ी यह भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मामले का संज्ञान लेने और फैसला देने में देर कर दी। उसकी आपत्ति तब सामने आई, जब बकरीद पर दुकानें खोलने और खरीदारी करने की छूट का आखिरी दिन था।

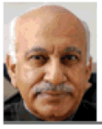
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर नाराज होते हुए कहा था कि यदि संक्रमण बढ़ा तो वह कार्रवाई करेगा। सवाल है कि क्या वह ऐसा करेगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, केरल सरकार को यह आभास होना चाहिए कि उसने अपने गैर जरूरी फैसले से राज्य की जनता को तो खतरे में डाला ही, देश में तीसरी लहर की आशंका को उभारने का भी काम किया। केरल में जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यह अंदेशा गहरा गया है कि तीसरी लहर की शुरुआत वहीं से हो सकती है। अंदेशा इसलिए भी गहरा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं देश के कुछ अन्य हिस्सों में संक्रमण घटने की दर थमती दिख रही है। इससे यह सवाल उभर आया है कि कहीं संक्रमण की तीसरी लहर सिर तो नहीं उठा रही है? बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यही मानकर चलें कि तीसरी लहर सिर उठाने ही वाली है और उसे रोकने के लिए हरसंभव जतन करें। निःसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास तभी प्रभावी साबित होंगे, जब आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तत्पर होगी। जनता को यह समझना ही होगा कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड जैसी खतरनाक महामारी केवल सरकारी प्रयासों से थमने वाली नहीं है।

# आपदा से सबक कब

प्रकृति से छेड़छाड़ के सबक हमें कई रूप में मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पहाड़ों पर अवैध निर्माण, अवैध कटान और अवैध खनन भी आपदाओं का अहम कारण है। इससे पहाड़ों की बनावट तो प्रभावित हो रही है, पहाड़ खोखले भी हो रहे हैं। यही कारण है कि हर मौसम में जानमाल का नुकसान सहना पड़ रहा है। हर हादसे के बाद आपदा प्रबंधन की बातें होती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, धरातल पर पहुंचने से पहले ही फिर हादसा हो जाता है। पहाड़ों पर हर साल हादसे हो रहे हैं, लेकिन इनसे कोई सबक नहीं लिया जाता है। यह सही है प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, लेकिन पूर्व आपदा प्रबंधन से इनसे होने वाले नुकसान को अवश्य कम किया जा सकता है। बरसात में नदी नाले उफान पर होते हैं, बादल फटने जैसी घटनाएं भी होती हैं। नदी-नालों के किनारे रह रहे लोगों को समय रहते हटाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 13 जून के बाद बरसात के कारण हुए हादसों में 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कांगड़ा जिले के रुलेहड़ व किन्नौर जिले के बटसेरी के हादसे के जख्म भरे भी नहीं थे कि बुधवार को लाहुल-स्पीति व कुल्लू जिले में बादल फटने व बाढ़ की चपेट में आने से 16 लोग बह गए। इनमें दो को बचा लिया गया है। सात लोगों के शव मिल गए हैं जबकि सात लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। किन्नौर के बटसेरी में पहाड़ दरकने से नौ पर्यटक दब गए थे और कांगड़ा के रुलेहड़ में 10 लोगों की मौत हो गई थी। फिर वही सवाल है कि नदी नालों के किनारे लोगों को बसने क्यों दिया जाता है? अगर इस पर पहले ही ध्यान दिया जाए तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। पहाड़ों पर किसी तरह के निर्माण से पूर्व भूविज्ञानियों की सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। नदियों व नालों के किनारे व पहाड़ों की ढलानों पर किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यदि सभी पहलुओं को देखकर नियोजित तरीके से निर्माण किया जाए तो हादसों की आशंका कम रहती है।

**हिमाचल प्रदेश में प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ का परिणाम आपदा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं तो नुकसान कम किया जा सकता है**

# भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता



एमजे अकबर

**हमारे लोकतंत्र का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष चुनावी परिणाम को लेकर कभी पूरी तरह आश्वस्त होने का जोखिम नहीं ले सकते और वास्तव में यही होना भी चाहिए**

इस साल की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर मुझे कुछ दिन पहले एक अखबार में बतौर विज्ञापन दिखी। उस विज्ञापन में उल्लेख था कि भारत के 56 प्रतिशत उत्पाद देश के मात्र 16 प्रतिशत लोग ही उपभोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की 84 प्रतिशत आबादी केवल 44 प्रतिशत उत्पाद खरीद पाती है। इसका सार यह है कि यह 84 प्रतिशत आबादी अपनी रकम मूल रूप से बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च करती है, न कि उन उत्पादों पर जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले होते हैं। यह गरीबी और विषमता की उतनी ही सटीक तस्वीर दिखाता है, जितनी कि आंकड़े आपको दिखाएंगे। हमारी राष्ट्रीय संपदा का पलड़ा पूरी तरह देश की 20 प्रतिशत आबादी के पक्ष में झुका हुआ है। यह वही आबादी है जो पहली या दूसरी दुनिया में रहती है। शेष आबादी चौथी दुनिया में रहने को अभिशप्त है। आधुनिक मशीनों के फायदे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्वतंत्रता के सात से अधिक दशकों के बाद हमारे देश की यही कड़वी हकीकत है।

हमने 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ संरक्षित भी किया। इसके बावजूद किसी भी प्रकार की आर्थिक समानता हासिल करने में हमें अभी कई दशक और लग जाएंगे। इसमें यह समकालीन तथ्य भी जोड़ लिया जाए कि कोविड महामारी के कारण हुई हालिया आर्थिक उथल-पुथल ने लाखों लोगों के रोजगार पर ग्रहण लगा दिया है। इससे हाल-फिलहाल का परिदृश्य बहुत बदरंग दिख रहा है।

लोकतंत्र में आर्थिक बदहाली का सीधा संबंध हमेशा राजनीतिक भविष्य से जुड़ा होता है। प्रत्येक चुनाव का गणित अलग होता है। यहां तक आप जिन कारणों के दम पर दोबारा चुनाव जीतकर आते हैं, वे भी पहले चुनाव के मुकाबले बदल जाते हैं। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो चुनाव आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जबकि पुनः चुनाव जीतकर आना सरकार के प्रदर्शन पर एक प्रकार की मुहर। इससे जुड़ा विश्लेषण भी उसी के इर्दगिर्द होता है। चुनावी जीत का अंतर निर्धारित करने वाले निर्वाचन अखाड़ों यानी निर्वाचकों की जमीन हमेशा बदलती रही है। यह कलाइडोस्कोप की तरह है। थोड़ी सी हलचल के साथ ही रुझान बदल जाता है। मतदाता समूहों को जाति और धर्म के पुराने चश्मे से देखने का हमारे राजनीतिक वर्ग का पारंपरिक नजरिया उनकी सबसे बड़ी असफलता है। निःसंदेह इन पहलुओं में सामाजिक तथ्य समाहित होते हैं, लेकिन वे पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। उन पर गहन मंथन आवश्यक है।

लोकतंत्र की गतिशीलता इसी में निहित होती है कि गैर-विशिष्ट पहचान वाले मतदाताओं की स्थिति में पिछले चुनाव के मुकाबले वर्तमान में कितना बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जातिगत समीकरणों की महत्ता जगजाहिर है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने माकूल समीकरणों को बैठाने की जुगत भिड़ाने में लगे भी रहते हैं। इस बीच कम से कम दो नए निर्वाचक सामने उभरे हैं। ये आर्थिक धारणाओं से प्रेरित होते हैं और इस कारण पारंपरिक पैमानों को तोड़ते हैं। चूंकि इनमें से एक वर्ग खेतिहर किसानों का है तो इसका गहराई की तुलना में जनसांख्यिकीय विस्तार से अधिक वास्ता है। ग्रामीण विमर्श को प्रभावित करने में वे माहिर हैं। यहां तक कि उन समुदायों में भी उनकी गहरी पैठ है, जो भले ही उनके आर्थिक हितों को साझा न करते हों। ऐसे कई साक्ष्य मिल रहे हैं कि कृषि कानून विरोधी मुहिम ने कई अन्य कारकों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा तो बना दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि के लिए कोई सटीक डाटा उपलब्ध नहीं। अगर है भी तो कम से कम वह मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि मतदाताओं के मन की थाह लेने वाले जरूर उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले और आगामी विधानसभा चुनावों के बीच परिदृश्य में कुछ परिवर्तन की आहट को महसूस कर रहे हैं।



अवधेश राजपूत

विशिष्ट पहचान से इतर एक वर्ग के रूप में कोविड से प्रभावित लोग हैं। इसमें विस्तार और गहराई दोनों है, क्योंकि कोई भी महामारी वर्ग, धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होती है। जैसा कि किसी भी आपदा में होता है कि ग्रामीण गरीब उससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं। वे गुमनाम मौत के शिकार होते हैं। यहां तक कि उनकी अंतिम क्रिया के लिए भी संसाधन नहीं मिलते। दुख की स्मृतियां दिल पर लगे दाग के रूप में अंकित हो जाती हैं। ये दाग भले ही हमेशा नमूदार न हों, लेकिन उन्हें मिटाना भी आसान नहीं होता। वे बहुत ही गहरे होते हैं।

भारतीय मतदाता नासमझ नहीं हैं। वे किसी बेलगाम महामारी के लिए सरकार को दोष नहीं देते। कोविड के कहर के बावजूद बंगाल, केरल और असम की सरकारें दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आ गईं। वे संकट के समय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकारी हस्तक्षेप की गुणवत्ता और आर्थिक परिणामों के आधार पर शासन के स्तर यानी गवर्नेंस को आंकते हैं। अगर उन्हें महसूस होता है कि सरकारों ने हरसंभव बेहतरीन प्रयास कर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो वे सकारात्मकता दिखाएंगे। इसके विपरीत यदि उन्हें यह लगे कि सरकारी रवैया पक्षपातपूर्ण और अक्षम रहा तो वे अपना आक्रोश भी जताएंगे। महामारी ने लोगों की जान से ज्यादा उनकी आजीविका पर प्रहार किया और यह चोट भी उन लोगों पर अधिक गहरी हुई, जो पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर या नाजुक थे।

भारतीय मतदाताओं ने अपने आक्रोश को मतदान के दिन तक सहेजकर रखना सीख लिया है, क्योंकि वे अभी भी लोकतंत्र की साख को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। हमारे लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय सच्चाई यही है कि चाहे सरकारी खेमा हो या विपक्षी दल, वे चुनावी परिणाम को लेकर कभी पूरी तरह आश्वस्त होने का जोखिम नहीं ले सकते और वास्तव में यही होना भी चाहिए। यहां केवल इसी बात की निश्चिंतता है, जिसमें यह थाह ली जा सके कि सियासी जमीन खिसक रही है और समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में वास्तविकता को स्वीकार करने वाले ही बदलाव की सही दिशा को भांप सकते हैं।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

# संरचनात्मक सुधारों की प्रतीक्षा में शिक्षा



गिरीश्वर मिश्र

**कोई भी समाज अपनी कैसी रचना करना चाहता है, इसका विकल्प शिक्षा द्वारा ही तय होता है**

नई शिक्षा नीति को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया। यह संतोष का विषय है कि लगभग तीन दशकों के बाद भारत ने अपने लिए शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल की और नई शिक्षा नीति के रूप में उसका एक महत्वाकांक्षी मसौदा तैयार किया। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन खुले मन से शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करते हुए किया गया। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि शिक्षा जगत की समस्याएं लगातार इकट्ठी होती रहीं और सरकारी उदासीनता के चलते कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ कि आकार में विश्व की एक प्रमुख वृहदाकार शिक्षा व्यवस्था तदर्थ रूप में चलती रही। हम लोग पुराने ढांचे में छिटपुट बदलाव और थोड़ी बहुत काट-छांट से काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि खराब गुणवत्ता वाली संस्थाओं का अंबार लग गया, लेकिन उनके समुद्र में श्रेष्ठ संस्थाओं के कुछ टापू नजर आते रहे, जिनमें पढ़-लिखकर युवा विदेश जाने को तत्पर रहे।

सभी संस्थाओं की अपनी जीवनी होती है और निहित रुचि या स्वार्थ भी होते हैं, जिनके तहत उनका संचालन होता है। नई शिक्षा नीति इन पर भी गौर कर रही है और संरचनात्मक रूप से बदलाव की तैयारी में है। हमारे पाठ्यक्रमों को लेकर यह शिकायत बनी रही है कि वे भारतीय समाज, यहां की संस्कृति, विरासत और ज्ञान की देशज परंपरा से कटे हुए हैं और कई तरह की मिथ्या धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। भारत को भारत में ही हाशिये पर पहुंचाते हुए ये पाठ्यक्रम एक संशयग्रस्त भारतीय मानस को गढ़ने का काम करते रहे हैं। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीयता का आग्रह किसी तरह की अवैज्ञानिकता या कट्टरपंथी दृष्टि की विश्व विजय की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि भारतीय विचार व्यापक हैं और सबका समावेश करने वाले हैं। उनमें मनुष्य या प्राणिमात्र की चिंता है और वे पूरी सृष्टि के साथ जुड़कर जीने में विश्वास करते हैं। योग और आयुर्वेद का ज्ञान और उनकी प्रक्रियाओं का स्वास्थ्य और मानसिक शांति पाने के लिए महत्व जगजाहिर है और उनकी स्वीकृति भी है।

जब नई शिक्षा नीति को भारत केंद्रित बनाने का संकल्प किया गया तो वह न केवल शिक्षा में भारत को पुनर्स्थापित करने के लिए था, बल्कि मनुष्यता के लिए जरूरी समझ कर किया गया। आज जलवायु का जो संकट है, वह भी भारतीय दृष्टि की ओर ध्यान दिलाता है, जिसमें मनुष्य को सिर्फ उपभोक्ता समझने की सख्त मनाही है। भारत केंद्रित शिक्षा वस्तुतः मनुष्य और जीवन केंद्रित शिक्षा है और वह उन मूल्यों के प्रति समर्पित है जो सह अस्तित्व, सहकार और परस्पर सहयोग को जीवन शैली में स्थापित करती है। मनुष्यत्व के इन चिन्हों को बचाए रखना और संजोना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन्हीं के संदर्भ में आयोजित किया जाना चाहिए। इनके स्रोत अभी भी जीवन और समाज में मौजूद हैं। उपेक्षा के कारण वे कुछ कुम्हला जरूर गए हैं, पर उन्हें हरा-भरा किया जा सकता है।



केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तय करनी होंगी प्राथमिकताएं। फाइल

शिक्षा को नौकरी से जिस तरह जोड़ा गया और जीवन के अन्य उद्देश्यों से तोड़ दिया गया, वह एक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या बन गई है। शिक्षा समाज की खास जरूरत होती है, क्योंकि समाज अपनी कैसी रचना करना चाहता है, इसका विकल्प शिक्षा द्वारा तय होता है। न्याय, समता और स्वतंत्रता जैसे सरोकार स्थापित करने के लिए और नागरिक के दायित्व मन में बैठाने के लिए शिक्षा अवसर दे सकती है, बशर्ते उसका आयोजन इन मूल्यों की अभिव्यक्ति करते हुए किया जाए। इसके लिए जिस मानसिकता की आवश्यकता है, वह प्रवेश और परीक्षा की चालू अनुष्ठानप्रधान शैली से नहीं निर्मित हो सकती। कोरोना के दौर में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमें मूल्यांकन के नए विकल्प ढूंढने ही होंगे, साथ ही आनलाइन शिक्षा को भी व्यवस्था में शामिल करना होगा। इसी तरह मातृभाषा में शिक्षा मिले, इस बात की वकालत करते हुए पद्धति में बदलाव लाने की बात की गई है। शिक्षा को सिर्फ किताबी न बनाकर जीवनोपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है।

शिक्षक-प्रशिक्षण हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव को झेलने के लिए संस्थाओं की संख्या जरूर बढ़ती गई, पर उसी अनुपात में शिक्षा स्तर में गिरावट भी दर्ज हुई और गुणवत्ता का सवाल गौण होता गया। सरकारी तंत्र से अलग निजी शिक्षा संस्थान भी खड़े होते गए। स्कूली शिक्षा में कान्वेंट और मिशनरी स्कूलों का एक अलग दर्जा अंग्रेजों के जमाने में ही बन गया था। उसी की तर्ज पर धनाढ्य वर्ग भी स्कूल चलाने में रुचि लेने लगा और अब उच्च शिक्षा में भी उसकी अच्छी दखल हो चुकी है। शिक्षा जगत में निजी क्षेत्र का विस्तार खूब हुआ है, पर कुछ गिनी-चुनी संस्थाओं को छोड़ दें तो निजी क्षेत्र की उतनी साख नहीं बन सकी है जिसकी अपेक्षा की गई थी। इन परिस्थितियों में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का स्वप्न कमजोर पड़ता है। संसाधनों की कमी और शिक्षा के प्रति सरकारों के अल्पकालिक और चलताऊ रवैये के कारण शिक्षा संस्थानों में अकादमिक संस्कृति प्रदूषित होती जा रही है। शैक्षिक परिसर राजनीतिमुक्त और स्वाधीन होने चाहिए ताकि वे उत्कृष्टता और गुणवत्ता की ओर उन्मुख हो सकें।

नई शिक्षा नीति के प्रति वर्तमान सरकार ने अनेक अवसरों पर प्रतिबद्धता दिखाई है, परंतु कोरोना ने उसके क्रियान्वयन में गतिरोध पैदा किया है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा जगत में वेबिनारों की सहायता से जागृति फैली है, भ्रम दूर हुए हैं और लोगों में आशा का संचार हुआ है। अब आवश्यकता है कि संरचनात्मक सुधारों को लागू किया जाए, पर सबसे जरूरी है कि शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक वातावरण की बहाली की जाए और अकादमिक संस्कृति का क्षरण रोका जाए।

(लेखक पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### मोक्ष प्राप्ति का पूर्वाभास

मोक्ष एक परम आकांक्षा है, परंतु उसके लिए पात्रता भी आवश्यक है। इस पात्रता की परिभाषा भी समझनी होगी। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति और परमब्रह्म में विलीन होना। यह भी तथ्य है कि एक जैसे तत्व ही एक दूसरे में विलय हो सकते हैं। ईश्वर यानी ब्रह्म निर्गुण तथा सम स्थिति में है। इसका अर्थ है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त है। यदि प्राणी भी उसमें विलीन होना चाहता है तो उसे भी इसी स्थिति में आना पड़ेगा। तभी वह मोक्ष का पात्र बनने में सक्षम हो सकेगा। इसीलिए प्रत्येक धर्म में यही शिक्षा दी गई है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले बुराइयों से मुक्ति पानी होगी।

सनातन धर्म में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसे चार भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्तमान में 60 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य का एक प्रकार से वानप्रस्थ आरंभ हो जाता है। जीवन के इस पड़ाव पर उसे सांसारिक बुराइयों से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे पतंजलि के अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए। यदि वह इसके पहले दो कदम यानी यम-सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असते और अपरिग्रह तथा नियम-ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, शौच, तप, संतोष और स्वाध्याय को ही अपना ले तो बहुत हितकारी होगा। इसमें अपरिग्रह से तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक भंडारण न करना। असते अर्थात किसी प्रकार की चोरी न करना। इन दोनों कदमों से ही मनुष्य की मानसिकता बदल जाएगी और परम शांति तथा सम स्थिति का अनुभव होगा। ऐसी अवस्था जिसमें कोई कामना या भय नहीं रहेगा। यदि यह अवस्था स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य को यह आभास हो जाना चाहिए कि वह मोक्ष का पात्र बन गया है और अब उसे सर्वशक्तिमान स्वयं अपने में विलीन करके परम शांति प्रदान करेंगे। इसी को मोक्ष का आभास भी कहा जाता है।

कर्नल शिवदान सिंह

# पहनावे के चुनाव का हक

डा. मोनिका शर्मा

**खेल हों या आम जिंदगी, अपनी मर्जी का पहनावा भी महिलाओं की समानता और सहजता से जुड़ा अहम पक्ष है**

टोक्यो ओलिंपिक के प्रशिक्षण सत्र में जर्मन महिला जिम्नास्ट टीम ने फुल-लेंथ बाडी सूट पहना और कहा कि प्रतियोगिता में भी इसे ही चुना जा सकता है। दरअसल टीम का मकसद यह दिखाना था कि पहनावे का चुनाव हमारा होगा। इसी टीम का हिस्सा जिम्नास्ट सारा वास के मुताबिक हम दिखाना चाहते हैं कि हर महिला, हर इंसान को तय करना चाहिए कि क्या पहनना है?

दरअसल खेल का मैदान हो या घर का आंगन, औरतों के पहनावे को लेकर बहस जारी है। इसी के चलते आज भी पहनावे से जुड़े नियम महिलाओं को कई क्षेत्रों का हिस्सा बनने से रोकते हैं। काबिलियत और रुचि के बावजूद किसी खास क्षेत्र में दस्तक देने में बाधा बनते हैं तो घरों में पहनावे से जुड़े नियम बंधन से लगते हैं। हमारे देश में ही नहीं दुनियाभर में ड्रेस कोड से जुड़ी असहजता औरतों के कदम ही पीछे नहीं खींचती, बल्कि यह उनकी सहूलियत से जुड़ा मामला भी है। खेल के समय तो सबसे ज्यादा सहजता की दरकार होती है, पर यह भी सच है कि खेलों की दुनिया में महिलाओं के स्पोर्ट्सवियर को लेकर कई नियम आज भी मौजूद हैं। बीते दिनों नार्वे की बीच हैंडबाल टीम पर यूरोपीय हैंडबाल फेडरेशन ने मैच में बिकिनी बाटम्स की जगह शार्ट्स पहनने को लेकर जुर्माना लगाया था। फेडरेशन ने इसका कारण यूनिफार्म के नियम को तोड़ना बताया था।

नार्वे में आमजन से लेकर खेल मंत्री तक ने फेडरेशन द्वारा जुर्माना लगाए जाने को लेकर विरोध जताया। इस विषय पर खूब विमर्श हुआ कि खेल के मैदान में महिला खिलाड़ी असुविधाजनक पहनावे के बजाय सहजता और सहूलियत के मुताबिक ड्रेस क्यों नहीं पहन सकतीं? क्यों कई खेलों के ड्रेस कोड के साथ एक खास सोच जुड़ी है? यह भी एक तरह का लैंगिक भेदभाव ही है, जो महिला खिलाड़ियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।

गौरतलब है कि साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय महिला खिलाड़ियों के दल ने भी साड़ी की जगह ब्लेजर और पैंट पहनने की शुरुआत की थी। तब भारतीय ओलिंपिक संघ ने खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरे के बाद यह फैसला लिया। गौरतलब है कि भारतीय महिला एथलीट अंजू बाबी जार्ज ने भी कहा था कि ओलंपिक खेलों में भारतीय दल में महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते समय साड़ी पहनकर चलते हुए उन्हें काफी दिक्कत हुई थी। ऐसे में तीन साल पहले यह कदम महिला खिलाड़ियों के पहनावे को लेकर परंपरागत नियमों से अलग उनकी सहजता और सहूलियत को देखकर उठाया गया था। ध्यान रहे कि सहज सा लगने वाला यह कदम महिला खिलाड़ियों की सहूलियत से जुड़ा एक बड़ा बदलाव था। अब जर्मन महिला जिम्नास्ट टीम द्वारा दिया गया यह संदेश कई मोर्चों पर औरतों की बेहतरी से जुड़ा है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### गलत परंपरा पर लगे विराम

संपादकीय टिप्पणी 'ठहरी हुई संसद' में संसद की मौजूदा स्थिति को लेकर एकदम सही बातें कही गई हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधियों का मौजूदा प्रदर्शन कई प्रश्न उठाने वाला है। वास्तव में जिन जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार से अनुकरणीय मिसाल कायम करनी चाहिए थी उन्हें लेकर ही अब सवाल उठने लगे हैं। संसद लोकतांत्रिक ढांचे के अहम अवयव विधायिका की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यदि उसका ही संचालन सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा तो देश की अन्य विधायी संस्थाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत नहीं होगा। जो विधानमंडल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक बनने वाली विधियों के प्रवर्तक बनने चाहिए जब वही शालीनता की सीमा को लांघकर मर्यादा को तार-तार करते हैं तो यह देखकर हमारे राष्ट्र के संस्थापकों की आत्मा अवश्य ही कलपती होगी। निःसंदेह मौजूदा राजनीतिक विपक्ष की भूमिका रचनात्मक न होकर नकारात्मक है, लेकिन इसमें केवल उसे ही दोष देना उचित नहीं होगा। सत्तारूढ़ पक्ष अतीत में जब प्रतिपक्ष के पाले में था तब उसका आचरण भी कोई अलग और प्रशंसनीय नहीं था। हालांकि इस आधार पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि पूर्व में विपक्ष ने कुछ अनुचित किया तो मौजूदा विपक्ष को भी उसकी पुनरावृत्ति का अधिकार मिल जाता है। यदि यह सिलसिला थमा नहीं तो लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को ही क्षति पहुंचेगी। इस पर कहीं न कहीं विराम लगाना ही होगा अन्यथा लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराएं इसी प्रकार क्षतिग्रस्त होती रहेंगी। उनकी क्षतिपूर्ति और पोषण संसदीय कार्यवाही में अवरोध पहुंचाने वाली परिपाटी के परित्याग करने से ही संभव और सुनिश्चित हो सकेगा।

मनीष कश्यप, नई दिल्ली

### सोच समझकर लिए जाएं फैसले

कुछ महीने पहले की ही बात है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि अब धीरे-धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं। राज्यों में लगी पाबंदियां अब कम हो रही हैं। इस बीच तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लंदन, अमेरिका और बांग्लादेश में एक बार फिर डेल्टा केस में इजाफा हो रहा है। भारत की बात करें तो यहां भी पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में डेल्टा वैरिएंट का साया गहराता जा रहा है। मामले बढ़ने के कारण मणिपुर में दस दिन और मिजोरम में सात दिन का पूर्ण लाकडाउन लगा दिया गया है। अकेले केरल से ही पचास फीसद से अधिक केस आ रहे हैं। यह एक संकेत है। इस बात को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। दूसरी लहर में की गई गलतियों और लापरवाही से हमें बचना होगा। केंद्र और राज्य सरकार को भी सतर्कता के साथ कदम उठाने की जरूरत है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। इन सब के बीच स्कूल और कालेज को खोलने की कवायद भी शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि सभी कर्मचारी और शिक्षक पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके हों। बेहतर तो यही होगा कि अभी सिर्फ अंतिम वर्ष और बोर्ड के विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। उसके बाद सभी वर्ग, कक्षा और विभाग को खोला जाना चाहिए। जो भी निर्णय हो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर हो, इसी में सबकी भलाई है।

अमन जायसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय

### परिपक्वता का देना होगा परिचय

असम और मिजोरम अपनी सीमा को लेकर अलग-अलग दावे करते रहे हैं। इसी वजह से दोनों के बीच लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है, जो बीच-बीच में भड़क उठता है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वह उसी का परिणाम है। भौगोलिक दृष्टि से विशालता के साथ सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्यता भारत की विशेषता रही है, लेकिन संकीर्ण हितवाद के आधार पर जब पारस्परिक संघर्ष एवं द्वंद्व उत्पन्न हो जाए तो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति विखंडनवाद को बढ़ावा देती है। असम में क्षेत्रीय भावनाओं के वशीभूत कई बार ऐसे संघर्षों को देखा गया है। अब यह जरूरी है कि संकीर्ण प्रांतीयता के संघर्ष की बजाय विवेकपूर्ण समाधान ढूंढें।

हरीश कुमार शर्मा, बख्तावरपुर गांव

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

**16.5** प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार का है देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में से। और कुल बाढ़ पीड़ित आबादी में 22.1 फीसद बिहार में रहती है।



आजकल



डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

# हर साल तबाही का सबब बनती बाढ़

बाढ़ अब देश की एक स्थायी समस्या बन गई है। दुख की बात है कि हर साल बाढ़ आती है, हल्ला मचता है, दौरे होते हैं और राहत पैकेज की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती। ऐसे में अब अहम सवाल यह है कि चांद पर झंडा बुलंद करने वाले इस देश की सरकारें जमीन पर आने वाली इस प्रलय के लिए आखिर कोई मिशन क्यों नहीं बना सकीं? हर साल आम लोग क्यों सरकार की नाकामी की बलि चढ़ते जा रहे हैं?



बाढ़ के वास्तविक कारणों की पहचान कर उनको खत्म करने की है जरूरत। फाइल

बीते दिनों देश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची। इससे एक दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र के तटीय कोंकण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के करीब 13 जिले बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। उधर बिहार और असम हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ की चपेट में हैं। मानसून के दौरान देश में भारी बारिश तथा बाढ़ आने, बादल फटने और भूस्खलन से देश के विभिन्न क्षेत्रों में तबाही का यह सिलसिला डरावना और चिंताजनक है। दुख की बात है कि मानसून के दौरान देश का एक बड़ा हिस्सा पहले बाढ़ का कहर झेलता है और फिर बाढ़ के पानी के उतरने के पश्चात भिन्न-भिन्न बीमारियों से जूझता है। जब तक जन-जीवन पटरी पर आता है तब तक एक और बाढ़ का समय आ चुका होता है। और कहानी फिर स्वयं को दोहराती है। नदी का जल उफान के समय जब जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास की जमीन को चपेट में लेता है तो इसी को बाढ़ की स्थिति कहते हैं।

वैसे बाढ़ की यह समस्या अकेले भारत में नहीं है। इस बार तो यूरोप के कई देश, अमेरिका और चीन भी पानी-पानी हुए हैं। यूरोप के जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड समेत स्पेन आदि देशों में बारिश ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस बार पिछले सौ साल की तुलना में सबसे भयंकर बाढ़ आई है। यूरोप को इस बार बाढ़ के कारण करीब 70 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अमेरिका भी इन दिनों वह एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बाढ़ की चपेट में है। गौरतलब है कि दक्षिण-पश्चिम अमेरिकी राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का जीवन मुहाल है, जबकि दक्षिण-पूर्वी राज्यों में भीषण चक्रवाती तूफान से हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। इसके पहले इसी साल मार्च में अमेरिका के उत्तरी राज्यों में इतनी बर्फ गिरी कि हफ्तेभर तक बिजली गुल रही थी। वहीं दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माने जाने वाले चीन में बारिश ने पिछले एक हजार वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। चीन के झेंगझोउ प्रांत में रिकार्ड 617 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह आंकड़ा तीन दिन का है, जबकि वहां साल भर में 640 मिलीमीटर बारिश होती है।

दरअसल मानव की गतिविधियों ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी में एक बाढ़ भी है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े को देखें तो 1950 में देश में 371 बांध थे। अब इनकी संख्या पांच हजार के करीब है। गौरतलब है कि नदियों पर बनने वाले बांध और तटबंध जल के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालते हैं। बारिश की स्थिति में नदियां उफान लेती हैं और इसी तटबंध को तोड़ते हुए मानव बस्ती को डुबो देती हैं। विश्व बैंक ने भी कई बार यह बात कही है कि नदियों पर जो बांध बने हैं, उनसे फायदे के स्थान पर नुकसान अधिक होता है। देश-दुनिया में बाढ़ आने के कारणों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी है। कुल मिलाकर फैलते शहर, सिकुड़ती नदियां और लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन बाढ़ की विभीषिका पैदा कर रहे हैं।

बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? दरअसल तकनीकी विकास के साथ-साथ मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों को प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी यह भविष्यवाणी 50 से 60 फीसद ही सही ठहरती है। वहीं देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चेतावनी केंद्र स्थापित करने की बात बरसों से लटकी हुई है। सभी बाढ़ इलाकों में नूतन तकनीक के साथ इन्हें स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी व्यवस्था को बिना किसी देरी के दुरुस्थ किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए केंद्र को और दो कदम आगे आना चाहिए। इनके अलावा नदियों में गाद का संचय होना, मानव निर्मित अवरोधों का उत्पन्न होना और वनों की कटाई जैसे अन्य कारण भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। इन पर भी ठोस कमा होने चाहिए।

दुनिया में जल निकासी प्रबंधन : यह सच है कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता। न ही इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। मगर सही रणनीति, तकनीक और साथ ही इसके प्रति सजगता विकसित की जाए तो जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने सही जल प्रबंधन के बल पर बाढ़ की समस्या से निजात पा ली है। छोटे-से देश सिंगापुर ने पूरी तरह बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी की सही व्यवस्था करने से वहां बाढ़ के मामलों में 98 फीसद कमी आई है। नीदरलैंड ने भी अपने जल प्रबंधन के चलते भारी बारिश के बावजूद कोई जन हानि नहीं होने दिया है। गौरतलब है कि नीदरलैंड एक समय समुद्र और उफनती नदियों से जूझता था। चूंकि उसकी अधिकांश भूमि समुद्र तल से नीचे है ऐसे में उसके 66 फीसद हिस्से में बाढ़ आने का जोखिम बना रहता था। इससे निपटने के लिए नीदरलैंड ने अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हुए जल प्रबंधन की व्यवस्था की। इसके चलते अब वहां हालात नियंत्रण में हैं। जापान, फ्रांस भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये देश पानी से लड़ने के बजाय पानी के साथ जीने का रास्ता खोज रहे हैं।

भारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही तो होती है भीषण गर्मी और सूखे भी तबाही के प्रतीक हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट तो कहती है कि 2030 तक प्रचंड गर्मी के कारण भारत में करीब साढ़े तीन करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। फिलहाल गर्मी और बाढ़ दोनों जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं, जिन्हें रोकते-रोकते दशकों हो गए, मगर परिणाम ढाक के तीन पात हैं। वास्तव में भारतीय कृषि के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून वरदान है। लिहाजा मानसून भी बना रहे और बाढ़ पर नियंत्रण भी पा लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा होगा।

## प्राकृतिक आपदाओं से घिरा भारत

रवि शंकर

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 400 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं हर साल लगभग 76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आती है। इससे औसतन 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती हैं। आशंका है कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन का असर बाढ़ की विभीषिका तथा जानमाल की हानि के ग्राफ को बढ़ाएगा। विश्व बैंक के एक अध्ययन में अंदेशा जताया गया है कि 2040 तक देश के ढाई करोड़ लोग भीषण बाढ़ की चपेट में होंगे।

बिहार के ही करीब 11 जिले के 388 पंचायत इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 16.5 प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार का है और कुल बाढ़ पीड़ित आबादी में 22.1 फीसद बिहार में रहती है। पिछले 43 वर्षों में एक भी ऐसा साल नहीं गुजरा, जब बिहार में बाढ़ नहीं आई हो। इसकी वजह से प्रदेश में हर साल औसतन 200 इंसानों और 662 पशुओं की मौत होती है और सालाना तीन अरब रुपये का नुकसान होता है।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई इकोनामिक लासेज, पावर्टी एंड डिजास्टर 1998-2017 के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में अकेले भारत को बाढ़ के कारण 79.5 बिलियन डालर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ की वजह से गुजरे 64 वर्षों में 1,07,487 लोगों की जान चली गई। यानी हर साल औसतन 1,654 लोगों के अलावा 92,763 पशुओं की मौत होती रही है। विभिन्न राज्यों में आने वाली बाढ़ से सालाना औसतन 1.680 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो जाती हैं और 12.40 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सरकार के अनुसार 1976 से लेकर 2017 तक हर साल (1999 में 745 और 2012 में 933 मौतों को छोड़कर) इस प्राकृतिक विपदा से मरने वालों की संख्या एक हजार से ज्यादा ही रही है। इंसानी जान के अलावा जल संबंधी आपदा से अगर फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जाए तो बीते 66 वर्षों में 3,65,860 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के आधार पर नजर डालें तो हर साल औसतन 5628.62 करोड़ रुपये भारी बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ जाती हैं। वहीं इंटरनल डिस्प्लेमेंट मानीटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल औसतन बीस लाख लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो जाते हैं। इसके बाद चक्रवाती तूफानों के कारण औसतन 2.50 लाख लोगों को हटाया जाता है।

जाहिर है भारत एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं से घिरा देश है। अब यह एक स्थाई समस्या बन गई है। हर साल बाढ़ आती है, हल्ला मचता है, दौरे होते हैं और राहत पैकेज की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती। ऐसे में अब अहम सवाल यह है कि चांद पर झंडा बुलंद करने वाले इस देश की सरकारें जमीन पर आने वाली इस प्रलय के लिए आखिर कोई मिशन क्यों नहीं बना सकीं? हर साल आम लोग क्यों सरकार की नाकामी की बलि चढ़ते जा रहे हैं?

इस लिहाज से जरूरी है कि बरसाती पानी का ऐसा प्रबंध किया जाए कि उसका जल भराव नदियों, नालों और बांधों में हो, जिससे बरसात के पानी का उपयोग जल की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में किया जा सके। केवल मृतकों के परिजनों और प्रभावित क्षेत्रों को मुआवजा देना बाढ़ का समाधान नहीं है। बाढ़ के वास्तविक कारणों को खत्म करने के लिए राष्ट्र स्तरीय नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने की सख्त आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## खरी-खरी

### जिंदगी, भार और कंधे

अरुण अर्णव खरे

हमारी आदत है भार से बचने की। भार उठाने की बात आई नहीं कि हम बचने के रास्ते तलाशने लगते हैं। रिश्तेदार दो-चार दिनों के लिए घर आकर टिक जाएं तो भार प्रतीत होने लगते हैं। अचानक कोई अतिरिक्त खर्चा आ जाए तो भार लगने लगता है। यदि बास समय-सीमा में कोई काम करने के लिए कह दे तो सिर भारी हो जाता है। मित्र-मंडली में किसी दिन वांछित तवज्जो नहीं मिली तो दिल भारी हो जाता है। कुछ मन का ज्यादा खा लो तो पेट भारी और मेहनत का मनचाहा फल न मिल पाए तो उम्मीदें भारी पड़ जाती हैं। जहां जवान होते बेटे को पिता की कही हल्की बात भी भारी लगती है, वहीं बहू को जरा सा टोकना सास पर भारी पड़ जाता है। भार उठाने के यही खतरे भार वहन करने की चाह में आड़े आते हैं। सोचते हैं इतना भार उठाएंगे तो जिंदगी भारी हो जाएगी, लेकिन जिंदगी के बोझ से झुके हमारे कंधे बड़े मजबूत होते हैं।

भार उठाने से बचना केवल हमारी नहीं, बल्कि सबकी आदत है। सबकी आदत है इसलिए सरकार की भी आदत है, लेकिन हमारी और सरकार की आदत में मूलभूत अंतर है। भार से बचना हमारी फितरत है और अपना भार कम करने के लिए हम पर भार डालना सरकार की आदत है। सरकार को लगता है कि हममें भार वहन की कूवत उससे ज्यादा है। वह जानती है कि खुद के भार से दबे हमारे कंधे उससे ज्यादा मजबूत हैं, जो नौकरियां गंवा कर, बेरोजगार रहकर, रूखा-सूखा खाकर भी उसका दिया भार किसी तरह झेल ही जाते हैं। हमारी जिंदगी कभी मन मुताबिक नहीं चलती, लेकिन हमेशा लगता है कि यदि जिंदगी भारहीन हो जाएगी तो जिंदगी से जैसे सारे रंग ही गायब होने लगेंगे। भार से हमारी खुशियां हैं और भार में ही हमारी खुशियों के सूत्र हैं। टोक्यो में हमने देखा कि किस तरह जिंदगी का भार हल्का करने की जद्दोजहद में सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ढोते-ढोते एक बेटी 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भार उठाने में सफल रही। विश्व मंच पर उसने अपने कंधों की मजबूती का ऐसा हुनर दिखाया कि सारा देश वाह-वाह कर उठा। जिंदगी के भार से झुके कंधे उम्मीदों को जिंदगी दे गए।

## ट्वीट-ट्वीट

अगर कम सीरो पाजिटिविटी से केरल बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बन जाता है तो कोई असम की बात क्यों नहीं कर रहा, जो इस मामले में दूसरे पायदान पर है, जबकि असम में केरल के मुकाबले कोरोना के बहुत कम मामले हैं। क्या यही माना जाए कि केरल में ही टेस्टिंग हो रही है और दूसरे राज्य इसमें पिछड़ रहे हैं। यह भी एक तथ्य है कि असम केरल के बराबर ही टेस्ट कर रहा है और कई मामलों में उससे भी ज्यादा।
कौशिक डेका@KDscribe

जिस तरह महाराष्ट्र व केरल का फ्लाप माडल कोरोना से लड़ाई में सुपरहिट बताकर बेचा गया है, उसे देखते हुए कुछ लोगों को मार्केटिंग का ही काम करना चाहिए। वे पत्रकार बेकार ही बन गए।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha



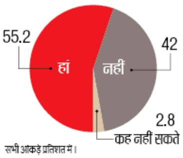
इस पर बड़ी हैरानी होती है कि पेगासस मामले में ममता बनर्जी द्वारा जांच आयोग गठित करने के बावजूद तृणमूल सांसद संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। क्या उन्हें खुद अपने द्वारा गठित और अपनी पसंद के सेवानिवृत्त जजों द्वारा बनाई गई संस्था पर भरोसा नहीं है? या फिर वे मूल रूप से अराजकतावादी ही हैं?
महेश जेठमलानी@JethmalaniM

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पीवी सिंधू का अगला मुकाबला जापानी शटलर यामागुची से होगा। दोनों का अब तक 18 बार आमना-सामना हो चुका है, जिसमें से सिंधू ने 11 बार जीत हासिल की है, लेकिन यह मैच बहुत कड़ा होगा।
विक्रम चंद्रा@vikramchandra

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेगासस जासूसी मामले में जांच की जरूरत है?




सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या लोकसभा में पर्चे उड़ाने वाले सांसदों को निलंबित किया जाना चाहिए था?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

चौटाला की हड्डियों में आई फिर जान,
उम्मीदें चढ़ने लगीं लालू की परवान।
लालू की परवान जेल से दोनों लौटे,
खोज रहे बाजार आजकल सिक्के खोटे!
आइकॉन है आज करे जो भी घोटाला,
घूमें सीना तान यहां लालू-चौटाला!!
-ओमप्रकाश तिवारी



प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

# असमंजस में कांग्रेस




रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस से बात करते कांग्रेस के नेता। जागरण आर्काइव

एक निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर दो कांग्रेसी विधायकों द्वारा हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद राज्य की राजनीति में बेशक कोई भूचाल न आया हो, लेकिन कांग्रेस में अंदरखाने चल रहा घमासान पूरी तरह सतह पर आ गया है। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति सांप-छछूंदर वाली हो गई है। न तो वह इस साजिश से पूरी तरह इन्कार कर पा रही है और न ही स्वीकार करने की स्थिति में है। कांग्रेस इसका ठीकरा विपक्षी भाजपा पर फोड़कर उसे घेरने की नाकाम कोशिश तो कर रही है, लेकिन पार्टी विधायकों को लेकर वह पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नहीं, पार्टी का एक धड़ा आरोपित विधायकों के साथ खड़ा हो गया है और उन्हें पूरी तरह पाक-साफ बता रहा है। रांची पुलिस का विशेष जांच दल (एसआइटी) इस मामले की तफ्तीश में जुटा है। हो सकता है इस जांच का अंतिम परिणाम आने में काफी समय लग जाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेसी विधायकों की बार-बार दिल्ली दौड़ पर कुछ समय के लिए अंकुश लग सकता है।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अभी सबकुछ ठीक नहीं ही चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव के खिलाफ कुछ विधायक लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। उन पर अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव है। उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वह पार्टी विधायकों की बात को सरकार के समक्ष मजबूती से नहीं रख रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह यहां अभी आमने-सामने दो फ्रंट नहीं बने हैं, लेकिन अलग-अलग ग्रुप में कई विधायक दिल्ली के चक्कर लगाकर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना दुखड़ा सुना चुके हैं। जब भी कांग्रेसी विधायकों का कोई ग्रुप दिल्ली जाता है राज्य में हलचल शुरू हो जाती है। कांग्रेस विधायकों की दिल्ली यात्राओं को यहां राजनीतिक गलियारे में हमेशा शक की निगाह से ही देखा जाता रहा है।

सरकार गिराने की साजिश के शक में रांची पुलिस ने जिन तीन आरोपितों अभिषेक दुबे, अमित सिंह व निवारण महतो को गिरफ्तार किया है उनके साथ दिल्ली के विवांता होटल की सीसीटीवी फुटेज में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक डा. इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित यादव दिखे हैं। गिरफ्तार आरोपितों के बयान के बाद भी अभी इन तीनों विधायकों का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में महाराष्ट्र के जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुडे व महाराष्ट्र के ही भाजपा नेता व पूर्व मंत्री चंद्रशेखर राव बावनकुले व चरण सिंह भी इन विधायकों के साथ दिखे हैं। झारखंड के तीनों विधायक और आरोपित 15 जुलाई को इंडिगो की फ्लाइट से ही दिल्ली गए थे। एक आरोपित के मुताबिक सभी का यात्रा टिकट जय कुमार बेलखेड़े ने कटवाया था। इस साजिश पर से पर्दा उठने के बाद भाजपा नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले मीडिया के समक्ष आकर इसे बेबुनियाद बता चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड सरकार को गिराने की न तो उनकी हिम्मत है और न ही औकात।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये तीन विधायक सरकार को अस्थिर करने में सक्षम थे? देखा जाए तो 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को 52 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 30, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल का एक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (एनसीपी) का एक और दो निर्दल विधायकों विनोद सिंह व सरयू राय के साथ-साथ कांग्रेस में विलय का इंतजार कर रहे बंधु तर्की व प्रदीप यादव शामिल हैं। सरकार गिराने के लिए कम से कम 12 विधायकों की जरूरत होगी। यह तभी संभव है जब कांग्रेस के एक तिहाई विधायक टूटकर नया धड़ा बना लें और भाजपा को समर्थन दे दें।

यह सोलह आना सच है कि सरकार में मंत्री बने कांग्रेस कोटे के चार विधायकों के अलावा अन्य सभी कांग्रेसी विधायक किसी न किसी कारण से अपनी नाखुशी जाहिर करते रहते हैं। इनमें ज्यादातर की नजर कैबिनेट में खाली एक सीट पर लगी हुई है। झामुमो ने कुछ दिनों पहले स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव पूर्व हुए समझौते के मुताबिक खाली बर्थ पर उसका हक है। कांग्रेसी बेवजह सपने न पालें। उधर कांग्रेस विधायक 20 सूत्रीय कमेटियों और निगमों-बोर्डों के अध्यक्ष पद पर भी नजर जमाए हुए हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार के पौने दो साल होने को आ रहे हैं और उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। जब हंगामा मचता है तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जल्द से जल्द इन खाली पदों पर नियुक्तियों का सुर्रा छोड़कर सभी को शांत करवा देता है। झामुमो भी इससे खुश है। उसे भी पता है कि सभी को मलाइदार पद चाहिए और यह संभव नहीं है।

संसद का मानसून सत्र



पीयूष द्विवेदी
स्वतंत्र पत्रकार

# गतिरोध की संकीर्ण राजनीति

संसद की मर्यादा का हनन करने, कामकाज बाधित करने एवं संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने की स्थिति में सांसद के वेतन-भत्ते को रोकने से लेकर उसका निर्वाचन रद करने तक की व्यवस्था होनी चाहिए



संसदीय कार्यवाही के दौरान शोरशराबे में गुम होते आमजन से जुड़े अहम मुद्दे। फाइल

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पूर्व केंद्र सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 33 दलों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार है और सदन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए उन्हें सभी दलों का सहयोग चाहिए। इस बैठक के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि मार्च में संसद का बजट सत्र निर्धारित समय से तेरह दिन पूर्व ही समाप्त हो जाने के चलते जो कार्य लंबित रह गए थे, उन सबकी भरपाई भी इस मानसून सत्र में हो जाएगी, लेकिन यह सत्र शुरू होने के बाद से जो नजारा दिखाई दे रहा है, वह बेहद शर्मनाक है।

मानसून सत्र को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित न करनी पड़ी हो। सत्र के पहले दिन भारतीय संसद की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विस्तारित मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों से सदन का परिचय करवाना था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने संसदीय परंपरा की भी परवाह न करते हुए ऐसा हंगामा किया कि सरकार के नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया और बिना इसके ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ानी पड़ी। हद तो तब हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में कथित पेगासस प्रकरण पर बयान दे रहे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से उनके बयान की प्रति छीनकर फाड़ दी और उसके टुकड़े उपसभापति की ओर उछाल दिए। शांतनु सेन की इस शर्मनाक हरकत से विश्व में भारतीय लोकतंत्र के प्रति क्या संदेश गया होगा, यह सोचकर भी शर्म आती है। यह उचित ही है कि उन्हें इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, पर इससे विपक्षी विरोध की गतिविधियों में परिवर्तन नहीं आया है। लगता है जैसे विपक्षी दल यह तय करके बैठे हैं कि चाहें कुछ भी हो जाए सदन में कामकाज नहीं होने देना है।

सरकार द्वारा इस सत्र में 31 विधेयक पेश किए जाने थे। उम्मीद की जा रही थी कि करीब दो दर्जन विधेयक पारित भी हो जाएंगे, पर सप्ताह भर से अधिक समय बीत जाने के बाद केवल दो विधेयक ही पारित हुए हैं, वह भी बिना किसी चर्चा के। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र में संसद संवाद और विमर्श का सबसे बेहतर माध्यम है। उम्मीद की जाती है कि यहां हमारे जनप्रतिनिधि परस्पर चर्चा और विमर्श करके देश की जनता के हित में जरूरी कानून बनाएंगे। विपक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वह चर्चा के दौरान रचनात्मक रुख रखते हुए न केवल जनहित से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सरकार से उचित सवाल पूछेगा, बल्कि आवश्यक सुझाव भी देगा, लेकिन यहां तो विपक्ष संसद चलने देने को ही तैयार नहीं है।

विपक्षी दलों को शायद ऐसा लगता है कि सदन चलने पर सरकार बहुमत के बल पर अपने मनमुताबिक विधेयक पारित करवाकर जनता में अपनी छवि चमका लेगी। अतः वे व्यर्थ हंगामे के जरिये सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करके सरकार को विधेयक पारित करवाने से रोकने की रणनीति अपना रहे हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से सरकार काम नहीं कर पाएगी और उसकी छवि कमजोर होगी। यह काम विपक्षी दल पहले के सत्रों में भी खूब कर चुके हैं, लेकिन आश्चर्य है कि विपक्ष को यह बुनियादी बात समझ नहीं आ रही कि सदन का न चलना सरकार के लिए किसी भी प्रकार से विशेष हानिकारक नहीं है। अव्वल तो सरकार आवश्यक कानून अध्यादेश के जरिये या शोर-शराबे के बीच भी पारित करवाकर लागू कर सकती है, दूसरा वह बड़े आराम से जनता के बीच जाकर यह भी कह सकती है कि हम तो अमुक विधेयक सदन में लाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने संसद चलने ही नहीं दी। चूंकि सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण टीवी पर होता है तो जनता स्वयं भी सबकुछ देख ही रही है। ऐसे में विपक्ष को समझना चाहिए कि संसद में गतिरोध की राजनीति उसे कोई लाभ नहीं देगी, बल्कि इससे हानि होने की संभावना ही अधिक है।

सवाल यह है कि संसद में विशेषाधिकार की आड़ में हंगामे को रणनीति बना देश का पैसा बर्बाद करने वाले माननीयों को रोकने के लिए क्या हमारे पास कोई ठोस व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली देश के लिए उपयुक्त है, परंतु तमाम अच्छे लोगों एक बीच कुछ गलत लोग भी इसमें घुस आते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। सांसदों का निलंबन पर्याप्त नहीं है, अपितु वर्तमान समय को देखते हुए संसद की मर्यादा का हनन करने, कामकाज बाधित करने एवं संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने की स्थिति में किसी सांसद के वेतन-भत्ते को रोकने से लेकर उनका निर्वाचन रद करने तक की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था कठोर अवश्य है, परंतु इसके लागू होने के बाद निश्चित रूप से आज संसद में जो अराजकता नजर आ रही है, इसमें कमी देखने को मिलेगी तथा देश के संसदीय कामकाज में भी गुणात्मक वृद्धि होगी।

**18.62** करोड़ रुपये की सहयोग राशि से आइआइटी कानपुर में बनेगा चंद्रकांता केसवन सेंटर फार एनर्जी। इस सेंटर का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और नीतिगत समाधान का विकास करना रहेगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 30 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

# युवाओं पर फोकस करने की जरूरत

उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का युवाओं पर खास फोकस दिख रहा है। यह अच्छी बात भी है। हालिया दिनों में सरकार ने युवाओं को केंद्र में रखकर कई फैसले लिए हैं। सरकार को अहसास हुआ है कि यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मगर संसाधनों के अभाव और आर्थिक हालात ठीक न होने से वे प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने को नई योजना की पहल की है। एनडीए, सीडीएस, ओटीए की लिखित परीक्षा में सफल युवाओं को साक्षात्कार से पहले तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निश्चय किया गया है। इसी तरह संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहने वाले सभी और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहने वाले सौ युवाओं को भी मुख्य परीक्षा से पहले 50-50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मंशा यही है कि प्रतिभावान युवा मुकाम हासिल करने से वंचित न रहने पाएं।

**प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने संबंधी सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन बुनियादी सवालों पर भी ध्यान देने की जरूरत है**

दरअसल काफी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, मगर अच्छे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के अभाव में मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में पिछड़ जाते हैं। ऐसे में ये निश्चित रूप से अच्छी पहल है, लेकिन बुनियादी सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही विश्वविद्यालयों के स्तर में भी सुधार की दरकार है। खासकर विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की स्थिति व स्तर जरूर आंका जानी चाहिए। बुनियाद बेहतर होने पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए प्रोत्साहन राशि का सही फायदा मिल पाएगा। हालांकि सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण को सेवायोजन समेत अन्य माध्यमों से व्यवस्था की है, मगर यह कागजों में अधिक और धरातल पर कम दिखती है। प्रशिक्षण व्यवस्था को धरातल पर मूर्त रूप देना होगा। यदि उच्चकोटि के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की व्यवस्था होगी तो प्रतिभाओं को दूसरे राज्यों में जाने को विवश नहीं होना पड़ेगा। कहने का आशय यह कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं को भी अप टू डेट रखना होगा। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आनलाइन सामग्री उपलब्ध करा दी जाए तो इससे मेधावी विद्यार्थियों को अधिक लाभ होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी निरंतरता की दरकार है। आलम ये है कि पिछले पांच वर्ष से पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई है। यदि हर वर्ष परीक्षाएं नहीं होंगी तो प्रोत्साहन की योजनाएं घोषणा मात्र होकर रह जाएंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि युवाओं के व्यापक हित में सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान देगी।

पंजाब

# सियासी तूफान का असर

पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांटों के समझौतों को रद या उन पर पुनर्विचार करने का आदेश पंजाब पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएस) को देकर सियासी तूफान को थामने का प्रयास किया है। यह बिजली समझौते पूर्व अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय में हुए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था और यह कहा था कि गठबंधन सरकार ने अपने हितों के लिए यह समझौते किए हैं। इससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। कांग्रेस सत्ता में आई तो यह मामला करीब साढ़े तीन साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा था सरकार इन समझौतों पर श्वेत पत्र लाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कारण मुख्यमंत्री पर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कई नेता भी यह आरोप लगाने लगे थे कि उनका अकालियों के प्रति नरम रवैया है। इस बार बिजली संकट पैदा हुआ तो अभी तक इस मुद्दे को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में रहे अकाली दल ने भी आक्रामक रुख अपना लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि उसने राज्य को बिजली संकट से उबारने के लिए वक्त की जरूरत और राज्य की वित्तीय हालत के मद्देनजर यह समझौते किए थे। जहां तक कांग्रेस की ही बात है तो असंतुष्ट विधायकों व मंत्रियों के साथ-साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस में अंतर्कलह को दूर करने के लिए हाईकमान ने जो तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसके समक्ष भी विधायकों व मंत्रियों ने यह मामला रखा। कमेटी की सिफारिशों पर हाईकमान ने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले जिस 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करने को कहा था उसमें बिजली समझौतों को रद करने के वादे पर अमल करना भी एक था।



राज्य को बिजली संकट से उबारने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करने चाहिए। फाइल

**संभवतया चौतरफा दबाव का नतीजा है कि बिजली समझौतों को रद करने का निर्देश मुख्यमंत्री को देना पड़ा है**

सिद्धू ने जब प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो भी मंच से उन्होंने इसका जिक्र किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में एक मांग यह भी थी। संभवतया इसी चौतरफा दबाव का नतीजा है कि इन समझौतों को रद करने का निर्देश मुख्यमंत्री को देना पड़ा है। कुछ समय पहले उन्होंने यह कहा था कि इन पर कानूनी राय ली जा रही है। अतः यह उम्मीद की जाती है कि सरकार ने तमाम कानूनी पक्षों पर राय लेकर ही अब यह निर्देश दिया होगा। अब देखना है कि पीपीसीएल कब इन समझौतों को रद करता है और उन्हें रद करने के पीछे क्या कारण बताए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश

# अपात्रों को सम्मान निधि

उत्तर प्रदेश में सात लाख से अधिक अपात्र किसानों को करीब दो साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते आना पूरे तंत्र की बड़ी नाकामी है। ये वो किसान हैं, जो लघु या सीमांत नहीं होने के कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आते। इनमें करीब सवा दो लाख लोग आयकरदाता होने के कारण सम्मान निधि लेने के हकदार नहीं हैं। कृषि विभाग के सत्यापन से पता लगा कि 3.86 लाख ऐसे किसानों को भी निधि भेजी जा रही है, जिनके खाते गलत हैं अथवा खाते से लिंक आधार फर्जी है। यह हकीकत प्रथम वर्ष के मात्र पांच प्रतिशत और दूसरे वर्ष के 10 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन करने से उजागर हुई है। प्रदेश के समस्त 16.48 करोड़ लाभार्थियों की जांच से अपात्रों का आंकड़ा कहां पर जाकर ठहरेगा, कहना कठिन है। दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी, 2019 से लघु व सीमांत किसानों के खाते में हर चार महीने में दो हजार रुपये (सालाना कुल छह हजार रुपये) भेजना शुरू किया था। इन्हें एक से लेकर आठ किस्तें दी जा चुकी हैं। योजना के दो साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार और आयकर विभाग से लिंक कराया तो गड़बड़ी का जिन्न बाहर आया।



लघु व सीमांत किसानों के लिए मददगार बन रही पीएम सम्मान निधि। फाइल

**कृषि विभाग को तत्काल ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे लोग बगैर किसी परेशानी के स्वत : सम्मान निधि लौटा सकें। इसके लिए बैंक खाता नंबर भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए**

अपात्रों के खाते में दो साल से किसान सम्मान निधि अगर पहुंच रही थी तो इसके लिए सीधे तौरपर कृषि विभाग के अधिकारी ही जिम्मेदार माने जाने चाहिए। यह उन्हें ही देखना था कि एक भी अपात्र किसान को यह राशि न पहुंचने पाए। बावजूद इसके गलत खातों या फर्जी आधार वाले लोगों को भी किस्त भेजते रहना समूची व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बेहतर यही होता कि लाभार्थियों को मानकों की कसौटी पर पहले ही कस लिया जाता। इससे किसानों की परेशानी बचती ही, रकम वापसी के लिए समूचे तंत्र को भी नहीं लगाना पड़ता। अब कृषि विभाग को तत्काल ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे लोग बगैर किसी परेशानी के स्वतः सम्मान निधि लौटा सकें। इसके लिए बैंक खाता नंबर भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

बंगाल

# वामपंथियों की दोहरी परेशानी

34 वर्षों तक शासन करने वाले राज्य में ही वामपंथी अप्रासंगिक हो जाएंगे, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बंगाल में इन दिनों माकपा नेतृत्व वाले वाममोर्चा की हालत दयनीय है। वाममोर्चा ने पहले जिस कांग्रेस के खिलाफ 2011 तक लड़ाई लड़ी उसी के साथ 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया। अब हालात यह है कि अपने खत्म हो रहे अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा विरोध के नाम पर किसी भी दल यहां तक कि धुर विरोधी तृणमूल कांग्रेस के साथ भी वह हाथ मिलाने के लिए तैयार है। वामपंथियों के लिए बंगाल में दोहरी परेशानी है। एक तरफ कांग्रेस की तृणमूल से बढ़ती नजदीकी है तो दूसरी ओर समाप्त हो चुका जनाधार है। ऐसे में माकपा किस ओर जाए इसे लेकर परेशान है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के बाद अपने रुख में बदलाव करते हुए माकपा ने संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है।

**वामपंथियों के लिए बंगाल में दोहरी परेशानी है। एक तरफ कांग्रेस की तृणमूल से बढ़ती नजदीकी है तो दूसरी ओर समाप्त हो चुका जनाधार है। ऐसे में माकपा किस ओर जाए इसे लेकर परेशान है**

सत्तर सालों में पहली बार है जब बंगाल विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों का एक भी सदस्य जीत कर नहीं सदन नहीं पहुंचा है। माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) ने एक मोर्चा बनाया था और विधानसभा चुनाव लड़ा था। इन पार्टियों ने घोषणा की थी कि तृणमूल और भाजपा दोनों ही उनके प्रमुख दुश्मन हैं। पर बुरी तरह हार हुई। वाम दल की तरह कांग्रेस भी राज्य विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई है। बंगाल में कांग्रेस भी अस्तित्व संकट की लड़ाई लड़ रही है। यदि प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दिया जाए तो इस समय बंगाल में कांग्रेस के लिए जनाधार वाले नेताओं का घोर अकाल है। कुछ नेता थे भी तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस तोड़ चुकी है। इसके बावजूद कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को बेकरार है। ऐसे में वाममपंथियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि वामपंथी दलों के नेता परेशान हैं।

इसी के मद्देनजर जब माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य व वाममोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस से पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए माकपा तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाएगी? इस पर उनका जवाब था कि हम किसी भी भाजपा विरोधी पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसे मजबूरी नहीं तो और क्या कहा जाएगा? क्योंकि बंगाल में अब भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है।

## शिव : महाकाल और भोले भंडारी

देवाधिदेव महादेव सृष्टि के सर्वशक्तिमान देव हैं। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय है। एक ओर वह संहार के देव हैं, तो दूसरी ओर स्वयं में पूर्ण आरोग्य और अमरत्व के आशीर्वाद की शक्ति भी धारण करते हैं। वह अघोरियों के साथ भस्मीभूत होकर श्मशान में तांडव करने वाले महाकाल हैं तो गृहस्थों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद स्वरूप उन्हें झटपट तथास्तु कहने वाले आशुतोष भी। श्रावण के दौरान वह हरिद्वार में ही विराजकर तीनों लोक की व्यवस्था संभालते हैं। इसीलिए श्रावण में हरिद्वार में रुद्राभिषेक करने वाले को भगवान शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। श्रावण शिवरात्रि को भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए इस दिन गंगाजल से शिव के अभिषेक का अलग ही महत्व है। शिव ने कंठ में विष धारण करने से उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए हरिद्वार स्थित गंगा की धारा में स्नान किया। इससे उस स्थान पर गंगा की धारा नीली पड़ गई थी, जिसे अब नीलधारा नाम से जाना जाता है। श्रावण में हरिद्वार से गंगाजल ले जाकर अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानों पर रुद्राभिषेक करने की परंपरा की एक शुरुआत इसे भी माना जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस माह शिव भक्त हरिद्वार आते हैं और पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ यहां शिवालय और मठ-मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। करुणा के सागर भोले भंडारी अपने भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं।



अनंत श्रीविभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ
पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री भूमा निकेतन, हरिद्वार

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

# नीति आयोग की रिपोर्ट में कई मानकों पर सबसे पिछड़ा बिहार

- जदयू सांसद के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने दी जानकारी
- विशेष राज्य का दर्जा देने की बात परोक्ष रूप से की खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) के मानकों पर बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है। वहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में भी यह स्पष्ट कर दिया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अब विशेष राज्य और सामान्य राज्य को मिलने वाले टैक्स शेयर के बंटवारे में कोई फर्क नहीं रह गया है। लिहाजा बिहार को केंद्र के राजस्व में अब 32 की बजाय 42 फीसद हिस्सा मिल रहा है। योजनाओं को लागू करने के लिए यह ज्यादा माकूल स्थिति है।

नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले राज्यों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसी आधार पर राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को संसद में केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और क्या केंद्र सरकार उसे विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इस पर सांख्यिकी विभाग के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट में बिहार सौ में 52 के आंकड़े पर खड़ा है। यह सभी राज्यों में निम्नतम है। यह आंकड़ा सतत विकास लक्ष्य के 16 मानकों पर 115 संकेतकों (इंडिकेटर) के आधार पर तय किया जाता है। बता दें कि कुछ मानकों पर बिहार ऊपर है, जैसे पेयजल। लेकिन कुल अंक बिहार के निम्नतम हैं। नीचे आने का बड़ा कारण गरीबों की बड़ी संख्या है। लगभग 33.74 फीसद लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। स्वास्थ्य बीमे के दायरे में सिर्फ 12.3 फीसद लोग हैं। पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में विकास अवरुद्ध है। साक्षरता की बात हो तो 15 से ऊपर के आयुवर्ग में यह 64.7 फीसद है। सेकेंडरी लेवल स्कूलों में छात्र-शिक्षक का राष्ट्रीय अनुपात 21 है, लेकिन बिहार में यह 58 है। मोबाइल टेली डेंसिटी और इंटरनेट उपभोक्ता के मामले में भी बिहार पिछड़ा हुआ है।



राजीव रंजन सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। फाइल

# उत्तर प्रदेश में ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से छिने आरक्षण का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के निवासी और विभिन्न संगठन चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बन रहा कानून और सख्त हो। उसका दायरा और बड़ा किया जाए। इस बात के गवाह राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव हैं। आयोग को भेजे गए करीब 8,500 सुझावों में अधिकांश ने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर मताधिकार छीनने की सिफारिशें की हैं। बहुत से लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव (नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक) के साथ ही एमपी और एमएलए के चुनाव को भी इसके दायरे में लाने की पैरवी की है। हालांकि कई सुझाव ऐसे हैं, जिन पर आयोग अपने स्तर से अमल नहीं कर सकता। इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। फिलहाल, आयोग सुझावों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर मंथन कर रहा है। विधिक पहलुओं को भी गहराई से देखा जा रहा है। आयोग अगस्त माह के दूसरे सप्ताह तक उप्र जनसंख्यक (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप सौंपने की तैयारी में है।

राज्य विधि आयोग ने उप्र जनसंख्यक (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। आयोग ने सुझाव देने की समय सीमा 19 जुलाई तय की थी। इस अवधि तक आयोग को करीब 8500 सुझाव मिले हैं।

इनमें कई सुझाव एक जैसे भी हैं। आयोग को भेजे गए सुझावों में कई लोगों ने दो के स्थान पर अधिकतम तीन बच्चों के लिए कानून बनाए जाने की बात भी कही है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस कानून को पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था।

### मशविरा

- मताधिकार से वंचित करने की भी सिफारिश, एमपी-एमएलए पर भी लगे प्रतिबंध
- उप्र में अगस्त के दूसरे सप्ताह तक शासन को विधेयक का प्रारूप सौंपने की तैयारी

### आठ हजार से अधिक जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। हालांकि सूबे की आबादी को देखते हुए इस कानून को लेकर अपने सुझाव देने वालों की संख्या बेहद सीमित रही है। आयोग को मिले करीब 8500 सुझावों में आठ हजार से अधिक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। वहीं करीब 300 मेल इस कानून के विरोध में भी आए हैं।

### यह भी अहम सुझाव

- दो बच्चे ही पैदा करने वाले मुस्लिम परिवार को कराई जाए मुफ्त हज यात्रा।
- एक बच्चा ही पैदा करने वाले सभी परिवारों को मिले अतिरिक्त लाभ।
- दो बच्चों के बजाए तीन बच्चों पर लागू हो कानून।
- दो बेटियां होने पर मिले तीसरे बच्चे की छूट।
- दो में से एक बच्चे के दिव्यांग होने पर मिले तीसरे बच्चे की छूट।

इसमें देर हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में खड़े हुए लोगों ने कानून तोड़ने वालों को राशन तक न दिए जाने की सिफारिश की है। आयोग अब सभी सुझावों के व्यावहारिक, विधिक व सामाजिक पहलुओं का भी अध्यन कर रहा है। कौन से सुझाव कितने प्रतिशत लोगों ने दिया है, इसे भी श्रेणीवार देखा जा रहा है।

बताया गया कि 50 से अधिक प्रकार के सुझाव आए हैं। अलग-अलग सुझावों के साथ उनके प्रतिशत तथा उन पर आयोग की टिप्पणी की तालिका भी बनाई जा रही है ताकि उसे भी प्रारूप का हिस्सा बनाया जा सके। आयोग प्रारूप शासन को सौंपेगा, जिसके बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी।

# कार्ययोजना तैयार, आधुनिक स्थापत्य कला के होंगे दर्शन

- राम मंदिर के अलावा अन्य प्रखंडों के निर्माण में प्रयुक्त होगी नई तकनीक

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

रामजन्मभूमि परिसर में भव्य राममंदिर के अलावा अन्य कई प्रकल्प भी आकार लेंगे। लोग यहां भारत की आधुनिकतम स्थापत्य कला की शैली के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल, राम मंदिर परिसर को दो हिस्सों में बांट कर निर्माण की कार्ययोजना बनी है। पहला पार्ट ए, जिसमें राम मंदिर है। पार्ट बी में अन्य प्रकल्प हैं। पार्ट ए जहां परंपरागत शैली में निर्मित किया जा रहा है तो पार्ट बी आधुनिक टेक्नोलाजी से निर्मित होगा।

गत दिनों रामनगरी में हुई मंदिर निर्माण समिति की बैठक में अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने विस्तारित एरिया में निर्मित होने वालों भवनों का निर्माण नई तकनीक से करने पर जोर दिया। इसकी सलाह इंजीनियरों को दी। पार्ट ए पांच एकड़ में व पार्ट बी 68 एकड़ में निर्मित होगा। पार्ट बी की डिजाइन तैयार की जा रही है। निर्माण के लिए नए सिरे से कार्यदायी संस्था भी निर्धारित की जाएगी।

**परिसर में ये भवन निर्मित होंगे :** पांच एकड़ में राममंदिर बनेगा। 65 एकड़ को कल्चरल कैपिटल आफ दि वर्ल्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। रामजन्मभूमि परिसर का सिंह द्वार पर दीप स्तंभ रोशन होंगे। श्रीराम कुंड के नाम से यज्ञशाला, कर्मक्षेत्र के नाम से अनुष्ठान मंडप, वीर मारुति के नाम से हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी परिसर में श्री रामलला पुराकालिक दर्शन मंडल की स्थापना की जाएगी। पुराकालिक दर्शन मंडल में रामजन्मभूमि के उत्खनन में प्राप्त शिलालेख व पुरावशेषों का संरक्षण होना है। एक अन्य प्रकल्प गुरु वशिष्ठ पीठिका है, जिसमें वेद, पुराण, रामायण व संस्कृत अध्ययन-अनुसंधान का क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान एवं मनन निकुंज के रूप में भक्ति टीला का विकास किया जाएगा। यहां रामलीला केंद्र होगा। इसी में 360 डिग्री का थिएटर बनेगा। माता कौशल्या वात्सल्य मंडप नाम का प्रदर्शनी कक्ष एवं झांकियों का परिसर आकार लेगा।




# जमीन कौन खरीदेगा यह जाति से तय होगा!

- जम्मू कश्मीर में महाजन, खत्री और सिख नहीं खरीद सकते कृषि भूमि
- महाराजा के समय से इस कानून में लिखा है, इन जातियों का खेती से लेनादेना नहीं

ललित कुमार, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म हुए दो साल बीत रहे हैं पर अधिकारी अभी भी पुरानी व्यवस्था को ढोह रहे हैं। यहां तक की किसी के काम का निर्धारण उसकी जाति से किया जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में आज भी महाजन, खत्री बिरादरी के अलावा सिख समुदाय को कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है और यह दावा किया जा रहा है कि इन तीनों का खेती से कोई लेनादेना नहीं है।

अनुच्छेद-370 और 35ए खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद के लिए नए नियम बनाए गए। कृषि भूमि किसानों के हाथ में ही रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में प्रावधान रखा गया। 26 अक्टूबर, 2020 को लागू नए कानून में यह साफ कर दिया गया कि खेती से जुड़े लोग ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं और अन्य नहीं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि खेती की जमीन का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही होगा।

उस समय कानून तो बना दिया गया पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कृषक की पहचान कैसे होगी और किसे कृषि भूमि खरीदने का अधिकार होगा। लगभग दस माह बाद भी यह नियम स्पष्ट नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मर्जी से नियम लागू कर दिए। इन नियमों के तहत महाजन, खत्री और सिख कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पूर्वज खेती नहीं करते थे।

**जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व कानून है जड़ :** महाराजा के समय से जम्मू-कश्मीर में भूमि राजस्व कानून में यह स्पष्ट था कि केवल किसान ही कृषि जमीन खरीद सकते हैं। चूंकि तब महाजन, खत्री व सिखों का कृषि से कोई लेनादेना नहीं था। बाद में भी यह कानून लागू रहा पर खेती की जमीन की खरीद-फरोख्त होती रही। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद नया कानून लागू हुआ और इसमें फिर उसी शर्त का उल्लेख है। क्योंकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं था कि किसान की परिभाषा क्या होगी, ऐसे में महाराजा के समय की परिभाषा अधिकारी लागू किए जा रहे हैं।

**कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में नहीं खरीद सकते मकान :** वर्तमान शहर के कई क्षेत्र व अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले खेत ही होते थे। आज वहां दशकों से बस्तियां बसी हैं। अब इन इलाकों में महाजन, खत्री व सिख परिवार मकान नहीं खरीद पा रहे। तर्क यह कि राजस्व रिकार्ड में आज भी यह कृषि भूमि है।

नए जमीन कानून के तहत एक बोर्ड गठित होना था, जिसने तय करना था कि कृषि भूमि कौन खरीद सकता है और कौन नहीं। यह बोर्ड अभी तक गठित नहीं हुआ। इसलिए कुछ इलाकों में राजस्व अधिकारी पुराने कानून को आधार बनाकर काम कर रहे हैं।
**- जसमीत सिंह, रजिस्ट्रार, जम्मू**

नए भूमि कानून में कहा गया है कि जो लोग खेती-बाड़ी से नहीं जुड़े, वे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। यह भी सही है कि पुराने कानून में महाजन, खत्री व सिख समुदाय के बारे में कहा गया था कि ये लोग कृषि से नहीं जुड़े, लिहाजा ये कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। अब हमारे पास जो भी आ रहा है, हम उसका पुराना रिकार्ड चेक करके कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वह या उसका परिवार कृषि से जुड़ा है तो वो जमीन खरीद सकता है।
**- अभिषेक कुमार, उप-जिलाधीश, जम्मू दक्षिण**

आज हमारी बिरादरी का कोई व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में मकान खरीदने जाता है तो उसके नाम रजिस्ट्री नहीं होती। पिछले एक साल में ऐसे दर्जनों केस हमारे पास आए हैं। हमने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर जाति आधारित यह भेदभाव समाप्त करने की अपील भी की थी।
**- रमेश महाजन, प्रधान जम्मू सेंट्रल महाजन सभा**

# 'सहमति से शारीरिक संबंध बनाने पर अकेले पुरुष दोषी नहीं'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी के बहाने से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए सिर्फ पुरुष दोषी नहीं है। जस्टिस सुदीप अहलूवालिया ने इस मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रविधानों के तहत दर्ज करने पर भी सवाल उठाया और आरोपित पुरुष को जमानत दे दी।

पेश मामले में आरोपित के खिलाफ कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन पुलिस थाने में गत 17 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पुरुष ने महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उसने महिला से शादी किया वादा था, क्योंकि उसके पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे। एक कालम में पता चला कि महिला का जन्म 1991 का था।

इस तरह, उसने बहुत पहले वयस्क होने की आयु पार कर ली थी। कोर्ट के अनुसार यह दो पक्षों के बीच सहमति से यौन संबंध का मामला प्रतीत होता है और दोनों के बीच विवाह कम से कम तब तक संभव नहीं था, जब तक कि शिकायतकर्ता की पहली शादी समाप्त नहीं होती। कानूनन अब तक उसकी पहली शादी चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में पुरुष को पूरी तरह दोषी नहीं माना जा सकता है, भले ही उसके खिलाफ आरोप लगे हों। कोर्ट ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एफआइआर में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि पुरुष ने अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण महिला का अपमान किया या उसे पीड़ित किया। ऐसे में एससी एसटी अधिनियम जोड़ना आश्चर्य से कम नहीं है।

हाई कोर्ट ने आरोपित को नियमित जमानत देने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। साथ ही, ट्रायल कोर्ट को सलाह दी कि वह हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर मामले का निपटारा करे।

### हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

- एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने पर उठाया सवाल
- हाई कोर्ट ने आरोपित को जमानत के साथ किया याचिका का निपटारा

# अमेरिका के अलास्का में 8.2 रिक्टर स्केल का आया भूकंप



अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके के साथ सुनामी का अलर्ट जारी होने के बाद होमर में लोगों ने वाहनों से सुरक्षित स्थानों को पलायन करना शुरू कर दिया। इस दौरान वाहनों की कतार नजर आई। एपी

पेरीविले, एपी: अमेरिका के बर्फीले अलास्का प्रायद्वीप में गुरुवार को 8.2 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने के साथ ही कई झटके महसूस किए गए। इसके बाद अमेरिका के पेसिफिक वार्निंग सेंटर ने हवाई के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया जिसे बाद में वापस ले लिया। हालांकि अलास्का के कई इलाकों में छोटी सुनामी की समुद्री हिलोरें देखी गई हैं।

यूएस जियोलाजिकल सर्वे के मुताबिक अलास्का के दक्षिण-पूर्व में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.2 दर्ज की गई। हालांकि होनोलुलु स्टार एडवेटाइजर के मुताबिक, पैसेफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता पर 8.1 ही बताई है। पेरीविले में समुद्र की सतह से 46.7 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र है। भूकंप को सतह पर 91 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में बेहद तीव्रता से महसूस किया गया।

यूएस जियोलाजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, आधे घंटे के अंतर पर दो और भूकंप के झटके लगे। पहला वाला 6.2 रिक्टर स्केल और दूसरा वाला 5.6 रिक्टर स्केल का था।

इसके बाद पैसेफिक वार्निंग सेंटर के सुनामी की चेतावनी वापस लेने के बावजूद अलास्का में छोटी सुनामी की लहरें उठीं जिनकी ऊंचाई एक फुट से ज्यादा नहीं थी। छोटी सुनामी लहरों को सैंड प्वाइंट, ओल्ड हार्बर, किंग कोव, कोडियक, अनअलास्का और अलिटक बे में देखा गया।

भूकंप या छोटी सुनामी से क्षेत्र में जानमाल की क्षति की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अमेरिकी राज्य कैलीफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन के अलावा कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में सुनामी का कोई खतरा फिलहाल नहीं है।

## आस्ट्रेलिया लौटा रहा भारत की चुराई कलाकृतियां

केनबरा, एएनआइ : आस्ट्रेलिया के नेशनल आर्ट म्यूजियम में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी हो रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग और कुछ तस्वीरें शामिल हैं। 1989-2009 के बीच ये आर्टवर्क नेशनल म्यूजियम के अधिकार में शामिल किए गए। ये सभी आर्टवर्क कलाकृतियों की स्मगलिंग करने वाले डीलर सुभाष कपूर से लिए गए थे। यह जानकारी सिडनी मार्निंग हेराल्ड की ओर से दी गई।

आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत वोरा ने कहा, 'आस्ट्रेलिया के इस फैसले के लिए भारत सरकार आभारी है।' इससे पहले 2014 में म्यूजियम की ओर से 50 लाख डालर मूल्य वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। पीतल की इस मूर्ति को पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था। भारत सरकार को जो आर्टवर्क दिए जाएंगे उनकी कीमत 30 लाख डालर है। म्यूजियम के मुताबिक, ये सभी कलाकृतियां चोरी के बाद तस्करी के जरिये यहां पहुंचीं हैं। कपूर से खरीदे गए आर्टवर्क को चौथी बार आस्ट्रेलिया द्वारा दिया जा रहा है।

# तनाव के बीच अमेरिका और रूस में टकराव के मुद्दों पर बातचीत

- हथियार नियंत्रण व अन्य रणनीतिक मुद्दों पर आगे बढ़ी बातचीत
- दोनों देशों के उप विदेश मंत्रियों ने परणाणु खतरों पर भी किया विचार



अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस। एएफपी

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका की रूस से रैंसमवेयर व अन्य मुद्दों पर बेशक तनाव की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर वार्ता का भी दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन पर हमले के बीच दोनों देशों के उप-विदेश मंत्रियों के स्तर पर कई मुद्दों पर वार्ता हुई। यह वार्ता परमाणु हथियारों के नियंत्रण से लेकर रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित रही।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम हमेशा हथियारों के नियंत्रण और परमाणु खतरों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेशक विभिन्न मुद्दों को लेकर तनाव क्यों न बढ़ा हुआ हो। हर मुद्दे का हल वार्ता है। उन्होंने बताया कि जेनेवा में दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी, इसी क्रम में उन्हीं मुद्दों पर अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेर्मन और रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने वार्ता की है।

उल्लेखनीय है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब रूस आर्कटिक में सैन्य शक्ति बढ़ाकर नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसमें परमाणु रिएक्टर से संचालित मानवरहित स्टील्थ टारपीडो भी शामिल है। रैंसमवेयर हमले, यूक्रेन विवाद के कारण दोनों देशों में पहले से ही तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2022 में होने वाले प्रतिनिधि सभा और राज्य चुनावों को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर लगाया है।

### अमेरिका रूस का प्रतिद्वंद्वी, भागीदार नहीं

आइएएनएस के अनुसार रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने हाल ही में अमेरिकी नेताओं के बयान और चल रहे वार्ता के दौर में स्पष्ट किया कि वर्तमान में रूस के अमेरिका के साथ साझेदारी में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, न ही कोई विशेष संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अमेरिका को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, पार्टनर के रूप में नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थितियों में भी राष्ट्रपति पुतिन सकारात्मक वार्ता में विश्वास रखते हैं। रूसी प्रवक्ता के बयानों में अमेरिकी नेताओं की तीखी बयानबाजी का प्रभाव स्पष्ट रूप दिखाई दिया।

## तनाव के बीच चीन के अमेरिका में नए राजदूत



अमेरिका में चीन के नए राजदूत किन गैंग। फाइल फोटो/एएफपी

बीजिंग, एपी : चीन ने अमेरिका में अपने नए राजदूत की नियुक्ति की है। कई मुद्दों पर टकराव के हालात में नियुक्त हुए नए राजदूत किन गैंग ने कहा कि अमेरिका और चीन आपसी समन्वय के साथ खोज और समझ के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस नए युग में एक दूसरे साथ आने का रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि किन गैंग अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस अवसर पर सधे बयान दिए। किन गैंग चीन के नौ उप-मंत्रियों में से एक हैं। अब तक वह विदेशी मामलों को देख रहे थे। उनका आगमन ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका के चीन के साथ संबंध दशकों में सबसे निचले स्तर पर हैं। साइबर सुरक्षा, प्रोद्यौगिकी, मानवाधिकार और चीन की आक्रामक विदेश नीति के कारण टकराव बना हुआ है। फिलहाल अमेरिका का चीन में भी कोई राजदूत नहीं है। माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन नाटो के पूर्व राजदूत निकोलस बर्न को चीन का राजदूत नियुक्त कर सकते हैं।

# मध्य एशियाई देशों की अफगान सीमा पर तैनात हुए रूस के लड़ाकू विमान

**अफगान संकट** ▶ सेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमले तेज किए

### 23 आतंकियों को मार गिराया, प्रांतीय राजधानी से दूर खदेड़ा

मास्को, रायटर : अफगानिस्तान में जारी जंग के दौरान मध्य एशिया के देशों की सीमाओं पर सेना सतर्क हो गई है। इन देशों में रूस की सक्रियता बढ़ गई है। ताजिकिस्तान की सीमा पर टैंक तैनात करने के बाद अब रूस के लड़ाकू विमान भी यहां युद्धाभ्यास करेंगे। इधर अफगान सेना ने तालिबान के कई ठिकानों पर हमले किए। इस कार्रवाई में 23 आतंकियों को ढेर कर दिया गया।

अफगानिस्तान में तालिबान का तेजी से कब्जा होने के बाद अब पड़ोसी देश सतर्क हो गए हैं। मध्य एशिया के देश, विशेषकर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। यहां रूस ने अफगान सीमा से लगे ताजिकिस्तान क्षेत्र में पहले अपने सैनिक और टैंक तैनात किए थे, अब हवाई ताकत भी बढ़ा दी है। 10 अगस्त तक अफगान सीमा पर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के सहयोग से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस ने यहां सुखोई-25 विमानों को तैनात किया है। रूस मध्य एशियाई देशों को अफगान समस्या के मामले में सुरक्षा की पूरी गारंटी देना चाहता है, जिससे अमेरिका को यहां सैन्य अड्डा बनाने में सफलता न मिल सके।

### तालिबान नियंत्रित कामदीश घाटी में बाढ़, 150 लोग मरे

काबुल, एपी : अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाले नूरिस्तान प्रांत की कामदीश घाटी में अचानक आई बाढ़ से 150 लोगों की मौत हो गई। सौ से ज्यादा घर गिर गए। यहां खराब संचार व्यवस्था के कारण राहत कार्य में भी मुश्किल हो रही है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि मानवीय एजेंसियों को क्षेत्र में राहत कार्य के लिए प्रवेश करने देंगे। हमारे लोग क्षेत्र में सहायता कार्य में लग गए हैं। इधर काबुल में सरकारी प्रवक्ता ने तालिबान से अपील की है कि वह राहत दल को क्षेत्र में काम करने दे। इस क्षेत्र में नागरिक जारी युद्ध और कोरोना महामारी के साथ अब बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण सहायता करना एक चुनौती है। पिछले महीने हेरात के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ के कारण यहां 12 लोगों की मौत हो गई थी।

### पाकिस्तानी पीएम इमरान का शर्मनाक बयान, तालिबान सैन्य संगठन नहीं, सामान्य नागरिक



इमरान खान। फाइल फोटो

**आतंकियों के प्रति पाक प्रधानमंत्री ने जताई हमदर्दी**

वाशिंगटन, एएनआइः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकियों के समर्थन में खुल कर सामने आ गए हैं। उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया, 'तालिबान कोई सैन्य संगठन नहीं, वे सामान्य नागरिक हैं।'

इमरान ने एक साक्षात्कार में कहा, उनके देश को आतंकियों का अभयारण्य बताया जाता है। यहां तीस लाख पश्तून शरणार्थी हैं। तालिबान भी उसी तरह की ही जाति है। बताइए फिर आप कैसे पहचान कर कार्रवाई करेंगे। इमरान ने कहा, उन पर लंबे समय से आतंकियों को संरक्षण देने और फंडिंग का आरोप लग रहा है। यह पूरी तरह गलत है।

उन्होंने कहा, अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 के हमले के बाद अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हजारों पाकिस्तानी मारे गए। उनका क्या दोष था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पांच हजार आतंकी तालिबान के साथ अफगान सेना के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। इधर प्रेट्र के अनुसार इमरान ने एक अन्य बयान में कहा है कि वह तालिबान के प्रवक्ता नहीं हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उससे उनकी सरकार का कोई वास्ता नहीं।

इधर आइएएनएस के अनुसार, फरयाब प्रांत के पश्तूनकोट और अलमार जिलों में तालिबान के ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए गए। हथियार, गोलाबारूद नष्ट करने के साथ ही यहां 23 तालिबान आतंकियों को मार दिया गया। तालिबान यहां फरयाब प्रांत की राजधानी मेयमना को लेकर भी संघर्ष कर रहा है। तालुकान शहर पर कब्जे को लेकर भी युद्ध चल रहा है।

**तालिबान ने माना, अफगान हास्य कलाकार को उसने मारा :** एपी के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्वीकार किया है कि हास्य कलाकार नजर मोहम्मद जिन्हें खाशा ज्वान के नाम से जाना जाता है, उनकी हत्या तालिबान ने ही की है। उनका पूर्व में दो लोगों के पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।

# अमेरिका में फिर लगने लगे मास्क, वैक्सीन पर पूरा जोर

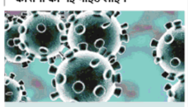
**न्यूयार्क टाइम्स से**

- न्यूयार्क में पहली वैक्सीन खुराक पर अब मिलेंगे 100 डालर
- सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी होगी कोरोना की नई गाइड लाइन

न्यूयार्क : अमेरिका में वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों के लिए भी मास्क की अनिवार्यता से अब माहौल तेजी से बदल गया है। लोगों के चेहरे से उतरे हुए मास्क फिर आ गए हैं। प्रशासन का पूरा जोर अब वैक्सीन लगाने पर है। बाइडन प्रशासन सरकारी कर्मियों के लिए इसी हफ्ते कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करेगा। न्यूयार्क में तो वैक्सीन का पहली खुराक लेने वालों को 100 डालर देने की घोषणा की गई है।

डेल्टा वैरिएंट के कारण अमेरिका में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दो माह पहले सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) ने मास्क लगाने से छूट दे दी थी। कई पाबंदियों को हटा लिया गया था। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में बहार लौट आई थी। लोग कोरोना को भूलने लगे थे और चेहरों से मास्क उतर गए थे। सीडीसी द्वारा इनडोर में मास्क पहनने की अनिवार्यता के बाद तस्वीर बदल गई है।

न्यूयार्क में रेस्तरां और बार में फिर एहतियात देखा गया। यहां के मेयर बिल डी ब्लेसिओ ने घोषणा की है कि जो भी नागरिक न्यूयार्क के वैक्सीन सेंटर में पहली खुराक लगवाएंगे, उन्हें 100 डालर (करीब 7426 रुपये) दिए जाएंगे। इधर बाइडन प्रशासन कोरोना संबंधी नई गाइड लाइन जारी करने जा रहा है। इसमें वैक्सीन की दोनों खुराक लेने, शारीरिक दूरी का पालन करने, नियमित जांच और मास्क लगाने की अनिवार्यता होगी। यात्रा के संबंध में भी नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। व्हाइट हाउस ने बताया कि हफ्ते के अंत तक योजना के बारे में जानकारी दे दी जाएगी।



**डेल्टा वैरिएंट 132 देशों में, हर रोज आ रहे 54 लाख नए केस :** एएनआइ के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार डेल्टा वैरिएंट 132 देशों में फैल चुका है। इसके कारण संक्रमण में तेजी आई है। कुछ सप्ताह पहले हर रोज वैश्विक स्तर पर औसतन 49 लाख नए मरीज आ रहे थे, लेकिन पिछले सप्ताह से अब यह संख्या औसतन 54 लाख पहुंच गई है।

**बैंकाक एयरपोर्ट पर 1800 बिस्तरों का अस्पताल :** एपी के अनुसार थाईलैंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बैंकाक एयरपोर्ट की कार्गो बिल्डिंग में 1800 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है।

**आस्ट्रेलिया :** सिडनी में चार सप्ताह का लाकडाउन लगाने के साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सेना तैनात कर दी गई है।

# भारत से आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ाना अमेरिका के हित में



डोनाल्ड लू। फाइल

**अमेरिकी उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा-दो महान लोकतंत्र होने के चलते हमें अपना उदाहरण पेश करना चाहिए**

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा है कि भारत के साथ तेजी से रणनीतिक, आर्थिक और लोगों से जुड़े संबंधों को प्रगाढ़ करना अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हित में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से दक्षिण और मध्य एशिया के लिए नामित वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने बुधवार को सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय में अपने तीस सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के लिए काम किया है।

उन्होंने सांसदों से कहा कि हिंद-प्रशांत महासागर शक्तियों के तौर पर एशियाई साझीदारों के तौर पर संप्रभुता और आजादी को प्रमुखता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तेजी से बढ़ती सामरिक, आर्थिक और जन नीतियों के आधार पर भारत से संबंध और मजबूत करना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए बेहद लाभदायक है। फिर अमेरिका भी मानवाधिकारों और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात करेगा। दो महान लोकतंत्र होने के चलते हमें अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। ताकि लोगों को पता चले कि लोकतंत्र से शांति, स्थिरता और निजी स्वतंत्रता को बढ़ावा क्यों मिलता है। उन्होंने कहा कि यह दोनों ही देश बड़े मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने राजनयिकों से उम्मीद करता हूं कि यह भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के संदर्भ में वह श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करना जारी रखेंगे।

## आर्मीनिया-अजरबैजान के बीच फिर युद्ध विराम

मास्को, रायटर : अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रहे युद्ध में जमकर गोलीबारी हुई। बाद में रूस के प्रस्ताव पर यहां युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिंयान ने रूस से अपनी सेना तैनात करने की मांग की है।

आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि अजेरी (अजरबैजान) सेना ने सीमा पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आर्मीनिया के तीन सैनिकों की मौत हो गई और चार घायल हुए हैं। हमलों के प्रतिकार के लिए पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की गई। बाद में रूस के प्रस्ताव पर युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है।

आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिंयान का आरोप है कि अजरबैजान सीमा पर निरंतर भड़काने की कार्रवाई कर रहा है, ऐसी स्थिति में रूस को दोनों देशों की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर मास्को से विचार करने के लिए कहा जाएगा।



## कुदरत का दिलकश नजारा

दुनियाभर में मौसम के पल-पल बदलते मिजाज के बीच कुदरत के अद्भुत नजारे देखने को मिल जाते हैं। इंग्लैंड के डंस्टेबल में स्थित एक पार्क में इंद्रधनुष के सामने गरजती बिजली के इस बेहद खूबसूरत दृश्य को लंदन के फोटोग्राफर इजी ब्रेट ने कैमरे में कैद किया है। इन दिनों यहां तेज हवाओं के साथ बरसात जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश में धूलभरी आंधियां चलने की चेतावनी भी जारी की है। साभार : गार्जियन

## अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ के कोविड स्रोत के पता लगाने का समर्थन किया

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख टेड्रास घेब्रयेसिस से कुवैत में मुलाकात की। उन्होंने कहा, अमेरिका कोविड-19 के मूल स्रोत पर संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था के चीन समेत सभी अतिरिक्त शोधों का पुनः समर्थन करता है। ब्लिंकन ने कहा, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रास से इस वैश्विक महामारी के खात्मे और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई है। कोविड-19 के मूल स्रोत का पता लगाने संबंधी पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना (पीआरसी) समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के अतिरिक्त शोधों से वह पूरी तरह से सहमत हैं। लैब-लीक थ्योरी ने इतना जोर पकड़ा कि बाइडन प्रशासन को खुफिया एजेंसियों को इसके स्रोत का पता लगाने का निर्देश देना पड़ा था। डब्ल्यूएचओ ने चीन में कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए शोध कराने का प्रस्ताव रखा था जिसे चीन ने खारिज कर दिया था।

# विदेशी छात्रों का पढ़ाई के बाद अमेरिका में रुकना होगा मुश्किल

**सुविधा पर संकट**

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 'आप्ट' प्रोग्राम के खिलाफ विधेयक पेश, अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की बढ़ सकती है मुसीबत

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में विदेशी छात्रों से जुड़ा एक विधेयक पेश किया है, जिससे भारतीय भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। यह विधेयक वैकल्पिक अभ्यास प्रशिक्षण (आप्ट) के खिलाफ पेश किया गया है। आप्ट के जरिये विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती थी।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सांसद पाल ए. गोसर के साथ सांसद मो ब्रूक्स, एंडी बिग्स और मैट गेट्ज ने फेयरनेस फार हाई-स्किल्ड अमेरिकन एक्ट पेश किया। इस विधेयकके पारित होने पर इसके जरिये वैकल्पिक अभ्यास प्रशिक्षण (आप्ट) के लिए इमिग्रेशन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम में संशोधन संभव हो पाएगा।

गोसर ने कहा कि कौन सा देश ऐसा कानून नहीं बल्कि कार्यक्रम बनाता है जो अपने व्यवसायों को अपने नागरिकों को निकालने और उनके स्थान पर विदेशी श्रमिकों को रखने के लिए पुरस्कृत करता है। अमेरिका के इस कार्यक्रम का नाम 'आप्ट' है और यह हमारे अपने श्रमिकों के पूर्ण परित्याग को दर्शाता है।



फाइल/इंटरनेट मीडिया

गोसर ने पहली बार 116वीं संसद में 'फेयरनेस फार हाई-स्किल्ड अमेरिकन एक्ट' पेश किया था। साथ ही आप्ट को खत्म करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के खिलाफ एक मुकदमे में अमेरिकी श्रमिकों के समर्थन में दो बार उन्होंने 'एमिकस ब्रीफ' पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 'एमिकस ब्रीफ' एक कानूनी दस्तावेज है, जिसे किसी अदालती मामले में उन लोगों द्वारा दायर किया जा सकता है, जो मामले में वादी नहीं होते, लेकिन इसमें रुचि रखते हैं। गोसर ने आरोप लगाया कि आप्ट ने एक लाख से अधिक विदेशी छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में तीन साल तक काम करने की अनुमति देकर एच-1बी सीमा के नियम को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि इन विदेशी श्रमिकों को पेरोल करों से छूट दी गई है, जिससे उनका खर्चा एक अमेरिकी मजदूर की तुलना में करीब 10 से 15 प्रतिशत कम हो जाता है। आप्ट 'यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट' (आइसीई) द्वारा प्रशासित एक अतिथि श्रमिक कार्यक्रम है।

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ने जाते हैं। इस वजह से अगर इस विधेयक को मंजूर कर लिया जाता है तो आने वाले वक्त में अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोरोना से पहले तक अमेरिका में एक लाख से अधिक संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे। मगर महामारी की शुरुआत होने के बाद से ही इस संख्या में कमी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका पढ़ाई करने जाने की योजना बनाते हैं। ऐसे में उन्हें आने वाले समय में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने में कठिनाई हो सकती है।

# भारत ने आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिशें हमेशा रोकीं : तिरुमूर्ति

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि उनके देश ने आतंकवाद से लड़ने और इस संकट पर ध्यान को 'कमजोर' करने की कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद के अंदर और बाहर लगातार इस पर जोर दिया है। भारत को अगले महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान आइएसआइएल पर महासचिव की रिपोर्ट से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित करने हैं।

भारत एक अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। यह सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत अगले साल दिसंबर में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।

तिरुमूर्ति ने एक इंटरव्यू में कहा, 'भारत परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है। हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को न केवल मजबूत किया है खासतौर से आतंकवाद के वित्त पोषण को बल्कि हमने आतंकवाद पर ध्यान को कमजोर करने की कोशिशों को भी रोका है।'

अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा, आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा। इस साल की शुरुआत में भारत ने कहा था कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत पर महासचिव की रिपोर्ट में आइएसआइएल व अलकायदा के तहत आने वाले लश्कर-ए-तैयबा और अन्य पाकिस्तानी आतंकी समूह भी शामिल होनी चाहिए।

# मेरी की हार से उठे अंपायरिंग पर सवाल

## तीन में से दो राउंड जीतने के बावजूद प्री-क्वार्टर फाइनल में हारीं मेरी कोम

**टोक्यो, प्रेट्र :** जीतने के बाद भी कोई खिलाड़ी हारता है, सुनने में अजीब लगता है ना। लेकिन ऐसा हुआ है और यह भारत की ओलिंपिक की पदक की दावेदार मुक्केबाज एमसी मेरी कोम के साथ हुआ है। मेरी तीन राउंड में से दो राउंड जीतने के बाद भी प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गईं जिसके बाद अंपायरों पर सवाल उठने लगे हैं।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी (51 किग्रा) का दूसरा ओलिंपिक पदक जीतने का सपना प्री-क्वार्टर फाइनल में रियो ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता इंग्रिट लोरेन वेलेंसिया से 2-3 से हारकर समाप्त हो गया। संभावना है कि यह मेरी का आखिरी ओलिंपिक है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के नियमों के अनुसार, 40 साल से ज्यादा के मुक्केबाज ओलिंपिक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और मणिपुर की यह मुक्केबाज अभी 38 साल की है जबकि अगले ओलिंपिक 2024 पेरिस में होने हैं।

**पहले राउंड में पिछड़ी मेरी कोम :** भारतीय मुक्केबाज पहले राउंड में 1-4 से पिछड़ गईं

**पांच जजों का फाइनल नतीजा**

| जज | वेलेंसिया | मेरी कोम |
|---|---|---|
| जज-1 | 30 | 27 |
| जज-2 | 29 | 28 |
| जज-3 | 27 | 30 |
| जज-4 | 29 | 28 |
| जज-5 | 28 | 29 |

जिसमें पांच में से चार जज ने 10-9 के स्कोर से वेलेंसिया के पक्ष में फैसला किया। अगले दो राउंड में पांच में से तीन जजों ने मेरी कोम के पक्ष में फैसला किया लेकिन, कुल स्कोर फिर भी वेलेंसिया के हक में रहा। ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता मेरी कोम ने इस चुनौतीपूर्ण मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया लेकिन, वह आगे नहीं बढ़ सकी जो 38 वर्षीय महान मुक्केबाज का अंतिम ओलिंपिक मुकाबला होगा।

**हार के बाद आंखों में थे आंसू :** जब रेफरी ने मुकाबले के अंत में वेलेसिया का हाथ उठाया तो मेरी की आंखों में आंसू थे। शुरू से ही दोनों मुक्केबाज एक-दूसरे पर मुक्के जड़ रही थीं लेकिन, वेलेंसिया अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पिछली दो हार का बदला चुकता करने के लिए विश्वास से भरी दिख रही थीं। मेरी ने दूसरे और तीसरे राउंड में दाहिने हुक का इस्तेमाल करके वापसी की। उन्होंने खुद को अंत तक जिस तरीके से ऊर्जावान बनाए रखा, उसके लिए उनकी दाद देनी होगी। मेरी 2019 विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में वेलेंसिया को हरा चुकी हैं। कोलंबियाई मुक्केबाज की यह मेरी पर पहली जीत है। मेरी की तरह वेलेंसिया भी अपने देश के लिए अहम खिलाड़ी हैं। वह पहली महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने देश के लिए ओलिंपिक पदक जीता।



हार के बाद मेरी कोम • ट्विटर

**2012** लंदन ओलिंपिक में भारतीय मुक्केबाज एमसी मेरी कोम ने कांस्य पदक जीत था

**6** बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं मेरी कोम। उन्होंने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था

**2014** एशियन गेम्स में मणिपुर की मुक्केबाज मेरी कोम ने स्वर्ण पदक पर पंच जड़ा था

**5** बार मेरी कोम एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण जीत चुकी हैं

**2018** गोल्ड कोस्ट में मेरी कोम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था

नहीं पता कि क्या हुआ, पहले दौर में मुझे लगा कि हम दोनों एक-दूसरे की रणनीति को भांपने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद मैंने दोनों राउंड जीते। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यह क्या हो रहा है। हम शुरुआत में कोई विरोध नहीं कर पाए। कोई फैसला नहीं बदलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए यह मेरा सबसे खराब ओलिंपिक था। कोई भी टोक्यो में सहयोग नहीं कर रहा है।

**एमसी मेरी कोम**

मेरी कोम स्पष्ट विजेता थीं, लेकिन जजों की अपनी गणना होती है।

**किरण रिजिजू,** पूर्व खेल मंत्री

# सतीश कुमार ने जगाई पदक की उम्मीद



जीत के बाद सतीश कुमार • एएफपी

**टोक्यो, प्रेट्र :** ओलिंपिक में भाग ले रहे भारत के पहले सुपर हैवीवेट (+91 किग्रा) मुक्केबाज सतीश कुमार ने अपने पहले ही खेलों में जमैका के रिकार्डो ब्राउन को पहले मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अगर वह क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो उनका पदक पक्का हो जाएगा। दोनों मुक्केबाजों का यह पहला ओलिंपिक है। सतीश ने 4-1 से जीत दर्ज की। दो बार एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सतीश को ब्राउन के खराब फुटवर्क का फायदा मिला। उन्हें हालांकि मुकाबले में माथे पर खरोंच भी आई। अब सतीश का सामना उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव से होगा जो मौजूदा विश्व और एशियाई चैंपियन हैं। जालोलोव ने अजरबैजान के मुहम्मद अब्दुल्लायेव को 5-0 से हराया।

# सिंधू का विजयी अभियान जारी, क्वार्टर फाइनल में

**टोक्यो, प्रेट्र :** रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन पीवी सिंधू ने प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को यहां टोक्यो ओलिंपिक की महिला सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा के एकतरफा प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। छठी वरीय सिंधू ने 41 मिनट चले मुकाबले में मिया को 21-15, 21-13 से हराया। डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ सिंधू की छह मैचों में यह पांचवीं जीत है। भारतीय खिलाड़ी को मिया के खिलाफ एकमात्र हार का सामना इस साल थाइलैंड ओपन में करना पड़ा था। दो व्यक्तिगत ओलिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने के लिए चुनौती पेश कर रही सिंधू का सामना क्वार्टर फाइनल में जापान की चौथी वरीय अकाने यामागुची से होगा जिन्होंने कोरिया की 12वीं वरीय किम गुएन को सीधे गेम में 21-17, 21-18 से हराया। जापान की दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ सिंधू ने 18 में से 11 मुकाबले जीते हैं जबकि सात में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच मार्च में आल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हुए पिछले मुकाबले में सिंधू ने बाजी मारी थी।

सिंधू ने कहा, 'पहले गेम में मैंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन 15-16 के स्कोर के आसपास कुछ अंक गंवाए। कोच ने मुझे बताया कि मैं गलत तरीके से खेल रही हूं और मैंने भी यह महसूस किया। मैंने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया और पहला गेम जीता। दूसरे गेम में मैंने अच्छा किया, मैंने बढ़त बरकरार रखी और मुकाबले को खत्म किया।' बी साई प्रणीत पुरुष सिंगल्स के अपने दोनों ग्रुप मुकाबले हारकर बाहर हो गए जबकि सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी अपने तीन में से दो ग्रुप मुकाबले जीतने के बावजूद नाकआउट में जगह बनाने में नाकाम रही।



मैच जीतने के बाद खुश पीवी सिंधू • प्रेट्र

# अर्जेंटीना को रौंदकर पुरुष हाकी टीम क्वार्टर फाइनल में

**टोक्यो, प्रेट्र :** आखिरी तीन मिनट में दो गोल करने वाली भारतीय टीम ने रियो ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलिंपिक की पुरुष हाकी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

पिछले मैच में स्पेन को हराने के बाद भारतीय टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए यह महत्वपूर्ण मुकाबला जीता। भारत की युवा ब्रिगेड ने इस जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई और भारत को हाकी में चार दशक बाद ओलिंपिक पदक जीतने के और करीब पहुंचा दिया। भारतीय टीम के लिए वरुण कुमार ने 43वें और विवेक सागर प्रसाद ने 58वें मिनट में गोल किया। हरमनप्रीत ने 59वें मिनट में गोल दागा। अर्जेंटीना ने 48वें मिनट में माइको के गोल के दम पर बराबरी की और 58वें मिनट तक स्कोर बराबर था। इसके बाद भारत ने तीन मिनट के अंतराल में दो गोल दागकर साबित कर दिया कि यह टीम निर्णायक मौकों पर दबाव के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है। भारत पूल-ए में आस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर चल रहा है। भारत को अब 30 जुलाई को आखिरी पूल मैच में मेजबान जापान से खेलना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 की संघर्षपूर्ण जीत के बाद भारतीयों को आस्ट्रेलिया के हाथों 1-7 की करारी हार का सामना करना पड़ा था। मनप्रीत सिंह की टीम हालांकि स्पेन पर 3-0 की जीत से वापसी करने में सफल रही। वहीं, पूल-बी से नीदरलैंड्स और ग्रेट ब्रिटेन ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।



गोल करने के बाद विवेक सागर • प्रेट्र

### दीपिका के बाद उनके पति अतानु भी जीते

**टोक्यो, प्रेट्र :** भारत के स्टार तीरंदाज अतानु दास दूसरे दौर के बेहद रोमांचक मुकाबले में दो बार ओलिंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के ओह जिन हयेक को शूट आफ में हराकर टोक्यो ओलिंपिक की पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। बुधवार को ही उनकी पत्नी दीपिका कुमारी भी महिलाओं के व्यक्तिगत स्पर्धा में जीती थीं। दास ने पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए 6-5 से जीत दर्ज की। शूट आफ में लंदन ओलिंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता जिन हयेक ने नौ अंक जुटाए जिसके बाद दुनिया के नौवें नंबर के खिलाड़ी दास ने 10 अंक पर निशाना साधकर अगले दौर में प्रवेश सुनिश्चित किया। जिन हयेक मौजूदा खेलों में टीम स्वर्ण पदक जीतने वाली कोरियाई टीम का भी हिस्सा थे। अगले दौर में दास का सामना जापान के ताकाहारू फुरुकावा से होगा जो लंदन ओलिंपिक के व्यक्तिगत रजत पदक विजेता हैं। फुरुकावा यहां कांस्य पदक जीतने वाली जापान की टीम का हिस्सा भी थे।



अतानु दास • एएफपी

# आसान नहीं होगा सिंधू का अगला मुकाबला

**ज्वाला गट्टा**



**कलम से**

ओलिंपिक खेलों के प्री-क्वार्टरफाइनलमें पीवी सिंधू की जीत अपेक्षा के अनुरूप ही रही। उन्होंने काफी आसानी से ये मुकाबला जीता और काफी सकारात्मक नजर आईं। आगे चुनौती और मुश्किल होगी, लेकिन वह अच्छी फार्म में हैं और मुझे उम्मीद है कि अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहेंगी। हालांकि ये आसान नहीं होगा और उन्हें जापान की इस अप्रत्याशित खिलाड़ी के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। बेशक सिंधू के दिमाग में ये बात भी चल रही होगी कि उन्होंने इस साल ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में यामागुची को मात दी थी, फिर भी जापानी खिलाड़ी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिंधू को यामागुची को कोर्ट में सहज होने का कोई मौका नहीं देना होगा। अच्छा होगा अगर सिंधू अपनी एनर्जी सेमीफाइनल के लिए बचाकर रखें जहां उनका सामना चीनी ताइपे की ताइ झु यिंग से हो सकता है।

मुझे ये देखकर खुशी हुई कि सिंधू कोर्ट पर कभी भी शिथिल नहीं पड़ीं। तब भी नहीं जब वह आरामदायक बढ़त पर थीं। जहां तक मानसिक हालत की बात है तो वह इस समय आजाद, खुश और रिलेक्स नजर आ रही हैं। ओलिंपिक खेलों जैसे आयोजनों में पीवी सिंधू को इस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते देखना सुखद है। कोर्ट के भीतर और बाहर वह अपनी समस्याओं के समाधान खुद ही तलाशती दिख रही हैं।

अब बात साई प्रणीत की करते हैं। ओलिंपिक में उनके मुकाबले जिस तरह से तय हुए, उससे वह निराश होंगे। 28 साल की उम्र में उनके पास सेमीफाइनल तक पहुंचने का अच्छा मौका था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को कम करके आंकने की गलती की। सात्विक और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स स्पर्धा में विदाई से भी मुझे खराब लगा। इससे 2012 लंदन ओलिंपिक की यादें ताजा हो गईं जब मुझे और अश्विनी पोनप्पा का भी दिल यूं ही टूटा था। तब तीसरे स्थान पर टाई हुआ था और हमसे आगे रहने वाली जापानी जोड़ी को सिर्फ एक अंक की मामूली बढ़त थी। हम यही सोचते रह गए कि काश हमारे कोच हमें संकेत दे देते कि हमें नॉकआउट में जगह बनाने के लिए सिंगापुर की जोड़ी के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूरत है। हमें तब पदक मिल सकता था क्योंकि जानबूझकर मैच हारने के बाद चीन और कोरिया की जोड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मैं काफी निराश थी कि जानकारी के अभाव में हमें पदक जीतने का मौका नहीं मिल सका।

सात्विक और चिराग अभी युवा हैं और मुझे उम्मीद है कि तीन साल बाद होने वाले ओलिंपिक खेलों में उनके पास एक और मौका होगा। उन्हें इस ओलिंपिक अनुभव का लाभ उठाना होगा और पेरिस 2024 ओलिंपिक के लिए तैयारी करनी होगी। टोक्यो में स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया। खासतौर पर 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक का स्वर्ण पदक जीतने वाली 17 साल की लाइडिया जैकबी की प्रतिक्रिया मुझे बेहद पसंद आई। उन्हें जीत दर्ज करने हुए देखना और उसके बाद उनकी अनूठी लेकिन शानदार प्रतिक्रिया का गवाह बनना सचमुच जादुई अनुभव था। (टीसीएम)



# साजन सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम, तैराकी में भारतीय चुनौती समाप्त

**टोक्यो, प्रेट्र :** तैराक साजन प्रकाश गुरुवार को यहां पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन यह सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था जिससे तैराकी में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। प्रकाश ने 53.45 सेकेंड का समय निकाला जबकि सेमीफाइनल के लिए कट 51.74 सेकेंड पर गया। केरल का यह तैराक 55 खिलाड़ियों के बीच 46वें स्थान पर रहा।

**लाहिड़ी की मजबूत शुरुआत :** भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने गोल्फ के पहले दौर में चार अंडर 67 का कार्ड खेलकर मजबूत शुरुआत की। लाहिड़ी ने छह बर्डी लगाई, लेकिन दो बोगी भी कर बैठे। इससे वह पाल कैसे (ब्रिटेन), एलेक्स नोरेन (स्वीडन) और सेबेस्टियन मुनोज (मेक्सिको) के साथ संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर चल रहे हैं। एक अन्य भारतीय गोल्फर उद्यन माने पांच ओवर 76 के कार्ड से लीडरबोर्ड में निचले स्थान पर थे।

**पदक तालिका**

| | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| चीन | 15 | 7 | 9 | 31 |
| जापान | 15 | 4 | 6 | 25 |
| अमेरिका | 14 | 14 | 10 | 38 |
| आरओसी | 8 | 11 | 9 | 28 |
| आस्ट्रेलिया | 8 | 2 | 10 | 20 |
| ग्रेट ब्रिटेन | 5 | 7 | 6 | 18 |
| द. कोरिया | 4 | 3 | 5 | 12 |
| फ्रांस | 3 | 5 | 3 | 11 |
| जर्मनी | 3 | 3 | 7 | 13 |
| इटली | 2 | 7 | 10 | 19 |
| भारत | 0 | 1 | 0 | 1 |

नोट : भारत तालिका में 46वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

**मनु 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन में पांचवें, राही 25वें स्थान पर :** भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबत ओलिंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता की महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन (प्रिसीजन) में क्रमशः पांचवें और 25वें स्थान पर रहीं। मनु ने 44 प्रतिभागियों के बीच क्वालीफिकेशन के प्रिसीजन दौर में 30 निशानों के बाद 292 जुटाए हैं हमवतन राही 287 अंक ही जुटा सकी। क्वालीफिकेशन का दूसरा चरण रेपिड दौर शुक्रवार को होगा। क्वालीफिकेशन में शीर्ष आठ में जगह बनाने वाले निशानेबाज फाइनल में प्रवेश करेंगे।

**नौकायन में अर्जुन और अरविंद 11वें स्थान पर :** भारतीय नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ओलिंपिक की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे जो इस स्पर्धा में ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय जोड़ी ने 6:29.66 का समय निकालकर फाइनल-बी में पांचवां स्थान हासिल किया जो पदक का दौर नहीं था।

# ओलिंपिक पर कोरोना का साया

**ओलिंपिक डायरी**

**टोक्यो, एपी :** ओलिंपिक में खिलाड़ियों को गर्मी के साथ कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। गुरुवार को खेल गांव में कोरोना संक्रमण के रिकार्ड 24 नए मामले सामने आए। इसमें अमेरिका के पोल वाल्ट खिलाड़ी सैम केंड्रिक्स भी संक्रमित पाए गए। इस वजह से आस्ट्रेलिया की पूरी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा टीम को कुछ समय के लिए क्वारंटाइन पर जाना पड़ा, क्योंकि वह आस्ट्रेलिया की टीम के संपर्क में थे। कुछ दिन पहले नंबर एक गोल्फर जान रहम भी खेल गांव में कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उन्हें घर जाना पड़ा था। दो बार के विश्व चैंपियन धारक केंड्रिक्स को ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं की शुरुआत से 24 घंटे से भी कम समय पहले खेलों से बाहर होना पड़ा।

**चीन की बटरफ्लाई क्वीन ने एक दिन में जीते दो स्वर्ण :** चीन की दमदार तैराक व बटरफ्लाई क्वीन के नाम से मशहूर झांग युफेई ने एक दिन में दो स्वर्ण पदक अपने नाम करके सभी को चौंका दिया। झांग ने पहले 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में ओलिंपिक रिकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उसके कुछ ही समय बाद चार गुणा 200 मीटर रिले फ्रीस्टाइल स्पर्धा में उतरकर भी झांग ने अपनी टीम को एक और स्वर्ण पदक जिताया। इस स्पर्धा में रजत पदक अमेरिकी टीम और कांस्य पदक मजबूत मानी जाने वाली आस्ट्रेलिया के नाम रहा।

**अमेरिकी तैराक ड्रेसेल ने जीता अपना दूसरा स्वर्ण :** अमेरिकी तैराक सेलेब ड्रेसेल ने पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में करियर का पहला ओलिंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि इससे पहले उन्होंने अमेरिका के लिए चार गुणा 100 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता। ड्रेसेल ने गत चैंपियन काइल चालमर्स को पछाड़कर सोने का तमगा जीता। ड्रेसेल ने ओलिंपिक रिकार्ड 47.02 सेकेंड के समय के साथ खिताब अपने नाम किया। लगातार दूसरे स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश कर रहे काइल, ड्रेसेल से सिर्फ 0.06 सेकेंड पीछे रहे और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कांस्य पदक रूस ओलिंपिक समिति के क्लिमेंट कोलेसनिकोव ने 47.44 सेकेंड के समय के साथ जीता।

### सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविक

**टोक्यो, एपी :** सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक ने पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक ने जापान के केई निशिकोरी को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से सिर्फ 72 मिनट में हराया। अब सेमीफाइनल में जोकोविक का सामना जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव या फ्रांस के जेरेमी चार्डी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।



नोवाक जोकोविक • प्रेट्र

**मेदवेदेव हुए बाहर :** रूस ओलिंपिक समिति (आरओसी) के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव को एक घंटे 43 मिनट तक क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्टा ने 6-2, 7-6 (7-5) से हराया। बुस्टा का अब सेमीफाइनल में मुकाबला आरओसी के कारेन खचानोव से होगा, जिन्होंने फ्रांस के यूगो हम्बर्ट को 7-6 (7-4), 4-6, 6-3 से हराया था।

# दुती और साबले करेंगे एथलेटिक्स अभियान का आगाज

**टोक्यो, प्रेट्र :** महिला धावक दुती चंद और 3000 मीटर स्टीपलचेज में प्रतिस्पर्धा करने वाले अविनाश साबले शुक्रवार को ओलिंपिक में भारतीय एथलेटिक्स अभियान का आगाज करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खिलाड़ियों के लिए ओलिंपिक से पहले विदेश में अभ्यास सह प्रतिस्पर्धा दौरों की योजना बनाई थी, लेकिन महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे रद करना पड़ा। शिवपाल सिंह (भाला फेंक), अविनाश साबले और एम श्रीशंकर (लंबी कूद) अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा सके तो फाइनल में पहुंच सकते हैं। पहले साबले उतरेंगे, उनके बाद दुती (100 मीटर), एमपी जाबीर (400 मीटर बाधा दौड़) दिखेंगे। मिक्स्ड चार गुणा 400 मीटर रिले टीम शाम को खेलेगी। विश्व रैंकिंग के जरिये टूर्नामेंट में उतरी दुती का लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचना होगा।

**महिला हाकी टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला :** लगातार तीन हार के बाद ओलिंपिक से बाहर होने की कगार पर खड़ी भारतीय महिला हाकी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बचाए रखने के लिए शुक्रवार को हर हाल में आयरलैंड को हराना होगा। वैसे लगातार तीन शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के लिए मनोबल ऊंचा रखकर अपने से ऊंची सातवीं रैंकिंग वाली टीम को हराना आसान नहीं होगा। भारत पूल-ए में पांचवें स्थान पर है, जबकि आयरलैंड एक जीत और दो हार के बाद चौथे स्थान पर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अभी खाता नहीं खोला है। दोनों पूल से शीर्ष-चार टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। भारत को अब आयरलैंड और शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के साथ गोल औसत भी बेहतर रखना होगा। इसके साथ ही उन्हें दुआ करनी होगी कि शनिवार को ब्रिटेन की टीम आयरलैंड को हरा दे। वैसे यह सब जोड़ घटाव तभी होगा जब भारत शुक्रवार को आयरलैंड को हरा पाता है।

**दीपिका से आस :** तीरंदाजी में भारत की आस नंबर एक महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी से लगी हैं। वह व्यक्तिगत मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेंगी। वह रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) की तीरंदाज सेनिया पेरोवा के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी। शुक्रवार को ही क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, कांस्य और स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले खेले जाएंगे।

### पदक पक्का करने उतरेंगी लवलीना

**टोक्यो :** भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पर शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेंगी तो सभी की निगाहें उन पर होंगी क्योंकि वह अगर यह मुकाबला जीत लेती हैं तो उनका खेलों के इस महाकुंभ में पदक पक्का हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे की मुक्केबाज एनसी चेन के खिलाफ होगा। मुक्केबाजी में दो कांस्य पदक दिए जाते हैं और इसीलिए सेमीफाइनल में जगह बनाने से ही लवलीना देश के लिए पदक पक्का कर देंगी। वहीं, अन्य मुक्केबाज सिमरनजीत कौर प्री-क्वार्टर फाइनल में थाइलैंड की सीसोंदे सुदापोर्न के खिलाफ उतरेंगी।



दुती चंद • फाइल फोटो प्रेट्र

## भारत के आज के मैच

**पदक के मुकाबले**

**निशानेबाजी :** महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन रैपिड, सुबह 5:30 बजे से, फाइनल : सुबह 10:30 बजे से, **खिलाड़ी :** राही सरनोबत और मनु भाकर

**अन्य मुकाबले**

**तीरंदाजी (व्यक्तिगत स्पर्धा)**

**खिलाड़ी :** दीपिका कुमारी, प्री-क्वार्टर फाइनल, सुबह 6:00 बजे से

**एथलेटिक्स**

- अविनाश साबले, पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज, राउंड-1 हीट-2, सुबह 6:17 बजे से, • जाबीर, पुरुष 400 मीटर हर्डल्स, राउंड-1 हीट-5, सुबह 8:27 बजे से, • दुती चंद, महिला 100 मीटर, राउंड-1 हीट, सुबह 8:45 बजे से, • मिक्स्ड चार गुणा 400 मीटर रिले रेस, राउंड-1 हीट 2, शाम 4:42 बजे से

**बैडमिंटन :** महिला सिंगल्स, क्वार्टर फाइनल, दोपहर 1:15 बजे से

**खिलाड़ी :** पीवी सिंधू

**मुक्केबाजी :** महिला, अंतिम-16, सुबह 8:18 बजे से

**खिलाड़ी :** सिमरनजीत कौर

- महिला, क्वार्टर फाइनल, दोपहर 8:48 बजे से

**खिलाड़ी :** लवलीना बोरगोहेन

**घुड़सवारी :** इवेंटिंग ड्रेसेज पहला दिन दूसरा सत्र, दोपहर 2:00 बजे से

**खिलाड़ी :** फवाद मिर्जा

**गोल्फ :** पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड-2, सुबह 4:00 बजे से

**खिलाड़ी :** अनिर्बानऔर उदयन माने

**हाकी :** • महिला टीम, पूल-ए, सुबह 8:15 बजे से, बनाम आयरलैंड, • पुरुष टीम, पूल-ए, दोपहर 3:00 बजे से, बनाम जापान

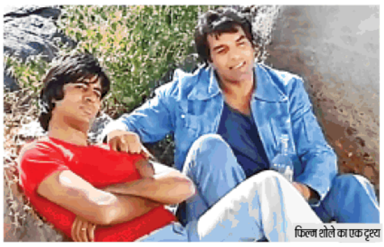
**सेलिंग :** पुरुष स्किफ 49ईआर रेस 7, 8 व 9, सुबह 8:35 बजे से

**खिलाड़ी :** गणपति व वरुण ठक्कर, • पुरुष लेसर रेस 9 व 10, सुबह 11:05 बजे से **खिलाड़ी :** विष्णु सरवनन • महिला लेसर रेडियल रेस 9 व 10, सुबह 8:35 बजे से

**खिलाड़ी :** नेत्रा कुमानन

*प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर*

दैनिक जागरण
# सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 30 जुलाई, 2021



फिल्म शोले का एक दृश्य

फ्रेंडशिप डे विशेष (1 अगस्त)



# दोस्ती का है दिल से रिश्ता



फिल्म दोस्ती का एक दृश्य



फिल्म वीरे दी वेडिंग का एक दृश्य

## दोस्ती का बढ़ता दायरा

पिकल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रमुख समीर दीक्षित कहते हैं कि सिनेमा अब लड़कियों की दोस्ती पर भी कहानियां लिखने से नहीं झिझक रहा। हिंदी में 'वीरे दी वेडिंग' फिल्म बनी है। डिजिटल प्लेटफार्म भी दोस्ती को खुलकर एक्सप्लोर कर रहा है। 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' का तीसरा सीजन आने वाला है। 'हास्टेल डेज' का दूसरा सीजन आ गया है। दोस्त खुलकर बात करते हैं। डिजिटल प्लेटफार्म पर दोस्ती को सच्चाई से दिखाने की आजादी है।

दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है...'थ्री इडियट्स' के इस डायलाग में खट्टी-मीठी दोस्ती का मस्तीभरा एहसास है। सच्चे दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। दोस्ती को परिभाषित करने में हिंदी सिनेमा हमेशा आगे रहा है। 'शोले' के जय-वीरू की दोस्ती मिसाल है, वहीं रैंचो-फरहान-राजू जैसे दोस्तों का जिक्र भी होता है। वक्त के साथ पर्दे पर दिखाई जाने वाली दोस्ती में भी बदलाव आया है। अब दोस्ती में सिर्फ एक-दूसरे के लिए जान देना या त्याग नहीं, बल्कि मौज-मस्ती, प्रतिस्पर्धा, सख्त लहजे में सही राह दिखाने व समझाने की बातें भी बयां होती हैं। एक अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। बदलते वक्त के साथ दोस्ती, उसके मायने, उसे प्रस्तुत करने का अंदाज सिनेमा में कितना बदला है, इसकी पड़ताल कर रहे हैं प्रियंका सिंह व दीपेश पांडेय...



फिल्म थ्री इडियट्स का एक दृश्य

पिछली सदी के छठवें, सातवें और आठवें दशक में 'दोस्ती', 'शोले', 'दोस्ताना', 'आनंद', 'याराना' जैसी फिल्में त्याग और समर्पण पर बना करती थीं, उसके बाद 'मैंने प्यार किया' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों में प्यार से पहले दोस्ती की अहमियत समझाई गई, वहीं 'दिल चाहता है', 'रंग दे बसंती', 'दोस्ताना', 'थ्री इडियट्स', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'काय पो छे', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'काकटेल', 'ये जवानी है दीवानी', 'फुकरे', 'वीरे दी वेडिंग', 'छिछोरे' जैसी फिल्मों ने दोस्ती के नए पाठ पढ़ाए। हर रंग में दोस्ती खूबसूरत ही नजर आई। दोस्ती पर कई फिल्में बन रही हैं, उनमें 'फुकरे 3', 'दोस्ताना 2' शामिल हैं। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म 'आरआरआर' में दोस्ती का एक गाना रखा गया है। आजादी से पहले की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर काल्पनिक कहानी है।

**दोस्ती में होते हैं सारे इमोशंस:** करण जौहर ने अपनी फिल्मों के जरिए समझाया कि प्यार दोस्ती है, वहीं सूरज बड़जात्या ने 'मैंने प्यार किया' में कहा कि दोस्ती का उसूल है... नो सारी, नो थैंक्यू, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। फिल्म 'तेरी मेहरबानियां' में हीरो और डाग के बीच की दोस्ती हो, 'हाथी मेरे साथी' फिल्म में हाथी और हीरो की दोस्ती हो या 'शोले' में घोड़ी धन्नो और बसंती की दोस्ती हो। इंसानों से लेकर जानवरों तक हर तरह की दोस्ती को सिनेमा में एक्सप्लोर किया गया है। दोस्तों पर बनी फिल्म 'बदमाश कंपनी' का निर्देशन और लेखन करने वाले परमीत सेठी कहते हैं कि दोस्ती में सारे इमोशंस होते हैं। ये इमोशन लेखक की कल्पनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करते हैं। फिल्म 'बदमाश कंपनी' मैंने अपने दोस्तों से प्रेरित होकर बनाई थी। मैंने बचपन में दोस्तों के साथ काफी मस्ती और संघर्ष किया था। दोस्ती के कई पहलू होते हैं, दोस्तों से जुड़ी कई घटनाएं होती हैं, इसलिए यह विषय कभी पुराना नहीं होगा। दोस्ती पर बनी फिल्म 'शोले' मेरी पसंदीदा फिल्म रही। जय-वीरू की जोड़ी दोस्ती के लिए एक मिसाल बन गई थी। पहले फिल्मों की दोस्ती बहुत सीधी सादी होती थी, लेकिन अब सिनेमा में उसका चित्रण जटिल होने लगा है, उनके रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव होते हैं। पहले सिनेमा में जैसे एकदूसरे के लिए जान देने वाली दोस्ती होती थी, अब वैसी बातें नहीं होतीं, क्योंकि ये वास्तविकता से दूर की बात है।

**दोस्ती की कहानियां ढूंढ़ते हैं मेकर्स:** 'फुकरे' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'फुकरे 3' की शूटिंग शुरू होने वाली है। चार दोस्तों पर आधारित इस फिल्म के निर्देशक और लेखक मृगदीप सिंह लांबा कहते हैं कि मेरी कोशिश यही होती है कि कहानी को जितना हो सके, आसपास जो चल रहा है, उसके करीब रखा जाए। मैं अपनी कहानियां लिखता हूं तो दर्शक के नजरिए से सोचता हूं। तभी दोस्ती पर नई कहानियां ला पाया। 'फुकरे' फिल्म दोस्ती वाली फिल्मों के लिए रेफरेंस बन गई। पहले लोग पूछते थे कि 'थ्री इडियट्स' जैसी कोई स्क्रिप्ट है क्या, अब 'फुकरे' के बाद लोग वैसी कहानियों की तलाश करने लगे हैं। स्लाइस आफ लाइफ वाली कहानी है। मैं खुद दिल्ली से हूं, ऐसे दोस्त मैंने अपने आसपास देखे हैं। उन्हीं अनुभवों को स्क्रीनप्ले के फार्मेट में डाल दिया था। जब 'फुकरे' बनाई थी तो एक रिस्क फैक्टर तो था ही, क्योंकि दोस्ती पर बहुत फिल्में बन चुकी हैं। मैं दोस्ती में कोई डार्कनेस नहीं दिखाना चाहता था। 'फुकरे' को बनाते वक्त एक ऐसा वक्त भी आया था, जहां स्क्रीनप्ले गंभीर हो रहा था। मुझे लगा कि यह तो 'रंग दे बसंती' फिल्म जैसी बन जाएगी। हमने फिर से बदलाव किए, हल्की फुल्की चीजें फिल्म में शामिल कीं।

**अच्छा दोस्त हूं, इसलिए वैसे रोल मिलते हैं:** 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'दिल बेचारा', 'शेरशाह' जैसी कई फिल्मों में हीरो के दोस्त का किरदार निभा चुके साहिल वैद्य कहते हैं कि मेरे लिए दोस्ती के मायने हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं। माता-पिता, रिश्तेदार ऊपर वाला तय करता है। दोस्त हम तय करते हैं। आपके मन में अगर अपने दोस्त की मदद करते वक्त संकोच हो रहा है तो समझ लीजिए उस दोस्ती में कहीं न कहीं खोट है। लाकडाउन जैसे मुश्किल वक्त में दिमाग को सही रखने में दोस्ती ने बहुत मदद की है। मेरे कुछ दोस्त हैं, जिनसे कोई भी बात कर सकता हूं। मैं जब निराश होता हूं तो वे मुझे मेरी क्षमता याद दिलाते हैं। शायद यही वजह है कि मैं आफस्क्रीन और आनस्क्रीन अच्छा दोस्त हूं, इसलिए ऐसे किरदार भी आफर हो रहे हैं। 'शेरशाह' फिल्म में भी हीरो का दोस्त बना हूं, लेकिन किरदार अलग है, क्योंकि कारगिल युद्ध में क्या हुआ वह दुनिया जानती है, लेकिन उससे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी में क्या हुआ, वह फिल्म का दिलचस्प पहलू है। उसमें मेरी भूमिका अहम है।

**दोस्तों की यादें ताजा कराती हैं फिल्में:** फिल्म 'छिछोरे' में दोस्तों के ग्रुप में शामिल तुषार पांडे कहते हैं कि दोस्ती एक आधारभूत इमोशनल रिश्ता है जो हर इंसान की जिंदगी में होता है। हम उनके साथ वक्त बिताते हैं। हमारे व्यक्तित्व पर उनका गहरा असर होता है। फिल्म निर्माण में भी इन्हीं भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं फिल्म 'छिछोरे' में अपने किरदार सुंदर श्रीवास्तव की बात करूं तो वह अपनी मम्मी का प्यारा बेटा है, जो थोड़ा डरकर रहता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दोस्तों के संपर्क में आने से उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। सुंदर की तरह मैं भी पढ़ने का बहुत शौकीन हूं, बाकी मेरा व्यक्तित्व उससे अलग है। मेरे भी स्कूल के दिनों में ऐसे कई दोस्त थे, जिनकी याद मुझे सुंदर का किरदार सुनने के बाद आई। मैंने उन्हीं के बारे में सोचकर इस किरदार को निभाया। यह एक सदाबहार विषय है जो कभी पुराना नहीं होगा।

**इंटरनेट के दौर में बदलती दोस्ती:** पिकल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रमुख समीर दीक्षित दर्शकों की पसंद को लेकर कहते हैं कि दोस्ती जीवंत विषय है। 'दिल चाहता है' दोस्ती पर बनी बेहतरीन फिल्म है। उसके सीक्वल के निर्माण की भी चर्चा है। अब न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। लोग रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्तों पर निर्भर करते हैं। दोस्त आपस में हर तरह की बातें करते हैं। आज की पीढ़ी इंटरनेट मीडिया की वजह से वर्चुअल दोस्त बहुत बना रही है। युवाओं की बदलती जिंदगी की वजह से दोस्ती पर बनने वाली कहानियों में भी बदलाव हुआ है। पहले दोस्ती में जो गर्माहट थी, जान देने की बातें होती थीं, वह एहसास गायब है, लेकिन आज की पीढ़ी उससे रिलेट भी नहीं कर पाएगी। फिल्म से कमर्शियल पहलू जुड़ा होता है, ऐसे में दर्शकों की पसंद का खयाल तो रखना होगा। अब भी दोस्ती पर अच्छी फिल्मों की गुंजाइश है। रोमांस के बाद दोस्ती के विषय में बहुत पोटेंशियल है। लेखक सिर्फ दोस्ती पर फोकस करके नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लगभग हर फिल्म में हीरो का दोस्त जरूर होता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो हीरो का एक कामेडियन दोस्त जरूर होता है। हालांकि वह दोस्ती का सही प्रोजेक्शन नहीं है। दोस्त आपका संबल होते हैं। जीवन में आगे बढ़ना व खुश रहना सिखाते हैं।

# हर मिजाज के किरदार करने हैं

मेरी बात

हिंदी सिनेमा में करीब चार दशक से सक्रिय नीना गुप्ता इन दिनों काफी व्यस्त हैं। छह अगस्त को जी5 पर रिलीज हो रही फिल्म 'डायल 100' में वह निगेटिव किरदार में नजर आएंगी। फिल्म 'गुड बाय' में वह अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही हैं। उनकी वेब सीरीज 'मसाबा मसाबा 2' पर भी काम चल रहा है। आने वाली फिल्मों और जीवन के अन्य पहलुओं को लेकर नीना साझा कर रही हैं दिल की बातें...

**पहली बार किया था इन्कार:** नीना ने पहली बार 'डायल 100' को करने से इन्कार कर दिया था। वह बताती हैं, 'पहले मुझसे एक लाइन में कहा गया था कि यह एक मां की कहानी है जो बदला लेती है तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की निगेटिव कहानी नहीं करनी है। फिर जब फिल्म के निर्देशक रेंजिल डिसिल्वा ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई तो बहुत अच्छी लगी और मैंने हामी भर दी। आगे भी मुझे जो किरदार या स्क्रिप्ट अच्छी लगेंगी, वे चाहे निगेटिव हों या पाजिटव, मैं वे प्रोजेक्ट जरूर करूंगी।'

**दिल से चुनती हूं प्रोजेक्ट:** किरदारों को लेकर लगातार प्रयोग कर रही नीना कहती हैं, 'अगर मेरा दिल कहता है कि यह प्रोजेक्ट करना है तो मैं उसे करती हूं। अगर दिल दिमाग को सोचने के लिए कहता है तो उसका मतलब प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। बात दिल से दिमाग तक पहुंचने का मतलब होता है कि दिमाग में प्रोजेक्ट के बाकी पहलू चल रहे हैं, जैसे पैसे कितने मिलेंगे, निर्देशक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, आगे मुझे इस प्रोडक्शन में काम मिलेगा या नहीं? ऐसा मैं पहले करती आई हूं, क्योंकि पहले पैसों की जरूरत थी। अब सिर्फ दिल की ही बातें सुनकर फैसले करती हूं।'

**बिग बी के साथ काम का अनुभव:** 'गुड बाय' में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के अनुभव पर नीना कहती हैं, 'उनके साथ काम करने में ज्यादातर सभी कलाकारों को शुरू में घबराहट होती है। शूटिंग से पहले उनके साथ फोटोशूट कराते समय मैंने उनसे कहा कि मैं नर्वस हूं तो वह हंसने लगे और पूछा कि नर्वस क्यों हो? उसके बाद धीरे-धीरे जब हम बातें करने लगे तो सबकुछ सामान्य लगने लगा। उनके लिए मन में तो सम्मान रहता था, लेकिन जब किरदार में होते थे तो हम दोनों उसी में रम जाते थे। फिलहाल मैं अमेरिका में अनुपम खेर के साथ फिल्म 'शिव शास्त्री बल्बोआ' की शूटिंग कर रही हूं। इसके बाद 'मसाबा मसाबा 2', 'पंचायत 2' की शूटिंग करूंगी। झोली में तीन फिल्में और हैं।'



**बायोपिक में करना चाहूंगी काम:** हाल ही में नीना गुप्ता ने अपनी बायोग्राफी 'सच कहूं' पेश की है। नीना अपनी बायोपिक के सवाल पर कहती हैं, 'फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर कभी बनती है तो मैं उसमें काम करना चाहूंगी। अभी तो मैं अपनी बायोग्राफी पर काम कर रही हूं। उसमें भाई और मां का चैप्टर लिखना सबसे मुश्किल था। अपनी बायोग्राफी का हिंदी अनुवाद मैं खुद ही कर रही हूं। जल्द ही हिंदी संस्करण उपलब्ध होगा।'

दीपेश पांडेय

# वरुण निकालते थे ओवरएक्टिंग की भड़ास

यादों का झरोखा

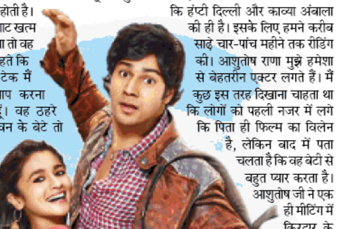


आलिया भट्ट और वरुण धवन अभिनीत फिल्म 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया' से शशांक खेतान ने निर्देशन में कदम रखा था। यह फिल्म अंबाला और दिल्ली की गलियों के उन किरदारों की कहानी है जो दिल से सोचते हैं और प्रेम में यकीन रखते हैं। फिल्म से जुड़ी यादों को साझा कर रहे हैं निर्देशक शशांक खेतान...

पहले इस फिल्म का टाइटल था 'हंप्टी शर्मा- द लव स्टोरी', लेकिन बाद में क्रिएटिव चीजों को देखते हुए इसका नाम बदलकर 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया' कर दिया गया। मुझे हमेशा से लगा है कि रोमांटिक फिल्मों के किरदारों के नाम प्यारे होने चाहिए जो लोगों को हमेशा याद रहें। इस फिल्म के शुरुआती दौर में मैंने नायक की एक बैकस्टोरी तैयार की थी कि एक लड़का है जिसका नाम राकेश शर्मा है। वह बचपन में मोटा था और बड़ा होने के बाद पतला हो गया है। मोटे होने के कारण लोग उसे हंप्टी डम्प्टी कार्टून के नाम पर हंप्टी बुलाते थे। इस तरह से मेरे किरदार हंप्टी का जन्म हुआ। काव्या नाम मुझे बहुत पसंद था। मैंने सोचा था कि फिल्म बनाऊंगा तो किरदार का नाम काव्या जरूर रखूंगा। लव स्टोरी लिखते वक्त मेरी कोशिश यही रहती है कि जोड़ियों का नाम सुनने में अच्छा लगे, हंप्टी और काव्या की जोड़ी सुनने में अच्छी लग रही थी।

वरुण की उस समय तक सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान ही हम दोनों ने समझ लिया कि हम दोनों के बीच कुछ खास होने वाला है। वरुण इतने ऊर्जावान हैं कि उनके साथ शूटिंग बहुत दिलचस्प होती है। जब पूरा शाट खत्म हो जाता था तो वह अंत में कहते कि यार एक टेक मैं अपने आप करना चाहता हूं। वह ठहरे डेविड धवन के बेटे तो उनमें ओवर एक्टिंग हमेशा से ही रही है। जब वह अपने अंदाज में ओवर एक्टिंग के साथ वह सीन करते तो पूरा सेट हंसता। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ओवरएक्टिंग की जो भड़ास है वह निकल जाए ताकि अगले दिन सीन में न आए।

वरुण और आलिया दोनों मुंबई में पले-बढ़े हैं। किरदारों की बोली में ढलने के लिए दोनों ने इतनी मेहनत की जिससे लगने लगा कि हंप्टी दिल्ली और काव्या अंबाला की ही है। इसके लिए हमने करीब साढ़े चार-पांच महीने तक रीडिंग की। आशुतोष राणा मुझे हमेशा से बेहतरीन एक्टर लगते हैं। मैं कुछ इस तरह दिखाना चाहता था कि लोगों को पहली नजर में लगे कि पिता ही फिल्म का विलेन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह बेटी से बहुत प्यार करता है। आशुतोष जी ने एक ही मीटिंग में किरदार के लिए स्वीकृति दे दी थी।



इस फिल्म के गाने 'दैंगड़ दैंगड़' की शूटिंग के दौरान हर दो घंटे के अंतराल पर बारिश होती थी। बारिश होने लगती तो सब लोग भागते और ग्राउंड को ढकते। सटर्डे-सटर्डे गाना फिल्म रिलीज होने से डेढ़-दो साल पहले ही पंजाब में रिलीज हो चुका था, लेकिन पापुलर नहीं हुआ था। जब मैंने इसे सुना तो हमारी फिल्म के लिए यह उपयुक्त लगा। हमारी फिल्म के निर्माता करण जौहर समेत जिसको भी मैंने यह गाना सुनाया, उन्होंने कहा कि यह तो बहुत कमाल का गाना है। फिर हमने इसके राइट्स खरीदे और प्रमोशनल वीडियो शूट किया।

फिल्म में मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया लहंगा भी आकर्षण का केंद्र रहा। मैं जब भी परिवार सहित शादियों में जाता था तो देखता कि लड़के शेरवानी-कुर्ते को लेकर इतना शौकीन नहीं होते, जितनी लड़कियां लहंगे को लेकर। उच्च मध्यमवर्गीय या मध्यमवर्गीय परिवार की लड़कियों के लिए शादी में मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना गर्व की बात होती है। मैंने समाज के इसी हिस्से को दिखाने की कोशिश की। क्लाइमेक्स सीन में आलिया को ट्रक के ऊपर चढ़कर हंप्टी को बुलाना था। उससे ठीक पहले आलिया के पांव में मोच आ गई थी, पर उन्होंने अपनी हिम्मत और क्रू के सहयोग से सीन पूरा किया।

स्मिता श्रीवास्तव

# अच्छा काम तो सहज हो जाता है

मुलाकात

डिज्नी प्लस हाटस्टार पर आज रिलीज वेब सीरीज 'सिटी आफ ड्रीम्स 2' में अभिनेता सचिन पिलगांवकर एक बार फिर राजनेता जगदीश गौरव के किरदार में नजर आएंगे। यह साल 2019 में आई वेब सीरीज 'सिटी आफ ड्रीम्स' का दूसरा सीजन है।



**दूसरे सीजन में क्या नया है?**
नए सीजन में नई चीजें होना स्वाभाविक हैं। इस बार शो में पिता अमेय राव गायकवाड़ और उनकी बेटी पूर्णिमा के बीच द्वंद्व होगा। दोनों के बीच एक तकरार है, जिसका कारण पहले सीजन के अंत में दिखाया गया था कि उम्मीद है लोग इसे भी प्यार देंगे।

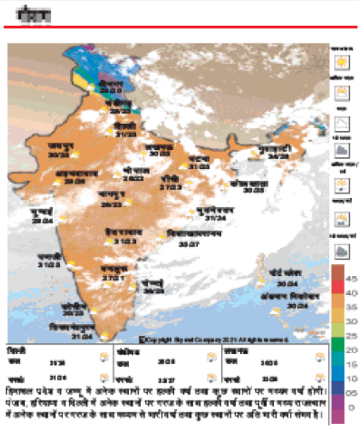
**बतौर कलाकार क्या प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता का दबाव आप लेते हैं?**
ये चीज सभी के साथ होती है। बतौर फिल्ममेकर भी पहले बनाई फिल्मों से अच्छा करने का दबाव रहता है। स्कूल में जब कोई छात्र अच्छे नंबर के साथ पास होता है तो अगली कक्षा में बेहतर परफार्मेंस की उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पहले से बेहतर करने लिए अभ्यास और मेहनत जरूरी है। सफलता या असफलता का दबाव निर्माता, निर्देशक, कलाकार और लेखक समेत पूरी टीम पर होता है। अच्छा काम कोई करता नहीं, वह तो बस सहज हो जाता है।

**साढ़े पांच दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहने के बाद किरदारों की तैयारी की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया है?**
बदलाव ही तो एक नियत सत्य है। बदलावों को अपनाना हम कलाकारों का काम है। डिजिटल प्लेटफार्म के परफार्मेंस और सिनेमा के परफार्मेंस में अंतर है। अगर हम सिनेमा की तरह ही किरदार की पिच डिजिटल प्लेटफार्म पर भी रखें तो यह सूट नहीं करेगा। थिएटर में लाइव आडिएंस होती है और सभी कलाकारों के लिए सिर्फ लांग शाट फ्रेम ही होता है, जबकि सिनेमा में सभी किरदारों का अलग-अलग फ्रेम होता है। प्लेटफार्म के अनुसार खुद को ढालने में कलाकार को निर्देशक की जरूरत पड़ती है और खुशकिस्मती से हमारे निर्देशक नागेश कुकुनूर को ये चीजें अच्छी तरह पता हैं।

**प्रत्येक प्लेटफार्म पर राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानियां निर्माताओं को लगातार आकर्षित कर रही हैं...**
संघर्ष ऐसी चीज है, जो अगर किताब में हो तो पढ़ने में मजा आता है, फिल्म या वेब सीरीज में हो तो देखने में मजा आता है। राजनीति तो एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर राजनीति की वजह से किसी के जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है तो वह ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हमारे शो के दोनों सीजन में इसी संघर्ष को अलग तरह से पेश किया गया है।

**मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। इससे जुड़े आपके क्या सपने रहे हैं?**
इस शहर के सपने खत्म नहीं होते हैं। मुंबई तो एक मायानगरी है, इसके सपने देखना पाप नहीं है, लेकिन वह सपना पूरा होना आसान भी नहीं होता है। कोरोना काल में इंडस्ट्री में आर्थिक तंगी ने लोगों को परेशान किया। मैं कलाकारों और तकनीशियनों से यही कहूंगा कि स्वयं को सक्षम बनाएं, बचत करें। बड़े-बड़े फोन और गाड़ियां हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। सिर्फ आपका आत्मविश्वास आपके साथ हमेशा रहता है। उसे संभाल के रखिए, भविष्य की चिंता कीजिए। बचत करते हुए सुखी जीवन बिताएं।

दीपेश पांडेय





### उत्तरी ग्रिड फेल होने से कई राज्यों में छा गया था अंधेरा

वर्ष 2012 में आज ही उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के आठ राज्यों में बिजली गुल हो गई थी। रेल, मेट्रो, जल आपूर्ति समेत कई तरह की सेवाएं ठप हो गई थीं। इसे पूरी तरह ठीक होने में 24 घंटे से ज्यादा समय लगा था।





### राइट मिलिट्री फ्लेयर विमान का परीक्षण हुआ पूरा

1909 में आज ही राइट ब्रदर्स विलबर और आरविल ने अपने विमान राइट मिलिट्री फ्लेयर का परीक्षण पूरा किया। आरविल ने अमेरिकी सेना के अधिकारी बेंजामिन डी के साथ उड़ान भरी थी। यह सेना द्वारा खरीदा गया पहला विमान था।

### भारत की पहली महिला विधायक थीं मुथुलक्ष्मी रेड्डी

पद्मभूषण से सम्मानित मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 में आज ही तमिलनाडु के पुदुकोट्टी में हुआ था। वह 1912 में भारत की पहली महिला सर्जन बनी थीं। 1927 में ब्रिटिश विधानसभा में भारत की पहली महिला विधायक चुनी गईं। दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा के लिए 1931 में अव्वाई होम स्थापित किया। 1954 में चेन्नई में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। 1956 में उन्हें पद्मभूषण मिला। 22 जुलाई, 1968 को चेन्नई में उनका निधन हो गया।



# लिवर की रक्षा करता है गुड कोलेस्ट्राल

## शोध ▶ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने खोजा गुड कोलेस्ट्राल का एक नया प्रकार

### बैक्टीरिया जनित जलन पैदा करने वाले पदार्थों के सिग्नल को करता है अवरुद्ध

**न्यूयार्क, आइएएनएस :** शोधकर्ताओं ने एक ऐसे गुड कोलेस्ट्राल की खोज की है, जो पेट में पाए जाने वाले सामान्य बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सूजन या जलन पैदा करने वाले पदार्थों के सिग्नल को अवरुद्ध कर लिवर की रक्षा करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) शरीर के कोलेस्ट्राल के निपटारे के लिए उसे लिवर तक पहुंचाता है। लेकिन अमेरिका के सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि एक प्रकार का गुड कोलेस्ट्राल, जिसे एचडीएल3 कहते हैं, जब आंत में पैदा होता है तो यह लिवर को सूजन और जख्म से बचाता है।



लिवर के रोगों का मिलेगा नया इलाज। फाइल

यूनिवर्सिटी के स्कूल आफ मेडिसिन में इम्यूनोलाजी के प्रोफेसर ग्वेंडालिन जे. रैंडोल्फ ने बताया कि आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जो इम्यून सेल को सक्रिय करता है और उसके कारण जलन या सूजन पैदा होता है। ऐसे में उसका सिग्नल यदि अवरुद्ध नहीं किया जाए तो यह लिवर तक पहुंच कर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्राल माना जाता है, लेकिन इसका स्तर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं का हाल के वर्षों में प्रयोग कम हुआ है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में कार्डियोवास्कुलर विकारों में उसका कोई खास फायदा नहीं दिखा है। लेकिन हमारे अध्ययन में पाया गया है कि यदि इस खास प्रकार के एचडीएल का स्तर आंत में बढ़ाया जाए तो यह लिवर संबंधी बीमारियों से बचा सकता है।

साइंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि आंत में मिलने वाले एचडीएल3 - लिवर को जलन या सूजन से बचाता है। आंत को यदि किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचे तो उसका असर जीवाणुओं के समूह (जिसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं) पर पड़ता है। इन जीवाणुओं के इंफ्लेमेटरी मालिक्यूल (लिपोपालीसेकेराइड) पोर्टल नस के जरिये लिवर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में आंत में पाए जाने वाले उन जीवाणुओं से पैदा होने वाले पदार्थ, जो इम्यून सेल को सक्रिय करते हैं, जिससे जलन या सूजन पैदा होता है- वे भी पोषण के साथ लिवर तक पहुंचते हैं। इससे फैटी लिवर तथा लिवर फिब्रोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, जिनमें लिवर में घाव पैदा होता है। उम्मीद है कि भविष्य में लिवर संबंधी बीमारियों के इलाज में एचडीएल3 कारगर साबित होगा।

## इसरो ने आमजन को जोड़ने के लिए लांच किया मर्केंडाइजर प्रोग्राम

**बेंगलुरु, प्रेट्र :** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपनी उपलब्धियों को जन-जन खासकर युवाओं और बच्चों तक पहुंचाने के लिए मर्केंडाइजर प्रोग्राम लांच किया है। इसके तहत टीशर्ट, खिलौनों, आनलाइन गेम और अन्य उत्पादों के जरिये इसरो की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। जनभावना को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

इसरो के अनुसार छात्रों व आमजन को जोड़ने के इस प्रयास के उत्साहजनक परिणाम की उम्मीद है। इसरो मर्केंडाइजर के रूप में अभी तक अंकुर हाबी सेंटर (गुजरात), ब्लैक व्हाइट ओरेंज ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र), इंडिक इंस्पाइरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) समेत करीब एक दर्जन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

## स्वस्थ जीवन शैली से कम हो सकता है कैंसर का खतरा

**अनुसंधान**

एक नए अध्ययन में बताया गया है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जोखिम अच्छी जीवन शैली से कम किया जा सकता है। पाया गया है कि धूमपान और शराब पीने से परहेज, मोटापा का न होना और नियमित व्यायाम से कैंसर के उच्च आनुवांशिक खतरे वाले लोग भी बचे रह सकते हैं।

यह अध्ययन अमेरिकन एसोसिएशन के कैंसर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्वांगफू जिन ने किया। टीम ने अध्ययन किया कि शरीर में सकारात्मक परिवर्तन करके कैंसर के उच्च आनुवांशिक खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। अध्ययन में सामान्य लोगों के साथ उन मरीजों को भी शामिल किया गया, जो कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं।

शोध में दो लाख से ज्यादा पुरुषों और सवा दो लाख महिलाओं को शामिल किया गया। इन सभी का डाटा यूके बायो बैंक से लिया गया था। 2006 से 2009 तक ब्रिटेन, स्काटलैंड और वेल्स में आंकड़ों का अध्ययन किया गया। लोगों में शराब और धूमपान की लत, बाडी मास इंडेक्स (मोटापा), व्यायाम, खान-पान की स्थितियों को बारीकी से देखा गया। -एएनआइ

### इधर-उधर की

#### कुआं खोदते हुए मिला विश्व का सबसे बड़ा नीलम

**कोलंबो, एजेंसी :** किस्मत अच्छी होने पर मिट्टी भी सोना बन जाती है। श्रीलंका के रत्नपुरा की खबर भी कुछ ऐसी ही है। यहां एक घर के आंगन में कुआं खोदने के दौरान मिला नीलम दुनिया का सबसे बड़ा नीलम निकला। इसकी कीमत करीब साढ़े सात अरब रुपये बताई जा रही है। एक व्यापारी के घर में खोदाई के दौरान मजदूरों को यह मिला था। व्यापारी ने कहा, इसके मिलने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी थी। 510 किलो के नीलम को साफ करने में करीब एक साल का समय लगा। सफाई के बाद इसकी सही कीमत का पता लग सका। इसको सेरेंडिपिटी सफायर (किस्मत से मिला नीलम) नाम दिया गया है।



सालभर चली सफाई की प्रक्रिया के बाद सामने आई खबर। इंटरनेट मीडिया

**जागरण विशेष**

# तंत्रिका तंत्र पर कोरोना के प्रभाव की गुत्थी सुलझाएगा रांची का रिम्स

## डब्ल्यूएचओ और अमेरिकी संस्थान एनआइएच संग करेगा वैश्विक शोध, चार यूरोपीय देश भी होंगे शामिल

अनुज तिवारी • रांची

कोरोना वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर देश-दुनिया के विशेषज्ञ चिंता कर रहे हैं। कई कोरोना मरीज मस्तिष्क और न्यूरो से संबंधित बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के विशेषज्ञ अब इस बात पर मंथन करेंगे कि कोरोना की चपेट में आने के बाद लोगों को मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारियां हो रही हैं। इस अंतराष्ट्रीय शोध के लिए दुनिया के बड़े संस्थानों ने रिम्स पर भरोसा जताया है। रिम्स के साथ इस शोध में अमेरिका के अलावा यूरोप के चार देश शामिल हैं। भारत से इस शोध में शामिल एकमात्र संस्थान रिम्स है।



रांची के रिम्स में न्यूरो विभाग में भर्ती मरीज और इलाज करते स्वास्थ्यकर्मी • जागरण

**न्यूयार्क विवि करेगा नेतृत्व :** यह शोध अमेरिका के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ (एनआइएच) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की देखरेख में हो रहा है। एनआइएच ने इस शोध के लिए तीन वर्ष का समय तय किया है। एनआइएच विश्व की बड़ी शोध संस्थाओं में से एक है। इस शोध के जो भी निष्कर्ष होंगे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जर्नल में प्रकाशित किए जाने की योजना है। रिम्स के निदेशक डा. कामेश्वर प्रसाद बताते हैं कि न्यूयार्क विश्वविद्यालय के नेतृत्व और समन्वय में होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय शोध के लिए रिम्स को मौका मिलना गौरव की बात है। इस शोध में न्यूयार्क विश्वविद्यालय के शोधार्थी और यूरोपीय देशों यूनाइटेड किंगडम (यूके), जर्मनी, स्पेन और इटली के चिकित्सक तंत्रिका तंत्र पर कोरोना के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

**रिम्स के कई डाक्टर होंगे शामिल :** एनआइएच ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय को इस शोध का कार्य सौंपा था। न्यूयार्क विश्वविद्यालय ने इस शोध को अंतरराष्ट्रीय शोध में बदलते हुए भारत समेत विश्व के अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया। हाल के दिनों में रिम्स द्वारा किए गए शोध कार्य को भी देखा-परखा गया। शोध में हिस्सा ले रहे पद्मश्री डा. कामेश्वर प्रसाद पहले से ही बतौर न्यूरो कोरोना एक्सपर्ट डब्ल्यूएचओ की टीम में शामिल हैं। पूर्व में उन्होंने न्यूरो के क्षेत्र में कई विषयों पर अपनी प्रस्तुति भी दी है। शोध में निदेशक के अलावा रिम्स के डा. अमित कुमार, डा. सुरेंद्र कुमार, डा. गणेश चौहान, डा. देवेश और डा. प्रभात कुमार सहित अन्य सहयोगी शामिल होंगे।

**ऐसे होगा शोध कार्य :** शोध कार्य के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया है। इसमें रिम्स में आने वाले व भर्ती हुए पोस्ट कोरोना मरीजों की पूरी जानकारी आनलाइन डाटा बेस में रखी जाएगी। देखा जाएगा कि कोरोना निगेटिव होने के बाद उनकी याददाश्त कैसी है, वह किस तरह की चीजों को भूल जाते हैं। उनमें बीपी व चक्कर आने की समस्या कैसी है। साथ ही, शरीर में कंपन की क्या स्थिति है। जो भी जांच कराई जाएगी, उसका भी डाटा सहेजा जाएगा। पूरा शोध कार्य इस डाटाबेस पर ही आधारित होगा। शोध के लिए रिम्स में पोस्ट कोरोना क्लिनिक बनाया जा चुका है। डा. कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

#### मजबूत इम्यून सिस्टम पर भी महामारी के असर की जांच

यह शोध उत्तर-पूर्वी भारत पर केंद्रित होगा। झारखंड में आदिवासी-जनजातीय आबादी की बहुतायत के कारण यह शोध ऐसे मरीजों पर भी हो सकेगा, जो जनजातीय समूह से आते हैं। इसे देखते हुए शोध के लिए रिम्स का चुनाव किया गया। शोध में यह भी पता चल सकेगा कि मजबूत इम्यून सिस्टम वाले जनजातीय समुदाय के लोगों पर कोरोना ने कैसा असर डाला।



रिम्स के लिए यह शोध बड़ी उपलब्धि है। इस शोध कार्य में रिम्स की न्यूरोलाजी की टीम के साथ-साथ अन्य विभागों के डाक्टरों को भी मौका दिया गया है।
**डा. कामेश्वर प्रसाद,** निदेशक, रिम्स, रांची



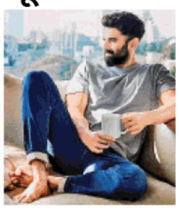
दुनिया के बड़े संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का अनुभव खास है। इस शोध से निकले निष्कर्ष आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों के इलाज में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
**डा. अमित कुमार,** न्यूरो विशेषज्ञ, रिम्स, रांची

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

**स्क्रीन शॉट**

# थाडम की रीमेक में होंगे आदित्य राय कपूर

एक के बाद एक लगातार हालीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी रीमेक बनने की घोषणाओं के बीच इस सूची में साल 2019 में रिलीज हुई तमिल फिल्म थाडम का नाम भी शामिल हो गया है। गुरुवार को इस फिल्म के निर्माताओं भूषण कुमार और मुराद खेतानी ने फिल्म के अभिनेता के साथ इसकी आधिकारिक रीमेक का एलान किया। फिल्म में आदित्य राय कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं अभिनेत्री के तौर पर मृणाल ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले थाडम की हिंदी रीमेक अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बनाए जाने की खबरें थी। इस फिल्म से वर्धन केतकर अपनी निर्देशन की पारी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वह कपूर एंड संस, मुबारकां और ब्रदर्स जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। इस फिल्म में आदित्य दो अलग-अलग लुक में दोहरे किरदार में नजर आएंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की हिंदी रीमेक का शीर्षक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस फिल्म के बारे में जारी बयान में आदित्य ने कहा, 'मैं इस तरह की दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। मूल फिल्म अविश्वसनीय तौर पर बहुत मनोरंजक थी, जिसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी। बतौर कलाकार डबल रोल करने का मौका मिलने का मतलब डबल चुनौती और डबल तैयारी होता है। मैं इसके लिए तैयार हूं।' इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी। सच्ची घटना पर आधारित मूल फिल्म में तमिल अभिनेता अरुण विजय के साथ अभिनेत्रियां तान्या होप और विद्या प्रदीप अहम भूमिकाओं में थीं।



थाडम की हिंदी रीमेक में दोहरे किरदार में होंगे आदित्य। इंस्टाग्राम

## सिनेमा में बढ़ते महिला प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करेगा आइएफएफएम-2021

**आस्ट्रेलिया में आयोजित** होने वाले द इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्न (आइएफएफएम) में इस साल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते महिला प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके तहत इस साल फिल्म फेस्टिवल के 12वें संस्करण में विभिन्न वर्गों में महिला फिल्मकारों द्वारा बनाई फिल्मों को प्राथमिकता दी गई है। आस्ट्रेलिया के सिनेमाघरों में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 12 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा तथा 15 अगस्त से 30 अगस्त तक इस फेस्टिवल की वर्चुअल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुनी गई कुल सौ फिल्मों में से 33 फिल्में महिला फिल्मकारों द्वारा निर्मित हैं। इस फेस्टिवल के निदेशक मितु भौमिक लांगे ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, 'महिला फिल्मकारों द्वारा इतनी गहराई और सशक्त विषयों पर आधारित फिल्में देखकर अच्छा लगा।' वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक रीमा दास का कहना है, 'फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष फिल्मकारों और महिला फिल्मकारों की संख्या में काफी अंतर है। इसलिए ज्यादातर कहानियां भी पुरुषों के नजरिए से दिखाई जाती हैं।' इस फेस्टिवल में रीमा द्वारा निर्देशित शार्ट फिल्म फार ईच अदर प्रदर्शित की जाएगी।



फेस्टिवल में रीमा दास द्वारा निर्देशित शार्ट फिल्म फार ईच अदर होगी प्रदर्शित। स्वयं की पीआर टीम

## करीब चार वर्षों बाद अभिनय में वापसी कर रही हैं नफीसा अली

**कला के प्रति** कलाकार का लगाव लाख मुश्किलों के बावजूद कम नहीं होता है। लंबे अर्से तक अभिनय से दूर रहने के बाद जब कलाकार को दोबारा अपनी कला से जुड़ने के मौका मिलता है, तो उनका उत्साह देखने लायक होता है। कुछ इसी तरह का उत्साह मेजर साहब, बेवफा और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों की अभिनेत्री नफीसा अली में भी है। नफीसा फिल्म इंडस्ट्री से करीब चार साल की दूरी के बाद एक बार फिर से अभिनय में वापसी कर रही हैं। उन्होंने बुधवार को हाथ में स्क्रिप्ट लिए अपनी एक तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर यह जानकारी साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कई वर्षों बाद कोई फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं। कैंसर से उबरने के बाद कई वर्षों बाद अभिनय के लिए मुंबई जा रही हूं। मैं आगे अपनी क्रिएटिव टीम के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।' नफीसा शुक्रवार को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई पहुचेंगी। हालांकि, उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं साझा की है। नफीसा की आखिरी फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 साल 2018 में रिलीज हुई थी। उसके बाद साल 2018 में ही वह कैंसर से पीड़ित हो गई थीं, जिसके कारण उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली थी। नफीसा ने साल 1979 में श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म जुनून से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया था। उसके बाद उन्होंने आतंक, बेवफा समेत कई फिल्मों में काम किया।



साल 2018 में रिलीज फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 थी नफीसा की आखिरी फिल्म। इंस्टाग्राम

## अब वक्त आ गया है कि लिंग भेद जैसी चीजों से आगे सोचें : आशी सिंह

**शिक्षा, जातिगत भेदभाव,** लैंगिक असमानता और ऊंच-नीच जैसे कई मुद्दों को वक्त के साथ बदलते समाज की सोच और विचार के साथ निर्माता अक्सर टेलीविजन धारावाहिकों में भी दिखाते हैं। जी टीवी का आगामी धारावाहिक मीत भी कुछ इसी तरह लैंगिक भेदभाव के प्रति बदलती सोच को प्रदर्शित करेगा। हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित इस धारावाहिक की कहानी मीत नामक एक उत्साही लड़की की कहानी है। जहां आमतौर पर लड़के ही घर का चिराग माने जाते हैं, इस कहानी में मीत ही अपने घर का चिराग है। वह न सिर्फ अपने घर की इकलौती कमाने वाली सदस्य है, बल्कि डिलीवरी एजेंट का काम करते हुए लड़के-लड़कियों के पेशों को लेकर बने समाज के खोखले नियमों को भी तोड़ती है। इस धारावाहिक में अभिनेत्री आशी सिंह मुख्य भूमिका निभाएंगी। दैनिक जागरण से बातचीत में आशी ने कहा, 'यह शो समाज के एक गंभीर मुद्दे को उठाता है। अब वक्त आ गया है कि हम लिंगभेद से आगे की सोचें और लोगों को उनके स्वाभाविक रूप में ही जीने दें। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी जिम्मेदारी को पूरा करने वाला व्यक्ति एक आदमी है या औरत। इस शो में एक बेटी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाती नजर आएगी। वो जानबूझकर नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी स्वाभाविक जिंदगी जीती है। मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर इस रोल में आगे बढ़ने के लिए बहुत संभावनाएं हैं।' इस शो का प्रसारण मध्य अगस्त से होगा।



आगामी धारावाहिक मीत में मुख्य भूमिका में दिखेंगी आशी। जीटीवी पीआर टीम



इंडस्ट्री में आए बदलावों के साथ आगे बढ़ने को तैयार एशा • जागरण आर्काइव

# ट्रोल्स से डर हो तो इस पेशे में नहीं आना चाहिए : एशा देओल

**सात सवाल**

दो बेटियों की मां एशा देओल तख्तानी कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अभिनय में वापसी कर चुकी हैं। आगामी दिनों में वह अजय देवगन के साथ वेब सीरीज रूद्र : द एज आफ डार्कनेस में अभिनय करती नजर आएंगी। वहीं फिल्म एक दुआ से वह निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी हैं। वूट सेलेक्ट पर रिलीज हो चुकी एक दुआ में उन्होंने मां की भूमिका निभाई है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी एशा ने अपनी वापसी, फिल्म निर्माण और अन्य पहलुओं पर बात की :

- **अभिनय में वापसी को लेकर क्या मन में कोई डर था? किस तरह के बदलाव फिल्म इंडस्ट्री में नजर आए?**

-मैंने 18 साल की उम्र से कैमरे के सामने काम करना शुरू किया था। कैमरे पर लौटना हमेशा खास होता है। डर जैसी चीज अगर आप अपने पेशे में लाएंगे, तो वह रुकावट बन जाएगी। मैं अब 18 साल वाली एशा नहीं हूं। वक्त के साथ मजबूत हो गई हूं। पहले से लेकर अब तक में इंडस्ट्री में काफी बदलाव हुए हैं। वर्कशाप, रीडिंग, सेट पर जाने से पहले कलाकारों पर बहुत मेहनत की जाती है। पहले हम सेट पर जाते थे, सुबह नया सीन दिया जाता था, हम पढ़कर सेट पर आ जाते थे। बहरहाल, हमारी वेब सीरीज की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अजय देवगन के साथ काम करके अच्छा लग रहा है।

- **कई कलाकार अपनी प्रोडक्शन कंपनी में खुद अभिनय नहीं करते हैं। अभिनय के साथ निर्माण का काम मुश्किल लगा?**

-मैं बड़े ही स्वाभाविक तरीके से निर्माता बनी। एक दुआ की स्क्रिप्ट मेरे दिल को छू गई थी। फिल्म का विषय लैंगिक समानता पर जागरूक करने को लेकर है। कलाकार और निर्माता होने के नाते जागरूकता लाने का काम करना चाहती हूं। लैंगिक असमानता कई वर्षों से चली आ रही है। अब शायद पहले के मुकाबले इसमें कमी आई होगी। इस उम्मीद से फिल्म बनाई है कि कुछ बदलाव आएं। किसी जल्दबाजी में नहीं हूं कि एक साल में 10 फिल्में बनानी हैं। दिल को छूने वाली कहानी होनी चाहिए, जो लोगों पर एक सकारात्मक असर छोड़े। मेरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में दूसरे एक्टर्स को भी मौका मिलेगा।

- **अभिनेत्रियों के लिए इस दौर को कैसा पाती हैं?**

-मेरी मां (हेमा मालिनी) ने बहुत सारे महिला केंद्रित किरदार किए थे, जिनमें लाल पत्थर, खुशबू जैसी फिल्में शामिल हैं। अब डिजिटल प्लेटफार्म की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई हैं। कंटेंट की एक नई वैरायटी आ गई है। मैं तो हर माध्यम पर काम करने को तैयार हूं। कुछ दिलचस्प टीवी पर भी मिला, तो वह भी करना चाहूंगी। अच्छी बात यह है कि खुद को अब किसी दायरे में अभिनेत्रियां नहीं बांध रही हैं।

- **इंटरनेट मीडिया पर कलाकारों को काफी ट्रोल किया जाता है। क्या आपको भी ट्रोल्स से डर लगता है?**

-अगर इन चीजों को गंभीरता से लेने लगे, तो इस पेशे में आना ही नहीं चाहिए। इतना रफ एंड टफ तो बनना चाहिए कि लोगों का प्यार भी अपना सकें और आलोचनाएं भी। हमें इस तरह की सभी चीजों की आदत हो जाती है।

- **फिल्म इंडस्ट्री पर पिछले दिनों काफी सवाल उठे...**

-इंडस्ट्री को लेकर जो गलत बातें होती हैं, मैं उसे नहीं मानती। यह हमें रोजी-रोटी देती है। हमारा मंदिर है। स्पाट ब्वाय से लेकर कलाकारों तक हर कोई एक-दूसरे की इज्जत करता है। सभी लोग इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं। हम क्रिएटिव लोग हैं। यह इंडस्ट्री हर किसी के लिए है।

- **आपके पति भरत प्रोडक्शन और फिल्मों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं?**

-वह बहुत ही लो प्रोफाइल इंसान हैं। उनकी यही बात मुझे पसंद है। वह बहुत सारा कंटेंट डिजिटल प्लेटफार्म पर देखते हैं। उन्हें जानकारी है कि किस तरह की कहानियां बेहतर होंगी। बतौर दर्शक वह अपना नजरिया टेबल पर रखते हैं। कैमरे के सामने और सेट पर आना अवाइड करते हैं, क्योंकि उनका अपना काम और बिजनेस है।

- **आप कई पुरानी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करती रहती हैं। पुरानी यादें सुकून देती हैं?**

-हां, बचपन की कई यादें हैं। मैंने मम्मी-पापा के साथ कई आउटडोर किए हैं। उनके साथ शूटिंग पर जाया करती थी। मेरे माता-पिता अब मेरी बेटियों के साथ वक्त बिता रहे हैं। मैं अपना बचपन अपने बच्चों में देखती हूं। वहीं मेरा बचपन मेरे माता-पिता मेरे बच्चों में देखते हैं। यह सब बहुत अलग एहसास है।

(स्मिता श्रीवास्तव)

## रनवे पर भजन करने वाला दृश्य नानी से सुनकर डाला था : अभिषेक

**वर्ष 1971** में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म भुजः द प्राइड आफ इंडिया के निर्देशक अभिषेक दुधैया की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है। उस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने भुज में भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी को क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसे भुज की 300 महिलाओं ने रातोंरात दुरुस्त किया था। उन महिलाओं में फिल्म के निर्देशक अभिषेक की नानी लक्ष्मी परमार भी थीं। दैनिक जागरण से बातचीत में अभिषेक ने बताया कि मेरी नानी की एक भजन मंडली थी। वह गांव में रोज सुबह भजन गाती थीं। फिल्म में जो भजन मंडली दिखाई है, उसमें मुखिया का किरदार मेरी नानी का ही है। सोनाक्षी का जो किरदार है, वह फिल्म में कहता है कि ढोल और बाकी चीजें भी साथ ले लो, रनवे बनने के बाद भजन भी वहीं कर लेंगे। क्लाइमेक्स में रनवे के पास बैठकर भजन करने वाला सीन वास्तविक जीवन से लिया गया है। मेरी नानी के हाथ की अंगुली उस दौरान टूट गई थी। जब रनवे बनाने के दौरान सायरन बजता था, तो उसका मतलब होता था कि पाकिस्तानी प्लेन अटैक करने आ रहे हैं। उस वक्त उनको जमीन पर लेटना होता था, ताकि बम से नुकसान न पहुंचे। जब नानी लेटी, तो उसी वक्त एक महिला के पैर के नीचे उनका हाथ आ गया और अंगुली फैक्चर हो गई। 10 साल की उम्र में मैंने ये कहानियां नानी से सुनी थीं, इसलिए उन्हें फिल्म में भी शामिल किया है। नानी के किरदार में मैंने अपनी राखी बहन विनीता मेनन को लिया है। वह मेरी नानी से मिली भी हैं। यह फिल्म डिज्नी प्लस हाटस्टार पर 13 अगस्त को रिलीज होगी।



साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बनी है भुज : द प्राइड आफ इंडिया • इंस्टाग्राम